हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च, 1982

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

भाुक्रवार, 19 मार्च, 1982

विशय सूची

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(5)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों लिखित उत्तर	(5)22
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(5)24
राज्य पाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)37
औचित्य प्र न– इलेक ान ईयर मे पूरा बजट पे ा करने संबंधी	(5)60
वाक आउट	(5)62
वर्श 1982.83 का बजट पेश करना निजी गन क्र ारों आदी मे गन्ने की कम कीमत संबंधी	(5)62
वाक आउटस	(5)82

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 19 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह)

ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहिबान, अब सवाल होंगे।

Elections to Municipal Committees in the State

***2613. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Local Government be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to hold elections to the Municipal Committees in the State, if so, the time by which the elections are likely to be held?

Local Government Minister (Shri Mange Ram Gupta): Yes, The Government have decided to hold elections in all the municipalities after completing the formalities afresh

on the basis of 1981 census data. The completion of these formalities is likely to take some time.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब जब असेम्बली के चुनाव सन् 1981 के सैंसिस की फिगर्ज के बगैर हो सकते है तो म्यूनिस्पिल कमेटीज के चुनाव क्यों नही हो सकते ? सरकार ने वायदा भी किया था कि चुनाव कराये जायेंगे। दूसरे मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि ये फामेंलिटीज कब तक पूरी हो जायेगी और किस डेट को चुनाव कराने जा रहे है ?

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, हमारे म्यूनिस्पिल इलैक ान रूल्ज मे ऐसा प्रोविजन है कि जब तक सैंसिस का डैटा नही आ जाता तब तक इलैक ान नही हो सकता । सैंसिस डैटा के बिना सीटों का फैसला नही हो सकता। जब तक सीटों का फैसला नही होगा तब तक इलैक ान होना पौसिबल नही ।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपके द्वारा लोकल बाडीज मिनिस्टर महोदय से जानना चाहता हूं कि म्यूनिस्पिल कमेटीज का पिछला इलैक ान कब हुआ था ? मंत्री जी ने कहा कि फार्मेलेटीज पूरी करनी है, क्या वे बतायेंगे कि फार्मेलेटीज क्या क्या है ?

श्री मांगे राम गुप्ताः पिछला इलैक ान ज्वायंट पंजाब मे हुआ था। कुछ कमेटीज के इलैक ान हरियाणा बनने के बाद भी सन 1969 मे हुए थे। उसके बाद इलैक ान नही हुए। डाक्टर

मंगल सैन जी को तो भली भांति पता है कि कब इलैक ान हुए थे।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्होंने अभी कहा था कि फार्मेलिटीज पूरी करनी है, मैं उन फार्मेलिटिज के बारे मे जानना चाहता हूं कि वे क्या है ?

श्री मांगे राम गुप्ताः जहां तक फार्मेलिटिज की बात है, पहले तो सीटस का फैसला करना है, फिर बार्डबंदी होनी है ओर उसके बाद बोटर्ज लिस्ट तेयार करनी पड़ेगी। बोटर्ज लिस्ट फाइनल होने पर इलैक ान हो जायेंगे।

डा. मंगल सैनः कौन सा रूल है जिसमे यह दिया हुआ है कि ये फार्मेलिटिज पूरी हुए बिना इलैक ान नही हो सकता ?

श्री मांगे राम गुप्ताः रूल नम्बर तीन है। इसमे दिया हुआ है कि जब सैंसिस हो जाये उसके बाद ही सीटों का फैसला होगा, फिर इलैक ान होते है।

चौधरी रिजक रामः अभी हाउस मे मंत्री महोदय ने बताया है कि सैंसिस की फिगर्ज नही आयी । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे फिगर्ज बाई ट्रक बाई एयर आयेंगी या हैलीकोप्टर से आयेंगी, किस प्रकार से आयेगी? दूसरे उन्होंने कहा कि अभी फार्मेलिटीज पूरी नही हुई है। सैंसिस सन 1981 मे पूरी हो चुकी है लेकिन फिगर्ज आज तक भी सरकार के पास नही आयी। उन्हें लाने का सरकार ने क्या तरीका अडौप्ट किया है ?

उन फिगर्ज को कब तक मुहैया कर सकेंगे? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब सैंसिस सन 1981 मे हो चुकी है तो सैंसिस की फिगर लाने मे क्या रूकावट थी जिसके कारण इलैक ान नही करा सके ?

श्री मांगे राम गुप्ताः आदणीय मैंबर, चौधरी रिजक राम ने पहला वाला यह पूछा कि क्या सैंसिस की फिगर्ज हैलीकोप्टर, ऐरोप्लेन या ट्रक से आयेंगी ? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि फिगर प्रोसैंस से ही आती है। सैंट्रल गवर्नमैंट से आनी है हमने उस डिपार्टमैंट को कांटैक्ट कर के पूछा था कि कब तक फिगर्ज भेज दोंगे ? उन्होंने कहा था कि जून, 1982 तक फिगर्ज भेज देंगे। जब फिगर्ज अवेलेबल हो जायेगी तो इलैक ान प्रोसैस चालू हो जायेगा।

दूसरे सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया है कि हरियाणा मे सन 1969 के बाद इलैक ान नही हुए। 13 साल पहले की फिगर्ज पहले भी आती रही है लेकिन अब सैसिस होने के बाद एक कानूनी अड़चन है जिसकी वजह से इलैक ान नही करा सके।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, एक सवाल तो मेरा चौधरी रिजक राम जी ने पूछ लिया। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह दरूस्त है कि जिस दफतर से सन 1981 के सैसिस के आंकड़ें आने है हरियाणा मे, उस दफतर का इंचार्ज हरियाणा का

ही आई0 ए0 एस0 अफसर लगा हुआ है ? फिर वहां से आंकड़ें प्राप्त करने मे सरकार को क्या दिक्कत पे ा आ रही है ?

श्री मांगे राम गुप्ताः सैंसिस आफिस केन्द्रीय सरकार का है। वहीं से हमें फिगर्ज आनी है। फिगर्ज आने पर ही इलैक ान की डेट का फैसला होगा। पले सीटों का फैसला होगा, फिर वाईबंदी होगी और उसके बाद वोटर्ज बनेगी तब जा कर इलैक ान होंगे।

चौधरी राम लाल वधवाः क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि किस डेट को इलैक ान कराने जा रहे है? यह सरकार अपने ही काल मे इलैक ान करा देगी या हमें ही ये इलैक ान करवाने पड़ेंगे ?

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब सन 1977 मे असैम्बली के इलैक ान हुए थे। डा. मंगल सैन और चौधरी राम लाल वधवा म्युनिस्पिल कमेटी एरिया से इलैक ान जीत कर आये है वे दोनो ही लोगों से यह वायदा करके आये थे कि हम म्युनिस्पिल कमेटीज के इलैक ान करायेंगे लेकिन इनका तीन साल तक राज रहा, उस दौरान ये इलैक ान क्यों नही कर सके?

Upgradation of Civil Hospital, Jhajjar

***2653. Capt. Mange Ram:** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether here is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Civil Hospital Jhajjar from 24 beds to 50 beds Hospital; and

(b) if so, the time by which the said Hospital is likely to be upgraded?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री (चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(क) जी हां।

(ख) इस अस्पताल को 50 बिस्तर का अस्पताल कब तक बनाया जायेगा, यह बताना इस समय कठिन है।

कैप्टन मांगे राम: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि झज्जर अस्पताल का दर्जा बढ़ा कर 24 बिस्तरों से 50 बिस्तरों का कब तक कर दिया जायेगा? मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि सरकार के विचाराधीन है। मुझे इस बात की खु ाी की है यह सरकार के विचाराधीन तो है लेकिन मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह कब तक विचाराधीन रहेगा, किस साल मे बनने की आ ाा है ? झज्जर तहसील भी है, जिले के दूसरे दफतर भी है ओर आर्मी के जवान कैजुअल और लौंग लीव काटने के लिये इस एरिया मे आते रहते है लेकिन उस अस्पताल मे केवल एक लेडी डाक्टर और एक मेल डाक्टर है। क्या सरकार के पास फण्ड की कमी है या काई अन्य कारण है जिस कारण दर्जा नही बढ़ाया

जा रहा ? कब तक उसे पचास बैडज का अस्पताल बना दिया जायेगा?

श्री अध्यक्षः अब क्वै चन आवर है। प्रार्थना का टाईम दफतर मे है।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब नया साल आ रहा है। नये साल मे 50 बैडज का अस्पताल बनाने जा रहे है।

Mr. Speaker: All supplementary should be confined to the question of upgradation of Civil Hospital, Jhajjar.

श्री मूल चंद मंगलाः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 24 बेडज से 50 बेडज का अस्पताल बनाने का क्या क्राइटेलिया है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः किसी भी अस्पताल को बनाने का निम्नलिखित क्राइटेरिया लेड डाउन किया हुआ है–

1- बैकवर्ड एरिया हो।

2- हैल्थ केयर की डिफिकल्टी हो।

3- हैल्थ सैंटर कितने डिसटैंस पर है।

4- उस एरिया मे हैल्थ के बारे मे किस किस्म कि सुविधायं उपलब्ध है?

5- सबसीडरी सैंटर और डिसपेंसरी उस एरिया मे कितनी फासले पर है ? इस किस्म की बेरीयस कैटेगरीज को और लोगों की दिक्कतों को देखते हुए अस्पताल बनाये जाते है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या झज्जर के अस्पताल को अपग्रेड मुख्य मंत्री जी की घोशणा के आधार पर किया जा रहा है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः यह बिल्कुल दुरूस्त है कि चीफ मिनिस्टर साहब से लोगों ने मांग की और उस मांग को और लोगों की परे ाानी को देखते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने एलान किया कि अस्पताल का दर्जा बढ़ाया जायेगा। इसी आधार पर पचास बैडज का बनाने जा रहे है।

श्रीमती डा. कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो क्राइटेरिया बताया है क्या इस क्राइटेरिया को झज्जर पूरा करना है ? किस आधान पर उसके अपग्रेड किया गया है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, जिस वक्त डाक्टर कमला वर्मा हैल्थ मिनिस्टर थी, उस वक्त झज्जर भाायद काइटेरिया पूरानही करता था लेकिन मौजूदा सरकार आने के बाद जरूरत महसूस की गई इसलिये अपग्रेड करने का निर्णय लिया। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी हर स्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, सरकार वहां पर 50 बेडज का हास्पिटल तो बनाने जा रही है लेकिन जो पे ोंटस के साथ आदमी आते है क्या उनके रहने के लिये भी कोई धर्म ाला का प्रोपीजन किया जायेगा ?

Mr. Speaker: It is a very good question and a good suggestion.

चौधरी गजराज बहादुर नागरः मेरे दोस्त ने यह बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मुख्य मंत्री जी ने इस बारे मे दो दफा मीटिग्ंज की है और हम बड़ी सीरियसली इस बात को कंसीडर कर रहे है कि कहां कहां पर यह सुविधा पहले उपलब्ध करवायी जाये। (व्यवधान व भाोर) जैसे मैंने बताया है यह मामला दो दफा हो चुका है और सीरियसली अंडर कंसीड्रे ान है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, आपके द्वारा मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि अस्पतालों मे दवाइयों का बिल्कुल प्रबंध नही है। जब भी कोई मरीज अस्पताल मे जाता है तो डाक्टर एक चिट लिख देता है। उसके पास अगर पैसे हों तो यह इलाज करवा ले अगर पैसे न हो तो वह न करवाये। अपग्रेड करने से ज्यादा जरूरी दवाईयों का प्रबंध करना है। इसलिये क्या सकरार ज्यादा दवाईया उपलब्ध करवाने का प्रबंध करेगी?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, दवाईयों के बारे मे मेरे फाजिल दोस्त ने सवाल उठाया है। हमारी सरकार जितना ज्यादा से ज्यादा बजट दवाईयों पर खर्च कर सकती है,

उतना कर रही है। सारे हिन्दुस्तान मे कोई भी स्टेट ऐसी नही है जो सारी दवाईयां अस्पतालों मे उपलब्ध करवाती हो यह कोई अंनिन्ग डिपार्टमैंट नही है यह एक्सपैंडिंग डिपार्टमैंट है। ज्यादा से ज्यादा पैसा इस डिपार्टमैंट को दवाईयों के लिये देते है। पैसे की एलोके ान बाकायदा पापुले ान और लोगों की दिक्कतों को देखते हुए डिस्ट्रिक्टवाईज करते है। सरकार अपनी ओर से पूरी सुविधा देने की कोि ा ा करती है।

डा. बृज मोहन गुप्ताः मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक 24 बैडज हास्पिटल मे कितने डाक्टर्ज की पोस्टस है ओर 50 बैडज के हास्पिटल मे कितनी पोस्टस है ?

श्री अध्यक्षः यह सैपरेट क्वै चन है। अगर मिनिस्टर साहब के पास इंफर्मे ान है तो दे दे। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, मैने तो यह कहा ही नही है कि इंफर्मे ान नही दे सकता। हरियाणा के किसी भी हास्पिटल के बारे मे कोई भी रैलेवेंट या इररैलेवैंट सवाल पूछे मैं जवाब दूंगा लेकिन इनमे पूछने का दम नही है। (व्यवधान व भाोर) हमारे इन साथियों मे न सवाल पूछने का दम है और नही जवाब सुनने का।

Mr. Speaker: Have you got the relevant information?

Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Then please supply.

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, मैडीकल आफिसर्ज–2, फार्मेसिस्ट्स–2, अस्सिटैंट डैटल सर्जन–1, नर्सिंग सिस्टर नर्स–4, रेडियोंग्राफर–1 लैबोरेटरी टैक्नी ीयन–1, क्लर्क–कम स्टोर कीपर–1, क्लास–फोर एम्पलाईज इन्वल्यूडिंग स्वीपर्ज–12। यह स्टाफ वहां के लिये सैक ांड है। अगर वहां पर कोई कर्मचारी एट प्रेजैंट पोस्टिड नही है या कम है तो मुझे इत्तलाह दे मैं फौरन पोस्टिंग कर दूंगा। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः यह आपने 24 बैडज का बताया है लेकिन इन्होंने 50 बैड का पूछा है। (व्यवधान व भाोन)

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, सरकार ने तो इनके ठहराने से ठहरेगी और नही इनके हटाने से हटेगी। यह सरकार तो अपनी क्षमता से चल रही है। इनके दूसरे सवाल का जवाब भी दे देता हूं। मेरे पास 50100 और 200 बेडज के स्टाफ नार्म भी है वह भी पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्षः इन्होंने केवल 50 बैडज का पूछा है।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः 50 बैडज के लिये एच0 सी0 एम0 एस0 क्लास–1–1 एच0 सी0 एम0 एम0 क्लास 2–4, डैंटल सर्जन–1, नर्सिंग सिस्टर–1, स्टाफ नर्सिंग/ए0एन0एमज0–13, रेडियोग्राफर–1, फार्मेसिस्टस–3, लैबोरेट्री टैक्नी ीयन ग्रेड–1/2–1–6 कुक–2, क्लर्क कम स्टोर

कीपर–1, चौकीदार–2, माली–2ख क्लास फोर एम्पलाईज इंक्लयूडिंग स्वीपर–17 और धोबी–2 (ाोर व व्यवधान)

चौधरी अजीत सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने फाइनल मंगवा ली है। क्या मंत्री जी फाइल देखकर बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य मंत्री ने इस अस्पताल का दर्जा बढ़ाने की घोशणा कद की थी और इस तरह की घोशणाओं कोपूराकरने के लिये आपके विभाग को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना समय चाहिए? क्या इस तरह की घोशणा बेरी मे भी की थी? यदि की थी तो उसे पूरा किया जायेगा ?

श्री अध्यक्षः यह सप्लीमैंटरी इस सवाल से संबंधित नही है।

कैप्टन मांगे रामः अध्यक्ष महोदय, झज्जर मे 24 से 50 बैडज का अस्पताल करने के लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इस वक्त वहां पर एक लेडी डाक्टर और एक मेल डाक्टर है। क्या मंत्री महोदय वहां पर और ज्यादा डाक्टर्ज पोस्ट करने की कृपा करेंगे?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, डाक्टर्ज पोस्ट का कुछ क्राईटेरिया है, उसी हिसाब से डाक्टर्ज पोस्ट किये जाते है।

डा. मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो क्राईटेरिया चोबीस से पचास बैडज का, पचास से सौ

बैडज का ओर सौ बेडज से दो सौ बेडज का अस्पताल बनाने का लेड डाउन किया है, क्या उस क्राईटेरिये मे कलानौर का अस्पताल भी आता है ?

श्री अध्यक्षः इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिए।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, मैं कोई प्र न तो नही पूछ रहा हूं। मैं केवल एक अनयिमितता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सदन मे हरियाणा प्रदे ा कांग्रेस कमेटी के कार्ड आपके स्टाफ द्वारा बांटे जा रहे है। यह भाोभा नही देता।

Mr. Speaker: I have given a ruling that in future such circulars will be placed in the lobby. वहां से मैंबर्ज कलैक्ट कर ले। इन फयूचर ऐसा कोई भी सरकूलर हो तो वह लौबी के अंदर रख दिया जायेगा। वहां से मैंबर साहिबान कलैक्ट कर सकते है। (ाोर व व्यवधान)

Irregularities in the distribution of Cement, Kerosene Oil and Sugar

*2645. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) whether any irregularities in the distribution of cement, kerosene oil and sugar came to the notice of the Government during the period from 1st Aril, 1981 to date; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the district wise detail of the persons involved in committing such irregularities together with the nature of the irregularities committed and the action, if any, taken against each one of them?

Food and Supplies Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Yes.

(b) The required information is laid on the Table of the House (Annexure)

ANNEXURE

CEMENT

(i) Cases in which police action taken during the period from 1-4-81 to 31-1-82.

Sr.	Name of Circle	No. of persons arrested	Nature of irregularities	Action	Taken
1	Ambala	13	Short weight, rate and stock board not displayed, physical balance not found as per stock register, overcharging and stocks found without	14	Cases regd. with police.

			valid license etc.		
2	Bhiwani	-		-	
3	Faridabad	13		12	-do-
4	Gurgaon	-		-	
5	Hisar	5		6	-do-
6	Jind	-		-	
7	Kaithal	-		-	
8	Karnal	11		10	-do-
9	Kurukshetra	-		1	-do-
10	Narnaul	2		1	-do-
11	Rohtak	-		-	
12	Sirsa	-		1	-do-
13	Sonepat	-		1	-do-
	Total	44		46	

(ii) Cases in which departmental action taken during the period from 1-4-81 to 31-1-82

Sr.	Name of Circle	No. of cases Checked	No. of Licenses cancelled	No. of licenses suspended	Security forfeited

1	Ambala	-	-	-	-
2	Bhiwani	6	-	-	-
3	Faridabad	-	-	-	-
4	Gurgaon	-	-	-	-
5	Hisar	-	-	-	-
6	Jind	-	-	-	-
7	Kaithal	3	-	-	2
8	Karnal	22	-	-	8
9	Kurukshetra	8	-	-	-
10	Narnaul	7	-	-	1
11	Rohtak	-	-	-	-
12	Sirsa	-	-	-	-
13	Sonepat	2	-	-	2
	Total	48			13

KEROSENE OIL

(i) Cases in which police action taken during the period from 1-4-81 to 31-1-82.

Sr.	Name of Circle	No. of persons	Nature of irregularities	Action	Taken

		arrested			
1	Ambala	-	Short weight, rate and stock board not displayed, physical balance not found as per stock register, overcharging and stocks found without valid license etc.	-	
2	Bhiwani	-		-	
3	Faridabad	2		2	Cases regd. with police.
4	Gurgaon	-		1	-do-
5	Hisar	-		1	-do-
6	Jind	4		4	-do-
7	Kaithal	2		2	-do-
8	Karnal	5		5	-do-
9	Kurukshetra	-		4	-do-
10	Narnaul	-		-	
11	Rohtak	-		-	

12	Sirsa	-		-	
13	Sonepat	2		2	-do-
	Total	15		21	

(ii) Cases in which departmental action taken during the period from 1-4-81 to 31-1-82

Sr.	Name of Circle	No. of cases Checked	No. of Licenses cancelled	No. of licenses suspended	Security forfeited
1	Ambala	6	-	4	2
2	Bhiwani	7	-	-	3
3	Faridabad	2	-	-	2
4	Gurgaon	3	-	-	1
5	Hisar	2	-	-	-
6	Jind	4	-	-	-
7	Kaithal	15	1	3	2
8	Karnal	18	1	1	5
9	Kurukshetra	20	2	-	1
10	Narnaul	2	-	-	1
11	Rohtak	-	-	-	-

12	Sirsa	8	1	-	3
13	Sonepat	1	-	-	1
	Total	88	5	8	21

SUGAR

(i) Cases in which police action taken during the period from 1-4-81 to 31-1-82.

Sr.	Name of Circle	No. of persons arrested	Nature of irregularities	Action	Taken
1	Ambala	-	Short weight, rate and stock board not displayed, physical balance not found as per stock register, overcharging and stocks found without valid license etc.	-	
2	Bhiwani	-		-	
3	Faridabad	3		7	Cases regd. with police.
4	Gurgaon	-		-	

5	Hisar	1		1	-do-
6	Jind	-		-	
7	Kaithal	-		-	
8	Karnal	8		6	-do-
9	Kurukshetra	1		1	-do-
10	Narnaul	-		-	
11	Rohtak	-		-	
12	Sirsa	-		1	-do-
13	Sonepat	-		-	
	Total	13		16	

(ii) Cases in which departmental action taken during the period from 1-4-81 to 31-1-82

Sr.	Name of Circle	No. of cases Checked	No. of Licenses cancelled	No. of licenses suspended	Security forfeited
1	Ambala	146	3	-	7
2	Bhiwani	212	4	-	63
3	Faridabad	236	17	-	44
4	Gurgaon	91	3	5	6

5	Hisar	51	9	-	41
6	Jind	74	20	-	20
7	Kaithal	305	1	-	1
8	Karnal	176	13	12	97
9	Kurukshetra	94	2	-	14
10	Narnaul	52	8	-	42
11	Rohtak	52	9	-	18
12	Sirsa	24	3	-	7
13	Sonepat	89	5	-	109
	Total	1602	97	17	459

स्वामी आदित्यवे ा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के पास जो विभाग हैउसने काफी चैकिंग की है। मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कया इस प्रकार की चैकिंग अब भी विभाग के द्वारा की जा रही है ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, हमारा विभाग अभी भी चैंकिंग पर लगा हुआ है और पिछले दो तीन दिन मे कोई 1700 जाली रा ान कार्ड वीड आउट किये है। अब सीमेंट का भी कोई झगड़ा नही रहा है क्योंकि वह फ्री हो गया है और न ही उस की किल्लत रही है। जहां तक चीनी का ताल्लुक है उसकी

डिस्ट्रीब्यू ान सरकार की तरफ से ठीक चल रही है। हमारी स्टेट मे न चीनी की दिक्कत है ओर न ही भाार्टेज है।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, मेरा सवाल बड़े लोक महत्व का है। मैने पिछले सै ान मे भी मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था और अब फिर डिटेल मे बता देता हूं। हमारे यहां मिटटी का तेल, डीजल मे मिक्स किया जाता है। पिछली बार भी मंत्री महोदन ने आ वासन दिया था कि इस लकूने को दूर कर दिया जायेगा। सैंट्रल गवर्नमैंट ने जिसे पैट्रोल पम्प का लाइसैंस दिया हुआ है उसे ही मिटटी के तेल का लाइसैंस भी दिया हुआ है। वह आदमी डीजल मे मिटटी का तेल मिलाकर के बेचता है। पिछले सै ान मे मैंने पूछा था कि क्या ऐसे डीलर के खिलाफ एक ान लिया जायेगा? तो मंत्री महोदय ने आ वासन दिया था कि एक ान लिया जायेगा। मैं कहना चाहता हू कि मिटटी का तेल का लाइसैंस किसी और नाम पर दे दो या उसके किसी रि तेदार को दे दो। अध्यक्ष महोदय, कालांवली मे भगवंत राय द र्ान कुमार के पास डीजल का पम्प भी है और मिटटी के तेल का लाइसैंस भी है। उसके खिलाफ कोर्ट के केस भी पैंडिग है। क्या मंत्री महोदय इसके बारे मे कोई टाईम निर्धारित करेंगे कि इस टाईम के बाद दोनों चीजों मे से लाइसैंस नही रहेगा ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, स्टेट गवर्नमैंट के नोटिस मे यह बात आई थी कि एक जगह पर डीजल और मिटटी

का तेल का लाइसैंस एक ही आदमी को मिला हुआ है। सारी स्टेट मे एक दो जगहें ही ऐसी है जहां पर दोनो चीजों के एक ही आदमी को लाइसैंस मिले हुए है। इसके लिये हमने भारत सरकार को लिखा था। भारत सरकार ने फरदर अलाट नही किया। वहां पर इस लिये ऐसा किया थाकि लोगों को पम्प द्वारा ही मिटटी का तेल मिल सके और जनता को सुविधा हो । स्पीकर साहबि, इसको चैक करने का भी फूल प्रूफ सिस्टम है। ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट और डी0 एस0 पी0 इन कोआर्डिने ान विद दी आफिसर्ज आफ दी इंडियन आयल कार्पोरे ान चैक करकते है और चैक करने के बाद ट्रायल होम डिपार्टमैंट करता है। हमारे नोटिसय मे अब काई केस नही आया है। अगर कोई केस माननीय सदसय बतायेंगे तो हम स्पै ाल चैकिंग सबवैड भेज सकते है।

श्री देवी दासः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि सीमेंट की कोई समस्या नही है। सीमेंट बाजार मे खुला मिलता है। अध्यक्ष महोदय, बाजार में 65 और 70 रूपये मे जो बेग मिलता है वह रेत मिलता है लेकिनह जो सीमेंट 35 रूपये बैग मिलता है, अगर उसका ठीक ढंग से वितरण हो तो कम से कम लोगो को रेत का सीमेंट तो न मिलेगा। क्या मंत्री महोदय इस दिशा मे कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैंम्बर साहब जो 35 रूपये बोरी सीमेंट बता रहे है वह अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यू ान मे सब लोगो को नही मिलेगा। जो आदमी अससी मीटर मे मकान

बनायेगा सिर्फ उसी को ही मिलेगा। जो इकनोमिकली बीकर सैक ान है या किसी को एक यादो बोरी सीमेंट रिपेयर के लिये चाहिए उसको मिलेगा। अभी ुाइनल पालिसी तय नही हुई है। भारत सरकरर ने यह सोचा कि सीमेंट की बहुत किल्लत है औरमिडल मैन बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है इस लिये अब 34.4 परसैंट सीमेंट पर कंट्रोल रखा है और बाकी को खुला कर दिया है । उसके ऊपर न तो रेट का कंट्रोल है और न डिस्ट्रीब्यू ान पर कंट्रोल है और न डिस्ट्रीब्यू ान पर कन्ट्रोल है। भारत सरकारने फक्टरीज को स्ट्रैस किया है कि वे ऐसी जगह जहां परसीमेंट की भाार्टेज है, जैसे ईस्टर्न यू0 पी0 तथा जम्मू का मीर है वहां पर सीमेंट पहुंचाने की कोि ा ा करे। स्पीकर साहब, जिसका एक कैनाल या पंद्रह मरले का प्लाट है उसे कंट्रोल का सीमेंट नही मिलेगा। उसे मार्किट से सीमेंट लेना पड़ेगा।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय के नोटिस मे है कि आज सीमेंट की बोरी का खुली मार्किट मे 60 से 70 रूपये रेट चल रहा है, जिसे एक मामूली आदमी के लिये खरीदना बड़ाह ीकठिन है। कल को सरकार 200 रूपये बोरी खुली सीमेंट का रेट कर दे, तो क्या यह वाजिब होगा ? दूसरी बात मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सचख नही है कि मंत्री जी आने कोर्ट से मिनिसटर्ज ओर वी0 आई0 पीज0 को दे रहे है? इसी तरह से कमी नर और डी0 सी0 अपने कोटे से अपने अपने आदमियों को कंट्रोल रेट पर सीमेंट दे रहे है। अध्यक्ष

महोदय, मोरनी हिलज मे इन्होंने 2000 बोरी अपने कोटे से सीमेंट दिया है।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैं आनरेबली मैंबर को बताना चाहता हूं कि 27 फरवरी से भारत सरकार के बजट के बाद कोई ऐसा सिस्टम डिस्ट्रीब्यू ान का नही रहा । पता नही मैंबर साहब को यह गलत बात कहां से पता लगी। अगर किसी डीलर के पास कोई पुराना स्टाक पड़ा हुआ है तो हम उसे महंगे भाव पर बेचने की इजाजत नही देंगे क्योंकि उसने सस्ते भाव पर खरीदा है। मैंबर साहब ने जो मिनिस्टर कोटे की बात कही है, वह गलीत, अब ऐसा कोई कोटा नही है। वह बहुत देर पहले समाप्त हो चुका है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं आप के जरिये मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार जो सीमेंट का कोटा हरियाणा स्टेट की अलाट करती है उस मे से पिछले दिनों पनि ामेंट के तौर पर सीमेंट की कट 20 परसैंट इसलिये तो नही लगाई गई कि यहां की फक्ट्रीयों मे पावर कट ज्यादा है?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैंबर साहेबान को यह बताना चाहता हूं कि हमें किसी भी क्वार्टर मे पूरा सीमेंट नही मिला है। पावर कट की वजह से कोटा कम नही है। हमें पिछले दस सालों से कभी 66 परसेंट और कभी 70 परसेंट सीमेंट रसीट होती रही है। इसका कारण यह है कि कभ्झी

पावर कट हो गई, कभी लोडिंग की प्रोबलम्ज हो गयी, कभी डीलर्ज ने समय पर पैसे नही जमा करवाये और कभी कभी कैरिज वगैरह की डिफीकलटीज भी हो गई। मतलब यह है कि एवरेज हमारी इन कारणो से कभी भी पूरी नही आयी। अब सरकार ने तीन डम्पस बनाये है, जिनमे दो रिवाड़ी के अंदर हे ताकि आगे के लिये सीमेंअ की कोई किल्लत ही न हो। जहां तक पनि ामैंट का सवाल है, ऐसी कोई बात नही है।

मास्टर ि ाव प्र ाादः स्पीकर साहब, 34.4 परसेंट सीमेंट का कोटा फ्री सेल का मिलताा है और 65 परसेंट का कोटा कंट्रोल रेट का मिलना चाहिए था, इस संबंध मे 22 दिसम्बर, 1981 को अम्बाला मे लास्ट डिस्ट्रीब्यू ान हुई थी। उसके बाद कोटा आज तक नही आया है। आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सीमेंट का कोटा कब तक आ जायेगा ?

श्री अध्यक्षः यह अम्बाला का सवाल नही है।

मास्टर ि ाव प्र ाादः ठीक हे आप इसे सारी स्टेट का ही मान ले लेकिन मिनिस्टर साहब से मेरे सवला का जवाब तो दिलवाये।

(इस प्र ान का उत्तर नही दिया गया)

Day time supply of Electricity of Tubewells

***2632. Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether thee is any proposal under consideration of the Government to supply electricity to tubewells for Irrigation purposes during the day time instead of night hours?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह): सिंचाई टयूबवैलों को बिजली की आपूर्ति क्रमानुसार दिन व रात के दौरान बिजली भार तथा वोल्टेज की स्थिति के आधार पर दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान, इस वियाय पर कल भी एक काल अटैं ान मो ान आ चुकी है, इसलिये इस पर केवल एक ही सवाल पूछा जायेगा।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से यह दरयाफत करना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा प्रबंध करेगी कि किसानों को रात की बजाय दिन मे यानी जब भी जरूरत हो, बिजली दी जा सके? दूसरी क्या कोई ऐसा प्रबंध भी सरकार करने का विचार रखती हे कि किसानो को जरूरत के मुताबिक और ज्यादा सयम के लिये बिजली मुहैया की जा सके ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैंबर की जानकारी के लिये डिटेल मे बता देता हूं कि भाखड़ा बोर्ड का सिस्टम भाम 6 बजे से चालू होता है। हरियाणा सरकार की नीति यह है कि एग्रीकल्चर सैक्टर मे किसानो को रैगूलरली बिजली दी जाये।

इसलिये हम किसानो को पहली ि ाफट मे भााम को 6 बजे से बिजली देना चाहते है ताकि किसानों को पूरी बिजली मिल सके। दूसरी ि ाफट बाई रोटे ान की है जो दिन के वक्त देते है। भााम को जिन लोगों को बिजली मिलती है वह पूरी मिलती है और लोग भी खु ा है। कुछ भाइयों के दिमांग मे यह गलत बात आई हुई है कि दिन के वक्त जो बिजली दी जाती है, उसे सरकार जानबूझ कर कम देती है। ऐसी बात नही है। इन लोगो को इस बात का पता नही है कि दिन के समय वैसे भी बिजली कट जाती है। इसमे हमारा कोई दोश नही है।

Allotment of posts in Urban Estate Panchkula

***2650. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Finance be pleased to state wheterhy any plots in Sector 12-A and Sector 11 of Panchkula Urban Estate are proposed to beallotted by the draw of lots; if so, the date fixed for the draw of such lots?

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): हा। लाटरी निकालने के लिये अभी तिथि नि ि चत नही की गई है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हें कि जिन लोगों ने पंचकूला मे प्लाटस लेने के लिये अप्लाई किया है, उनका कुल कितना पैसा आपके पास आ चुका है ? दूसरे जिन लोगों के पैसे वापिस किये जायेंगे क्या उनको ब्याज समेत लौटाये जायेंगे ? कब तक यह प्लाटस के ड्रा निलाल दिये जायेंगे?

चौधरी खुर ाीद अहमदः स्पीकर साहब, सैक्टर 11 और 12ए (पंचकूला) के प्लाटस के बारे मे इनका सवाल है। एप्लीके ान काल करने की लास्ट डेट 3.11.81 थी और हमारी एडवरटाइजमैंट के अनुसार लोगों ने पैसे जमा करवाये है। पैसा जमा करवाने के बाद हाई कोर्ट मे दो सिविल रिटस नं0 4693 और 4683 आफ 1981 फाईल हो गई है जिसकी वजह से एप्लीके ानज की प्रोसैसिंग धीमी पड़ गई थी और यह पता नही था कि इन रिटों का कोर्ट से कब फैसला होगा। 22 फरवारी को केस लगा था। कोर्ट ने कहा कि अलाटमैंट हो सकती है, सबजैक्ट टू दि आर्डर आफ दि हाईकोर्ट । इसलिये अब हमने एप्लीके ांज की प्रोसैसिंग ाुरू कर दी है और जितनी जल्दी होगा, हम इन प्लाटस का ड्रा निकाल देंगे।

श्री हीरानंद आर्यः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कुल कितनी रकम लोगों की तरफ से सरकार को आई है और कब से वह रकम सरकार के पास है ? दूसरे अब तक प्लाटस की अलाटमैंट क्यों रोक रखी है? क्या सरकार उन पैसे पर ब्याज भी देगी ?

चौधरी खुर ाीद अहमदः स्पीकर साहब, इन्होंने पहले जो सवाल किया था वह यह था कि कब से रकम आई है। तारीख मैंने बता दी थी। कितनी रकम आई, इसका ब्यौरा मेरे पास नही है। एग्जैक्ट अमाउंट दोनों सैक्टों के लिये या अलग अलग सैक्टर के लिये कितनी आई, यह सूचना इस वक्त मेरे पास नही है।

तिसरी बात इन्होंने यह कही कि यह क्यों रोका हुआ है, उसके बारे मे मैंने बताया था कि हाई कोर्ट का आर्डर था। अब हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है, हम एप्लीकें ाज को प्रोसैस करके जितनी जल्दी हो सकेगा, लाटरी निकाल देंगे। जहां तक ब्याज देने का ताल्लुक है, हुडडा के रूल्ज और रैगुले ांज मे ऐसा कोई प्रोवीजन नही है कि जो प्लाट के लिये पैसा जमा करवाए उसे ब्याज दिया जाये।

श्री भले राम: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्लाटस 11 या 12 सैक्टर मे अलाट किये जायेंगे वे टोटल कितने है और क्या उनमे वीकर सैक ांज के लिये भी रिजर्वे ान है ?

चौधरी खुर ीद अहमद: उनमें एक भी प्लाट रिजर्वे ान का नही है। सभी लाटरी निकालने के लिये रिजर्व है, जिसकी किस्मत खुलेगी उसको मिल जायेगा।

डा. मंगल सैन: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्लाटों का डिस्क्रि ानरी कोटा खत्म करैंगे या चालू ही रखेंगे ?

चौधरी खुर ीद अहमद: डिस्क्रि ानरी कोटे की वायर्स सुप्रीम कोर्ट मे चैलेंज की गई है। The case is pending in the highes court of the land and I am not in a position to go into the merit of that case.

Bogus Ration Cards

***2648. Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the population of Rohtak City, as per ration cards issued is far in excess of the population as per 1981 Census Reports; and

(b) if so, the steps, taken or proposed to be taken to eliminate bogus ration cards, if any, issued?

Food and Supplies Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Yes.

(b) Door to door checking of ration cards in Rohtak City is being conducted as a result of which 30473 units have been cancelled so far. The checking of ration cards is still continuing.

स्पीकर साहब, इसमे मैं एक बात और एड करना चाहता हूं कि पिछले दो दिनों मे 1654 रा ान कार्ड और कट चुके है, वह सूचना मुझे कल मिली है।

डा. मंगल सैनः क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बोगसइ यूनिटस अनअर्थ हुए है या पकड़े गये है, उनको बनाने वाले कर्चचारियों के खिलाफ भी कोई एक ान लिया गया है ?

श्री लछमन सिंहः अभी चैंकिंग हो रही है और जैसे ही रिजल्ट आ जायेगा, दोशियों के विरूद्ध एक ान होगा। जिन्होंने

ऐसे कार्ड बनवाएं है उनके खिलाफ भी एक ान होगा क्योंकि उनको एक एफीउैविट देना पड़ता है।

श्री मूल चंद जैनः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रोहतक भाहर मे रा ान कार्डज की यूनिटस की कुल तादाद कितनी है और 1981 की सैंसिस के मुताबिक वहां की आबादी कितनी है?

श्री लछमण सिंहः रोहतक भाहर की आबादी 166631 है जोकि 30.4.81 की फिगर्ज के मुताबिक है और वहां पर जो रा ान कार्ड बने उनके मुताबिक यह फिगर्ज 237904 है जिसमे से कुछ कट भी चुके है। जो बोगस रा ान कार्ड होंगे वे कट जायेंगे और उसके लिये हम डोर टू डोर चैंकिंग कर रहे है।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल रोहतक भाहर के बारे मे है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रोहतक मे ही सब बोगस काम क्यों होते है ? (ाोर) स्पीकर साहब, आपको यह पता है कि रोहतक के नुमायंदे कौन है ? (ाोर) वहां कभी मोम के कोटे का, कभी पेपर का और कभी और इंडस्टरी के कोटे का स्कैंडल होता है। इसलिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि सब से पहले रोहतक के बारे मे इंक्वायरी करवाएं। (ाोर)

श्री लहरी सिंह मेहराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कितने बोगस रा ान कार्ड

बने है, जिनका आज सवाल आया है। ये रा ान कार्ड किस के टाइम के बने हुए है ? क्या से उस समय के तो नही बने हुए जब डा0 मंगल सैंन जी मिनिस्टर थे। (ाोर)

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

राब बंसी सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे यह रोहतक के रा ान कार्डो का किस्सा चल रहा है उसी तरह से सारी स्टेट मे और भी रा ान कार्ड बने हुए है। मैं जानना चाहता हूं कि रा ान कार्ड बनाने का क्या क्राइटेरिया है किस अफसर के दस्तखत से यह भाहर मे लगाया जाता है और किसने दस्तखतों से गांव मे बनाया जाता है ? जिन्होंने रा ान कार्डो पर दस्तखत किये है, उनके खिलाफ दस्तखतों से गांव मे बनाया जाता है ? जिन्होंने रा ान कार्डो पर दस्तखत किये है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लछमन सिंहः हमारे महकमे के आदमी डोर टू डोर रा ान कार्ड बनाने जाते है। भाहरों मे तो किसी लोकल एम0 एल0 ए0 या एक्स म्यूनिसिपल कमि नर के दस्तखत होते है और गांवों मे किसी सरपंच, नम्बरदार या हरिजन पंच के दस्तखत होते है। जहां तक उनके खिलाफ कार्यवाही का संबधं है, अभी चेंकिंग चल रही है। अब तक हम 312000 रा ान कार्ड बीड आउट कर चुके है। जो आदमी रा ान कार्ड बनवाता है उसे भी एफीडैविट

देना पड़ता है कि मेरी फैमिली के मैंबर इतने है। अगर किसी का गलत ऐफीडैविट होगा, तो उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जायेगी।

श्री फतेह चंद विजः अभी मंत्री जी ने रोहतक की पापुले ान 1981 के सैंसस के मुताबिक बताई लेकिन बीच मे एक मंत्री जी बैठे बैठे कह रहे है कि कि अभी सैंसस की फिगर्ज नही आई तो इन दोनों बातों मे से कौन से कुलैक्ट की है।

चौधरी हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भाहरों मे जो रा ान कार्ड बनाए गये है वे 1981 की सैंसस के आधार पर बनाए है क्या गांवों मे भी 1981 की सैंसस के आधार पर रा ान कार्ड बनाए जायेंगे ?

श्री लछमन सिंहः गांवों मे भी 1981 की सैंसस के आधार पर ही बनेंगे लेकिन अगर कोई बच्चा उसके बाद पैदा होता है तो उसका भी तो बनाना पड़ेगा।

चौधरी हरि चंद हुडडाः स्पीकर साहब, सरकार का महकमा ही डोर टू डोर जा कर रा ान कार्ड बनाता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लगभग 30 हजार कार्ड बनाए गए थे वे मंत्री जी के महकमें ने ही बनाए थे इसलिये सरकार ही इसकी हम्मेदार है? क्या यह बात ठीक है ?

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

श्री जयनारायण वर्माः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि सारी स्टेट मे 3 लाख 12 हजार बोगस यूनिटस पकड़े गये है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा स्टेट मे यह घोटाला जहां भी हुआ हो, क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार नही है और अगर जिम्मेदार है तो क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार नही है तो क्या इस बात के लिये सदन मे खेद प्रकट करेगी?

(इस प्र न का उत्तर नही दिया गया)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक चीनी के वितरण का ताल्लुक है। खास तौर पर गांवो के डिपू होल्डर्ज महीने की 29 या 30 तारीख को चीनी ले कर जाते है और वह चीनी 31 या पहली तारीख को वितरित करते है। इसलिये दो महीने की चीनी का वितरण केवल एक बाद ही होता है। इस तरह से हजारों बोरी चीनी का घोटाला होता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ऐसी कोई डैड लाइन फिक्स करेंगे कि यदि कोई डिपू कैंसिल कर दिया जायेगा ?

श्री लछमण सिंहः स्पीकर साहब, पहले भी यह ि ाकायत हमारे नोटिस मे आई थी। अब यह फैसला कर दिया गया है कि डिपु होल्डर्ज महीने की 15 तारीख तक चीनी उठायेंगे। पिछले महीने भूगर मिल की तरफ से चीी मिलने मे कुछ दिक्कत आ गई थी। अब हम मार्च और अप्रैल की चीनी इकटठी दे देंगे।

चौधरी हर स्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रोहतक भाहर मे जो रा ान कार्ड बनाए गए थे उनकी चैंकिग करने वाला कौन है ?

श्री लछमण सिंहः स्पीकर साहब, मौजूदा सरकार चैक कर रही है। यह पुरानी सरकार का घोटाला है।

श्री मूल चंद जैनः स्पीकर साहब, इसी सवाल के बारे मे सितम्बर सै ान मे मंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा के अंदर अढ़ाई लाख बोगस यूनिटस कैंसिल कर दिये गये। आज मार्च का महीना चल रहा है, और इसको 6 महीने हो चुके है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सरकार इन 6 महीनों मे 15–16 लाख यूनिटस मे से केवल 75 हजार यूनिटस ही क्यों कैंसिल कर सकी है ?

(इस प्र न का कोई उत्तर नही दिया गया)

Crash programme for providing training to the Members of Scheduled Casts

***2746. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) whether any crash programme for providing training to the members of Scheduled Caste for recruitment through the Banking Services

Commissions was launched in the years 1980 and 1981; if so, the number of organisers, if any, apointed for the purpose togetherwith the details regarding their qualifications and salaries payable;

(b) whether the qualification salaries, T.A., D.A., Medical charges and othe facilities allowed to the said organisers were approved by the State Goverment, if so, the method fo recruitment prescribed for the posts of organisers;

(c) whether any persons have been imparted the training as referred to in part (a) above; if so, the number togetherwith the places of their training, number of batches and the names and addresses of trainees, if any, absorbed in the Banks;

(d) total expenditure so far incurred on the Salaries, T.A./D.A./Medical Charges and other facilities of the organisers togetherwith the amount of scholarships, if any, given separately; and

(e) whether the expenditure incurred on the said programme has been audited by the Audit parties?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्रीमती भाकुंतला भगवाड़िया): (क, ख, ग, घ, और ड़) इस बारे मे सूची सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

(क) हां दो क्रै ा कोर्स चलाये गये थे, प्रथम क्रै ा कोर्स एक मास के लिये दिनांक 4–8–80 से 4–9–80 तक चलाया गया था। यह समय बहुत थोड़ा था। इसलिये दूसरा कोर्स 3 मास के लिये चलाया गया था जो दिनांक 1–1–81 से 31–3–81 तक चला था। प्रथम क्रे ा कोर्स मे 2 संस्थापक (आर्गेनाईजर) नियुक्त कियये गये थे तथा दूसरे कोर्स मे तीन संस्थापक जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

(1) प्रथम क्रै ा कोर्स			
क्र0	**संस्थापक का नाम**	**योग्यता**	**मानदेय प्रतिमास**
1	डा0के0जी0 वरमानी	एम0ए0पी0एच0डी0 प्रवक्ता भौक्षणिक फिजोलौजी युनिट एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली।	2100/-
2	डा0 टी0 आर0 भाटिया	एम0ए0पी0एच0डी0 एसोि ाएट प्रोफेसर	2100/-

		नै ानल इन्स्टीच्यूट आफ प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रे ान, नई दिल्ली।	
(2) दूसरा क्रै ा कोर्स			
1	डा0 टी0आर0 भाटिया	यथोपरी	2500/-
2	कर्नल एस0बी0 सेठ	भूतपूर्व सदस्य रक्षा चयन बोर्ड	2500/-
3	कैप्टन जी0जे0 भााह	बतौर प्र ि ाक्षक प्र ाासकीय कोर्सों को चलाने मे उचित अनुभ तथा फिजोलोजी का अनुभव।	2500/-

(ख) हां सरकार की स्वीकृति के प चात् नियुक्ति नियत सौदे अनुसार की गई थी।

(ग) हां निम्न ब्यौरे अनुसारः

(1) प्रथम बैच		
स्थान का नाम		परीक्षार्थियों की संख्या
अम्बाला		35
रोहतक		39
	कुल योग	74
(2) दूसरा बैच		
अम्बाला		46
रोहतक		50
भिवानी		42
	कुल योग	138

प्रथम बैचः 57 हरितन प्र ि ाक्षणार्थियों के रोल नं0 विभाग के पास था जिनमे से 7 विद्यार्थियों (12 प्रति ात) ने लिखित परीक्षा पास की थी।

दूसरा बैचः 138 हरिजन उम्मीदवारों मे से केवल 123 विद्यार्थी परीक्षा मे बैठे थे जिनमे से अभी 17 विद्यार्थियों का परिणाम आना बाकी है। बाकी 106 विद्यार्थियों के परिणाम जिनमें से 48 विद्यार्थी 45 प्रति ात लिखित परीक्षा मे पास हो गए है। पास विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिये प्र ि ाक्षण दिया गया था। साक्षात्कार के प चात् अंतिम परिणाम अभी घोशित नही हुआ।

(घ)	**प्रथम बैच**	**दूसरा बैच**
वेतन	4335-00	25000-10
यात्रा भत्ता	658-00	1977-00
डी0ए0	-	-
चिकित्सा प्रतिपूर्ति अन्य सुविधायें	-	-
छात्रवृति की रा ि ा	3763-05	48838-30

कुल योग	8756-05	76572-40

क्रै ा कोर्स के खर्चे का 50 प्रति ात भाग केन्द्र सरकार ने बहन किया है यद्यपि दोनो कोर्स तजुर्बे के तौर पर चलाए गये थे।

(ड.) महालेखापाल द्वारा तीन वर्श मे एक बार लेखा निरीक्षण किया जाता है। अभी तक इसका लेखा परीक्षा नही किया गया।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस सवाल के जवाब मे राज्य मंत्री महोदया ने कहा है कि अनुसूचित जाति के कैंडीडेटस जो बैंक सेवा मे आना चाहते है उनको दो बैचिकज मे प्र ि ाक्षण दिया है। उन दो बैचिज मे लगभग 212 लोगो ने प्र ि ाक्षण लिया है। मैं राज्य मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उन 212 कैंडीडेटस मे से कितने कैंडीडेटस बैंकों मे विनियुक्त हुए है ?

श्रीमती भाकुन्ता भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय, अभी उनकी लिखित परीक्षा हुई है। इन्ट्रव्यू नही हुआ है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, बैंक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये हरियाणा मे रोहतक, भिवानी और अम्बाला सैंटर्ज है। मैं राज्य मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि उन सैंटर्ज मे

जो ट्रेनीज ट्रेनिंग लेते है, क्या उनको स्टाइपैंड दिया जाता है यदि दिया जाता है तो कितना दिया जाता है?

श्रीमती भाकुन्ता भगवाड़िया: स्पीकर साहब, ट्रेनीज को वजीफा सरकार की तरफ से दिया जाता है। अम्बाला ट्रेनिंग सेंटर मे 125 रूपये वजीफे के दिये जाते है और भोश दो जगह पर 75 रूपये दिये जाते है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं राज्य मंत्री महोदया से जानना चाहता है कि अम्बाला ट्रेनिंग सैंटर मे ट्रेंनीज को ज्यादा वजीफा क्यों दिया जाता है।

श्रीमती भाकुन्ता भगवाड़िया: स्पीकर साहब, अम्बाला मे इसलिये जयादा दिया जाता है क्योंकि वहां पर स्टाइपैंडरीज को होस्टल मे ठहरना पड़ता है।

डा. मंगल सैन: स्पीकर साहब, राज्य मंत्री महोदया ने सवाल के जवाब मे कहा है कि दो बैचिज मे यहज प्रि ाक्षण दिया गया है और प्रि ाक्षण देने वालो पर एक बैच मे 4200 रूपये खर्च हुए है और दूसरे बैच मे 7500 रूपये खर्च हुए है। मैं राज्य मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि प्रि ाक्षण देने वाले कितने संस्थापक थे और क्या उन पर इतना ही पेसा खर्च हुआ है जितना स्टेटमैंट मे दिखाया है या इसके अलावा और भी खर्च हुआ है ?

श्रीमती भाकुन्ता भगवाड़िया: स्पीकर साहब, पहले बैच को डा0 के0जी0 बरमानी, एम0ए0पी0एच0डी भाटिया,

एम0ए0पी0एच0डी, एसोि ाएट प्रोफेसर नै ानल इंस्टीच्यूट आफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रे ान, नई दिल्ली ने प्रि ाक्षण दिया और दूसरे बैच को डा0 टी0आर0 भाटिया, कर्नल एस0बी0 सेठ, भूतपूर्व सदस्य रक्षा चयन बोर्ड और कैप्टन जी0जे0 भााह ने प्रि ाक्षण दिया। इन पर जो भी खर्च हुआ है वह सवाल के जवाब मे लिखा हुआ है।

Construction of Farmers Rest House at Rania

***2672. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether any farmers Rest House is proposed to be constructed at Rania, in District Sirsa by the Marketing Board; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Rest House is likel to be constructed?

कृशि मंत्री (श्री भाम ोर सिंह):

(क) जी हां।

(ख) 31–8–82 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों

के लिखित उत्तर

Construction of Metalled Roads

***2681. Chaudhri Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state the total length of metalled roads constructed in the Darba Kalan, Adampur and Gharaunda Constituencies during the years 1980-81 and 1981-82 upto the 31st January, 1982, separately?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह): अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:—

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र	जिन वर्शो के माध्य जितनी कि0मी0 सड़कें पक्की की गई	
		(क)	(ख)
		1980—81	1981—82 (जनवरी 82 तक)
1	दड़वा कलां	12.21	6.20
2	आदमपुर	37.87	33.80

3	घरोंड़ा	34.86	25.72

Pucca Roads in Salhawas Constituency

***2712. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the following roads pucca in Salhawas constituency:-

(i) Sallanga to Dhalanwas

(ii) Dhalanwas to Jhamari

(iii) Bithla to Amboli

(iv) Malesiawas to Curyane-Jhajjar Road

(v) Birar to Nangaonwa

(vi) Ahmadpur Partal to Palhawas

(vii) Matanhail to Khaparwas

(viii) Matanhail to Intola

(ix) Tumna to Khushpura

(x) Lula Ahir to Daroli

(xi) Bhurthala to nangal Pathani

(b) if, so, the time by which the abvoe said roads are likely to be made pucca?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) सलांगा से ढालावास सड़क पहले ही बनाई जा रही है। मातनहेल से खापड़पास सड़क की मंजूरी दी जा चुकी है। परंतु इस पर अभी कार्य आरम्भ नही हुआ है। टुमणा से खु ापुरा सड़कों मे से कोई भी बनाने का फिलहाल प्रस्ताव विचार के लिये नही लिया गया है।

(ख) इस समय यह बताना सम्भव नही है कि किस समय तक सड़कें पक्की कर दी जायेगी।

Escapes on the Western Yamuna Canal near Indri

***2730. Chaudhri Satvir Singh Malik:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of escapes ont he Western Yamuna Canal near Indri in district karnal together with the dates on which desilting or remodelling, if any, was done on such escapes togetherwith the location and the expenditure incurred thereon; and

(b) the difference of height in feet between the bed of Indri escape and head regulator?

Irrigation and Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) There is only one Escape of Western Yamuna Canal near Indri in District Karnal i.e. Indiri Escape. The work of desilting the Escape Channel was carried out during the year 1974-75 to 1977-78 and the total expenditure incurred was Rs. 5.53 lacs.

(b) The difference of height in feet between the bed of Indri Escape and Head Regulator is 3.18 ft.

Tubewell Connections in Mahendergarh District

***2737. Rao Bansi Singh:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of a applications for tubewell connections; if ano, lying pending in district Mahendergarh upto 28-2-1982;

(b) the total number of tubwell connections given in district Mahendergarh during the year 1981-82; and

(c) the number of tubewell connections proposed to be given in Ateli Constituency during the year 1981-82?

Irrigation and Power Minister (Sardar Tara Singh):

(a) 4525 applications for Tubewell connections were lying pending in district Mahendergarh upto 28-2-1982, the number of test reports for this period, however, were 1285.

(b) 999 Nos. tubewell connections were released upto 28-2-1982 out of the test reports.

(c) About 250 tubewell connections are proposed tobe released in Ateli Constituency during the year 1981-82.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Animal Husbandry Hospitals & Dispensaries

590. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state—

(a) the districtwise names of the places where Animal Husbandry Hospitals and dispensaries were opened in the state during the year 1979-80, 1980-82 (todate) separately;

(b) the districtwise names of place where Hospitals and Dispensaries as referred to in part (a) above, are proposed to be opened during the year 1982-83; and

(c) the criteria, if any, adopted for opening such Hospitals and Dispensaries?

Jails & Dairy Development Minister (Chaudhri Shiv Ram Verma):

(a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Hospitals/Dispensaries are opened ont he basis of necessity and the availability of funds in a particular year. As such districtwise name of palce cannot be given at this stage.

(c) Normally a stockman centre/veterinary dispensary is opened at a place where exists no facility for verterinary and and breeding. As soon as a Gram Panchayat of village comes forward with a resolution that is would provide rent free accommodation for the stockman centre as well as for the staff, the department considers the request. Besides, the Gram panchayat also undertakes to construct a new building within a reasonable period.

Veterinary Hospitals are not opened by the departemnt directly, originally only Veterinary Dispensary/Stockman Centres are opened and later on these are upgraded to Veterinary Hospitals cum Breeding Centres.

A Veterinary DispensaryStockman Centre is considered for upgradation ot Hospita cum Breeding Centre ont he reques5t of the Gram panchaya5t. For this purpose it comes forward with a resultution that it will provide additional required rent free accommodation for Hospital cum Breeding Centre as well as for the staff. Besides, the Gram panchayats also undertakes to construct addtional building both for

Hospital cum Breeding Centre and the Staff within a reasonable period.

STATEMENT

Districwise Veterinary Dispensaries and Hospitals opened during 1979-80.		
Name of the district	Name of places where dispensary opened	Places where Veterinary Institutions upgraded into Hospital cum Breeding Centre
1	2	3
Ambala	1. Nanhera 2. Ganoli	Dhin
Bhiwani	1. Chirya	1. Bara Rangran 2. Birhi Kalan 3. Kadam
Faridabad	1. Bhuapur	1. Sehatpur Palla
Gurgaon	1. Hassanpur Taoru	-
Hisar	1. Newli Kalan 2. Kharia	1. Siswal 2. Nehla

	3. Bhadaheri 4. Saleemgarh 5. Rawalwas 6. Gorchhi 7. Modakhera 8. Bagla 9. Kajal 10. Pirthala 11. Thuian 12. Bhana 13. Ahrawan 14. Gorakhpur 15. Mohamadpur Sota 16. Jandli 17. Karnauli 18. Jakhal 19. Khajori 20. Haroli	

	21. Panihar Chak 22. Sultanpur 23. Chanaut	
Jind	1. Akalgarh 2. Padahna 3. Shahpur 4. Morkhi 5. Karkhana 6. Belarkhan	1. Lajwana Khurd 2. Buwana
Karnal	1. Mahayudin Pur 2. Garhi Birbal 3. Jhanjheri 4. Kokhni 5. Dapkoli Kalan 6. Udana 7. Panhera 8. Biana 9. Gadhi jattan 10. Badhara	1. Karsadod 2. Jamba 3. Salwan

	11. Saga 12. Parsalu 13. Sikri 14. Anjan Thali 15. Aluwala 16. Imrat Purkalan 17. Urlana Kalan 18. Chamrara 19. Kalkha 20. Kohrana 21. Alupur 22. Bhadaur 23. Gajbar 24. Gander 25. Pada 26. Karsa Chor 27. Mohri Jagir 28. Dadupr Raran 29. Majra Roran	

Kurukshetra	1. Man Desheri 2. Ahun 3. Munarheri 4. Jandota 5. Kohta Pur 6. Pipli 7. Madhana 8. Busthala 9. Ishaq	1. Rasina 2. Umri 3. Gumthala 4. Thana
Mohindergarh	1. Dogra Ahir 2. Bawana 3. Puran Pura 4. Jabwa	
Rohtak	1. Bhagwati Pur 2. Baniani 3. Birohad 4. Bahwa 5. Lula Ahir 6. Biswa	1. Mokhra

	7. Bhindawas 8. Bhamnola 9. Budhani 10. Munda Kheri 11. Kharkara 12. Farmana	
Sirsa	1. Lahenga Wala 2. Jordrehi 3. Fatehpur Jotewali 4. Fatehpur Bishnoi	1. Bara Gudha 2. Nathusari kalan 3. Dudinwali
Sonepat	1. Purkhas 2. Panchhi Jattan 3. Mohana 4. Garibala 5. Joli 6. Rukhi 7. Ananwali 8. Gaoli	

Districwise Veterinary Dispensaries and Hospitals opened during 1980-81		
Ambala		1. Ugla 2. Jansuna 3. Panchkula 4. Buria
Bhiwani	1. Kakroli Sardara	1. Pureh 2. Pichopa Khud
Faridabad	1. Puthali	1. Manpur 2. Mohana
Gurgaon	1. Bubalheri 2. Sakras	1. Hassanpur Taoru 2. Ujina 3. Mandi Khera
Hissar	1. Mohabatpur 2. Bahbilpur 3. Ladwi 4. Nangthala 5. chindhar 6. Akkanwali	1. Bhattu 2. Jakhal 3. Gorakpur 4. Rakhi Sahapur

	7. Gandu 8. Jhalania 9. Dhanger 10. Bighar 11. Khabra 12. Hassangarh 13. Sisi Bola	
Jind	1. Malvi 2. Mataur	1. Nidana 2. Popra 3. Dhathrath 4. Sindhwi Khera 5. Kharal 6. Dhanauri
Karnal	1. Sambhi 2. Barwa 3. Abhla Jagir 4. Jormajra Kalan 5. Panjokhera 6. Dabriki	1. Taraori 2. Amin 3. Sultanpur 4. Jhanjhari 5. Binana 6. Kutail

	7. Gunana	7. Jorasi 8. Kalron 9. Bapoli 10. Staundi 11. Aunak 12. Gadah
Kurukshetra	1. Deoban 2. Pindarsi 3. Chuhar Majra 4. Khananura	1. Karura 2. Babri 3. Pai 4. Munner Heri 5. Charhboni Jattan 6. Thol 7. Dogra Ahir 8. Siha
Mohindergarh	1. Berawas 2. Daroli 3. Sobhapur 4. Mandhana 5. Basdod	1. Dogra Ahir 2. Siha

	6. Bhungarwa 7. Tothwalka	
Rohtak	1. Ballamba 2. Chhapar 3. Soalda 4. Ukhalchana 5. Jasaur Kheri 6. Sundana 7. Sweana	1. Khadwali 2. Chhuchkwas 3. Silani 4. Birohar 5. Kalahwar 6. Kharhar
Sirsa	1. Maujgarh	1. Rori
Soepat	1. Tarakpur 2. Pipli Khera 3. Moi Majra 4. Jwahra	1. Begha 2. Khubru
Districwise Veterinary Dispensaries/Hospitals opened during 1981-82		
Ambala	1. Khatauli	1. Sahbapur 2. Jalbahra 3. Kathgarh Chhabra

Bhiwani	1. Rawatkhera	1. Jhumpa Kalan 2. Bhera 3. Chang
Faridabad	-	1.Panehra Khurd 2. Rupeka 3. Mandkaula 4. Hassanpur
Gurgaon	-	1. Rathiwas 2. Sakras
Hisar	1. Chuhar Pur 2. Mandouri 3. Kanoh 4. Nayana 5. Data 6. Hujravan Khurd 7. Baliala 8. Hanspur 9. Nathuwal	1. Bhoj Raj 2. Nangla 3. Kharar Alipur 4. Daulatpur

	10. Burak 11. Kot Kalan 12. Dharsul 13. Satraud Khurd 14. Nadodi 15. Ramsara 16. Massodpur 17. Kaluwas 18. Bad Chhapar 19. Kirmara 20. Sidhani 21. Ladhuwas 22. Khai 23. Khundan 24. Kirori 25. Depal	
Jind	1. Badanpur	1. Karkhana 2. Danoda Kalan 3. Amargarh

		4. Dhamtan Sabib 5. Kalwa 6. Morkhi
Karnal	1. Bahola	1. Kaimla 2. Kurana 3. Saga 4. Mohri Jagir 5. Anjanthali 6. Kalkha 7. Bastali 8. Kheri Saraf Ali 9. Yunaspur
Kurukshetra	-	1. Jhiwar Hari 2. Mehra
Mohindergarh	-	1. Sundrea 2. Dahina
Rohtak	1. Sisarkhas 2. Samchana 3. Bupania	1. Saman 2. Dubaldhan 3. Jasor Kheri

	4. Tumbaheri 5. Matana 6. Daboda Khurd 7. Kirholi Pehladpur 8. Mundhara 9 Bharan 10.Kharman	
Sirsa	-	1. Kingre
Sonepat	1. Rithal 2. Dipalpur 3. Mahmudpur 4. Saidpur 5. Ahulana 6. Bidhlan 7. Nathupur 8. Jatheri 9. Shamari Sisan 10.Kahni	1. Kharkhoda 2. Mohana

	11.Bhagan	

Supply of Coal of Industrial Units

591. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state—

the total quantity of coal required for supply to each Industrial unit in the State as per latest assessment made by the Industries Department separately;

the total quanitity of coal received agains assessed capacity by each such unit, as referred to in part (a) above during the period from 1.4.81 (to date) seperately;

the criteria, if any, adopted for making assessment of requirement and supply of coal, separately; and

the names of such units, if any, recommended for excessallotment of coal, during the period as referred to in part (a) above by the Chief Minister, Food and Supplies Minister or any other authority than Director of Industries, Haryana separately, togetherwith the reason therefor?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal): The time and labour involved would not be commensureate with any possibelr benefite to be obtained.

Loan application with Industries Department

592. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state—

the names and addresses of persons/firms/units, who applied for loand to the industries Department unde rthe Punjab State Aid to Industries Act and Rules, during the period 1-4-80 to todate, together with the date of application and amount of loan applied for in each case, separately;

the names and addresses of such persons/firms/units, out of thoese referred to in part (a) above who have been sanctioned loands, todate togetherwith the amount of loan sanctioned and date of sanction, separately; and

the criteria, if any, adopted for the sanction of loans, as referred to in part (b) above?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal): The time and labour involved would not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Rural Industrial Units

593. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the districtwise total number of Rural Industrial Untis working at present int he rural areas of the State;

(b) the district wise number of Rural Industrial Untis set up in Villages during the period from 1-4-80 to 31-3-81 and 1-4-81 to date separately, in villages of each district of the State;

(c) the total quantity of raw material required by the Industrial Units referred to in part (a) above, as per latest assessment made by the Industries departement toghetherwith the names of raw material required by each such units every year, separately; and

(d) the quantity of raw material received by the Industiral units, as referred to in part (a) above during the period 1-4-79 to 31-3-80, 1-4-80 to 31-3-80 and 1-4-81 to date, separately?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal):

(a) 8151 Units have been set up since the inception of the scheme in 1977-78 upto 28-2-1982 in the rural areas under Rural Industrieal Scheme. District wise position is given as under:-

Sr.	**District**	**No. of units set**

No.		up
1	Ambala	754
2	Bhiwani	508
3	Faridabad	558
4	Gurgaon	673
5	Hissar	609
6	Jind	497
7	Karnal	707
8	Kurukshetra	519
9	Mohindergarh	749
10	Rohtak	1220
11	Sirsa	535
12	Sonepat	823
	Total	8151

(b) 2812 and 3114 units were set up under RIS during the period from 1-4-80 to 31-3-81 and 1-4-81 to 28-2-82 respectively. The district wise position is given as under:-

Sr.	District	No. of units set up

No.		1-4-80 to 31-3-81	1-4-81 to 31-2-82
1	Ambala	152	485
2	Bhiwani	192	172
3	Faridabad	203	243
4	Gurgaon	209	323
5	Hissar	210	204
6	Jind	200	163
7	Karnal	237	221
8	Kurukshetra	206	161
9	Mohindergarh	166	360
10	Rohtak	564	375
11	Sirsa	140	210
12	Sonepat	333	197
	Total	2812	3114

(c) & (d) The time and labour involved in furnishing the requisite information will notbe commensurate withe any posisble benefit to be obtained.

Demand of the Haryana Civil Medical Service Association

634. Shri Ram Singh Mann: Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether the government has recently recieved any six point demand latter from Haryana Cicil Medical Service Association;

(b) the number of demands out of those referred to inpart (a) above which have been accepted by the Government; and

(c) the reasons for which the other demands have not been accepted?

Health & Tourism Minister (Chaudhir Gajraj Bahadur Nagar):

(a) Yes.

(b) Three demands namely (i) advance increments for post GRADUATES (ii) Rural allowance to B.M.Os. and (iii) use of amublance in hospital to call doctors on emergency duty and int he alternative if the vehicle as not availabe to permit them to claim mileage are under consideration. Regarding the fouth demand, 20 % reservation for H.C.M.S. doctors for Post Graduates has already been ordered.

(c) Rest of the demnads are not considered justified.

Rural Area Education Allowance and Medical Allowance to the Teachers

635. Shri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposalunder consideration of the Government to give Rural Area Education Allowance and Medical Allowance at flat rate to the teachers working in the Government Schools, and

(b) if so, the period within which the above concessions are likely to be allowed?

Education Minister (Chaudhri Des Raj):

(a) No.

(b) The quesiton does not arise.

Bridge over drain No. 8

6632. Chudhri Ajit Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge over Drain No. 8 in village Bakra of beri constituency; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bridge is likely to be constructed?

Public Works Minister (Kanwar Ram Pal Singh):

(a) Yes.

(b) The time for the construction of the bridge can not be specified, as it will depend upon the availablity of funds.

T.A. drawn by the Chief Minister and Chief Parliamentary Secretary

633. Chaudhri Ajit Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the amount of travelling allowance drawn by the Chief Minister and chief Prliamentary Secretary during the period from 1st January, 1981 to 3-3-1982?

Chief Minister (Chaudhri Bhajan Lal):

Sr. No.	Name & degisnation	T.A. (in repees)	Remarks
1	S/Sh. Bhajan Lal, C.M.	53878-25	-
2	S/Sh. Ram Kishan, C.P.S	10075-00	Appointed CPS w.e.f 14-1-81.

राज्य पाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः आदरणीय मैंबर साहेबान, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आज केवल राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा होगी। मैंबर्ज साहेबान गवर्नर एड्रैस पर ही बोल सकते है। बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आज न तो जीरो आवर होगा और नही काल अटैंशन मो ान आदि होंगे। यह फैसला इसलिये लिया गया था ताकि राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर अधिक से अधिक सदस्य बोल सके।

अब राज्यपाल महोंदय के अभिभाशण पर बहस होगी। श्री रणसिंह मान अपना भाशण आरम्भ करेंगे।

श्री रणसिंह मान (बादड़ा): स्पीकर साहब, राज्यपाल महोकदय ने अपने अभिभाशण के अंदर सरकार की बहुत तारीफ की है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय सत्तरूढ़ पार्टी के सदस्यों का व्यवहार ओर आचरण केवल इन दो लाईनों मे पढ़ कर ही समाप्त कर सकते थे। श्री हरस्वरूप बूराजी इस तरफ ध्यान देंगे । वे दो लाईनें य है–

'भजन लाल का राज है लूट सके सो लूट,

अययाा ी तो खत्म होगी जब राज जायेगा टूट।'

डिप्टी स्पीकर साहब, इस लूट ओर अय्या ी की कहानी मे ने केवल एक आदमी या वजीर है, बल्कि सत्तरूढ़ पक्ष के अनेक सदस्य भाामिल है। इस लूट की कहानी को सबसे पहले मैं ठाकुर बीर सिंह जी के महकमे से भाुय करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब हांसी स्पीनिंग मिल के अंदर इन्होंने अपनी ही जाति के व्यक्ति को एम.डी. नियुक्त करा दिया है। उनको वहां नियुक्त कराने के लिये उनसे कि तें बांधी हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर 29 सिक्योंरिटी गार्डस की भर्ती की गई है। इन 29 सिक्योरिटी गार्डस से सारे के सारे इन्ही की जाति से संबंधित है। इस नियुक्ति मे न किसी हरिजन भाई को लिया गया और न ही किसी बैकवर्ड क्लासिज के भाई को लिया गया । (ोम भोम की आवाजें) । (ाोर) जो एम. डी. वहां पर लगाया गया है वह इन्होंने ही लगवाया था। इन्होंने उनको 70 लाख रूपये के धागे सप्लाई करवा कर सारे के सारे दूसरे रास्ते से कम भाव पर बेच दिये। इससे सरकार को लाखों का घाटा हुआ है, सरकार को इस बात कली तरफ ध्यान दे कर इसका जवाब देना चाहिए। यहां पर हैफेड़, हरको बैंक ओरलैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक की काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिये मैं उनके बारे मे ज्यादा नही कहना चाहता। इन्होंने हैड आफिस हरकों बैंक मे भी भर्ती की है। इस भर्ती के दौरान असिस्टैंट मैनेजर और एकसउंटैंट लिए है। इन दोंनो पोस्टों के लिये 23 पद भरे गये है। इन 23 पदों मे से चार

वि नोई लिये है और 14 राजपूत लिये है। दूसरी जातियों के भाायद 4 आदमी लिये है। मैं अपने हरिजन मैंबर साथियों को बताना चाहता हूं कि एक भी हरिजन या बैकवर्ड क्लासिज का आदमी नही लिया गया। सभी के सभी अपनें भर्ती किये है। डिप्टी स्पीकर साहब इसी तरह से फरीदाबाद मे सैंट्रल को आप्रेटिव बैंक के अंदर कुछ पद भरे गये है। जिस समय आखबारों मे निकाला गया उस समय यह विज्ञापन छपा था कि ये पद हरिजन कैंडीडेटस से भरे जायेगें। लेकिन बाद मे इन्होंने ये पद रिजर्वे ान कोटे से न भर कर अपनी जाति के लोगो से भर लिये। इससे बढ़कर की इनके लिये और क्या बात हो सकती है ? डिप्टी स्पीकर साहब, ये बतौर रैफरी की कला मे माहिर है। खेत के अंदरएक खिलाड़ी मैंदान से बाहर हो जाये तो भी रैफरी उसको वापस बुला लेता है लेकिन ये ऐसे रैफरी है जो बाहर खड़े खिलाड़ी को भी फाउल दे सकते है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक निहायत ईमानदार आफिसर है। उसका यदि मैं नाम भी यहां पर ले दूं तो कोई गलत बात नही होगी। इस आफिसर का नाम श्री भगवान सिंह है। यह दो वर्श से एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की तरफ से कोआप्रे ान डिपार्टमैंट मे ओन डैपूटे ान पर था। भरागवान सिंह इतना ईमानदार और मेहनती आदमी है जिसकी जितनी भी प्र ांसा की जाये कम है। इससे घटिया बात ओर क्या हो सकती है ?डिप्टी स्पीकर साहब, आज अमलोक सिंह की इंटैन् ान व रामचंद्र ढाका की हैरासमेंट के किस्से भी सयब की जुबान पर है। एफ0 सी0 ने बहुत विस्तार के साथ इनकी रिपार्ट को देखा है। यदि सी0 एम0 साहब मे हिम्मत

है तो वह रिपोर्ट पे ा करे। डिप्टी स्पीकर साहब, ठाकुर बीर सिंह की कहानी का किस किस को नही पता। प्रत्येक को मालूम है कि ये किस प्रकार से काम कर रहे है ? (ाोर)

ठाकुर बीर सिंहः * * * * * *(ाोर)

श्री रण सिंह मानः * * *(ाोर) आप बीच मे कैसे बोल रहे है। आपको हमारी बातें सुननी चाहिए। (ाोर) बाद मे बोल लेना। (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीर साहब, इनको ** * का भाब्द नही कहना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्षः इस भाब्द को एक्सपंच कर दिया जाये।

श्री रण सिंह मानः डिप्टी स्पीकर साहब, आज ठाकुर जी ने जातीय उन्माद, जातीय आधार पर पक्षपात व भाई भतीजाबाद का नंगा प्रद र्न किया है। (ाोर) डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा के अंदर हुडडा मे गदर मचा हुआ है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैंडिंग है। इसलिये मैं इस समय को और नही उछालता। उन्होंने अपनी मर्जी से माफी लोगों को स्वैच्छित कोटे से मकान ओर प्लाटस अलाट किये है जो कि एकदम गलत काम है। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): श्री चरणसिंह ने भी तो लिया हुआ है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः उनको तो हमने दिया था। इसमे आपका कोई हाथ नही है।(ाोर)

श्री रण सिंह मानः डिप्टी स्पीकर साहब, परिवहन मंत्री के पहिए की जितनी भी तारीफ की जाये वह कम है। यह पहिया जींद से भ्रुरू हो कर भिवानी होता हुआ वाया पटौदी हाउस, देहली से अम्बाला मे आकर अपना रंग दिखा चुका है। (ाोर) वह पहिया अब भी अपनी रफतार बनाए हुए है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः मान जी आप राज्यपाल जी के अभिभाशण पर ही बोले, इससे इधर उधर न जायें। (ाोर)

श्री रण सिंह मानः ठीक है जी। यदि ऐसी बात जो परिवहन मंत्री जी कर रहे है किसी भले आदमी से गलती से हो जाये तो डूब कर मर जाये।

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): @ @ @ @ @

श्री रण सिंह मानः @ @ @ @

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाये। मान जी आप राज्यपाल जी के अभिभाशण पर ही बोले। (ाोर) आप किसी का नाम न ले। (ाोर) आप राज्यपाल के अभिाभाशण पर ही बोले।

I draw the attention of the hon'ble Member to rule 100 of the Rules of Produre and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembby. (Interruptions) If you do not hear me, I am sorry for that.

Rule 100 says-

1. The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly.

2. A member while speaking shall not-

1. reflet upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms.

2. use the name of persons in high authoirty for the purpose of inifluencinig the debate.....

So if the Member wants to reflect upon the conduct of a person he may move substantive motion but now he should restrict debate on the Governer's Address only. If the matter will be irrelevant, it will not be recorded.

श्री रणसिंह मानः डिप्टी स्पीकर साहब, झज्जर अर्बन एस्टेट में ओपन ओक ान में एक आदमी ने 40100 रूपये में भाोप–कम–फलैट का एक प्लाट खरीदा लेकिन मुझे पता लगा है कि ज्वायंट डायरैक्टर कोलोनाइजे ान ने कुछ आदमियों को जिनमें वे इंट्रैस्टिड थे औक ान की झूठी कहानी बनाकर केवल 20– 20 हजार रूपए में प्लौटस बेच दिए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रानियां में 40 भाोप–कम–फलैट औक ान होने थे। ओपन

औक ान में एक प्लोट की कीमत 149000 रूपये तक गई, लेकिन इसी ज्वायंट डारैक्टर कोलौनाइजे ान ने बाकी के सारे के सारे प्लाटस 50000 रूपये प्रति प्लोट के हिसाब से बेच दिए। जिस तरह उनको बेचा गया और झूठे औक ान की कहानी बनाई गई उससे डिप्टी स्पीकर साहब, आपको भी करप ान की कुछ न कुछ गंध आएगी। डिप्टी स्पीकर साहब, यहीं नहीं उस ज्वायंट डारैक्टर महोदय को उनकी इन सेवाओं के लिए क्योंकि उसने हाई अपस के इंट्रैस्टस को सेफ किया जिले का उपायुक्त बना दिया जबकि उसके 6 सीआर्ज खराब थे। इनके बारे में एक और बात सुनने में आई है। उसने अपने चंडीगढ रैजिडैंस के लिए वि ोश टेलिफोन के लिए प्रार्थना की है हालांकि उसका हैडक्वार्टर यहां नही है और मैनें सुना है कि इस बात की मंजूरी उसे मिल गई है।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः बिल्कुल गलत बात है।

श्री रणसिंह मानः डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी एक बात बडे गर्व के साथ कहते है कि कर्मचारियों के लिए जो कुछ इन्होंने किया उतना किसी और ने नहीं किया है लेकिन डाक्टर्ज के साथ जो दुर्व्यवहार इन्होंने किया उसका जिक्र में यहां नहीं करूंगा।

जींद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुलाजिमों के साथ इनके अपने चेहते अफसर और उसके पाले हुए गुन्डों ने जो कुछ किया उसका भी मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा लेकिन हरियाणा

अध्यापक संघ के साथ हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री जी ने जो बात की थी उसका यहां जरूर उल्लेख करूंगा। स्टेट में मुख्यमंख्त्री से बडा कोई आदमी नहीं होता। उसकी कही हुई बात की कीमत होती है। इन्होंने उस ि ाश्टमंडल के साथ 45 मिनट बात करने के बाद यह माना था कि उन्हें देहाती क्षेत्र ि ाक्षा भता और मेडिकल अलांउस फलैट रेट से दिया जाएगा। लेकिन अब वे अपनी बात से मुकर गए। यह चीफ मिनिस्टर को भाोभा नहीं देता। डिप्टी स्पीकर साहब कर्मचारियों के साथ जहां सारी स्टेट में दुर्व्यवहार हो रहा है वहां भिवानी जिले पर इनकी वि ोश मेहरबानी है। दादरी की आबादी के मुताबिक उसे बी क्लास भाहर और भिवानी को आबादी के मुताबिक ए क्लास भाहर मानना चाहिए लेकिन ये ऐसा नहीं मानते।

इसके अतिरिक्त सरकार ने कहा कि फसलों को बचाने के लिए इन्होंने बडी कोि ा ा की है लेकिन इसकी भी मैं एक मिसाल हाउस को बता देना चाहता हूं। बाढडा बडा रेतिला क्षेत्र हैं। वहां लगातार सूखे की स्थिति बनी हुई है। वहां इन्होंने फसलों को बचाने के लिए जो कुछ किया है वह मैं आपको बता देता हूं। खरीफ के वक्त सन 1978 में प्रति टयूबवैल 1870 यूनिट 1979 में 1940 यूनिट 1980 में 1902 यूनिट और 1981 में केवल मात्र 690 यूनिट बिजली दी गई। ये हैं सरकार के आंकडे जबकि अकाल की स्थिति है। बरसात नहीं हो रही है सरकार ने इस तरह की बिजली सप्लाई की है। फूड फार वर्क और एनआरपी स्कीम के

तहत 1970–80 में 112.18 लाख रूपये और 1980–81 में 146.37 लाख रूपये दिए गए लेकिन 1981–82 में इनका क्या कंट्रिब्यू ान रहा वह मैं बताता हूं। इनके सैंटर में एक वजीर है राव बीरेंद्र सिंह जी। मैंने इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उन्होंने उसे राव बीरेंद्र सिंह जी को भेज दिया। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि पहले दो क्वार्टर्ज में केवल 16.99 लाख रूपये और पूरे साल में केवल 30 लाख रूपये से कुछ उपर रा ि ा दी है। डिप्टी स्पीकर साहब इससे ज्यादा ज्यादती किसी इलाके के साथ और नहीं हो सकती। कितने अफसोस की बात है कि जिस इलाके में खेती नहीं हुई और जिसके परिणामस्वरूप वहां के खेतीहर मजदूर और कारीगर रोजगार के लिए सरकार की तरफ हाथ फैलाए खडे थे उन्हें रोजगार नहीं दिया गया। यह बडा जघन्य अपराध है। यह भाोभा नहीं देता जनतांत्रिक व्यवस्था में। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। तीन चार रोज पहले एक काल अटेन ान मो ान का जवाब यहां दिया गया। कुछ दिन पहले आंधी के कारण भिवानी के इलाके में खेती का काफी नुकसान हो गया था लेकिन इस सरकार ने टयूबवैल मालिकों को मुआवजा देने से साफ साफ इन्कार कर दिया। यह उस जिले के साथ बडा भारी भेदभाव है।

श्री उपाध्यक्षः अब आप वाइन्ड–अप करें।

श्री रणसिंह मानः डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त वित्तमंत्री जी याहं मौजद नहीं है लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ही

सुन लें। चिडिया गांव में लडकियों का स्कूल अपग्रेड हुआ था। गांव वालों ने 128000 रूपये इक्टठे किए और इन्होंने गांव के लोगों से वायदा किया था कि 256000 रूपये सरकार देगी लेकिन केवल 28000 रूपया दिया है। बाकी पैसा ये इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह स्कूल विपक्ष वालों के क्षेत्र में है। ये दावा तो बहुत करते है कि लडकियों को ि ाक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे है। लेकिन वास्तविकता यह है जो मैंने आपके सामने अर्ज की है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री के कारनामें और नियत की हम दाद देते हैं पिछले साल हम भिवानी में हुए किसानों के आन्दोलन में किसानों की मांगों के लिए और उनके दुख दर्द के लिए मरने वाले महावीर सिंह के परिवार को तो इन्होंने दस हजार रूपये दिये लेकिन इसी प्रकार पानीपत के लिए * * के जो ा में गढवाल के इलैक ान के वक्त पर मर गया था इन्होंने 50 हजार रूपये दिए। (ाोर)

चौधरी भजन लालः डिप्टी स्पीकर साहब, ये भाब्द एक्सपंज करवाए जाएं क्योंकि किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह की बात कहना गलत बात है।

श्री उपाध्यक्षः ये भाब्द एक्सपंज कर दिए जाएं।

श्री रणसिंह मानः डिप्टी स्पीकर साहब, लोकतंत्र व्यवस्था में .....

श्री उपाध्यक्षः आपका समय हो गया। आप बैठिए।

श्री रणसिंह मानः केवल दो मिनट में ही समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी बात है।

श्री उपाध्यक्षः अब चौधरी लहरी सिंह जी बोलेंगे।

श्री रणसिंह मानः डिप्टी स्पीकर साहब, लोकतंत्र व्यवस्था में यह सरकार अपना वि वास खो चुकी है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः मैं लहरी सिंह जी को कह चुका हूं इसलिए अब आप बैठिए।

श्री रणसिंह मानः डिप्टी स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुने। हांसी स्पीनिंग मिल्ज के वरकर्ज के जल्से की इजाजत लिख कर मांगी परन्तु इस सरकार ने इजाजत दी लेकिन इस भार्त पर दी कि आप मैनेजमैंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगे। (विघ्न) यह सरकार मजदूरों और किसानों के जनबादी अधिकारों को छीन रही है। यह कभी भी बरदास्त नहीं किया जा सकता। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिए। मैं लहरी सिंह जी को कह चुका हूं। अब वे बोलेंगे। आप बैठिए (विघ्न)

श्री लहरी सिंह (रादौर अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हूं कि आपने बोलेन के लिए समय दिया। सब से पहले मैं गवर्नर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि अच्छी सेहत न होने के बावजूद भी यहां आये और उन्होंने अभिभाशण हिन्दी में पडा। इतनी अधिक व्यवस्था होने पर भी

एक घंटे तक खडे होकर सदन का सम्बोधित करते रहे। उन्होंने अभिभाशण में सही बातों का जिक किया है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, राज्पाल महोदय ने अभिभाशण में जो भी बातें कही है उनके विशय में आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं। अपोजि ान के भाईयों को फोबिया हो गया है और वे हर बात को उल्ट समझते हैं। (विघ्न) अभी मेरे भाई रणसिंह मान जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरिजनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मैं आप द्वारा उन्हें अत्याचार के बारे में बात अर्ज करना चाहता हूं। जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी और हम लोग भी ट्रेजरी बैंचिज पर बैठा करते थे। हमने सदन में रिजर्वे ान के बारे में सवाल पूछा, उन्होंने गुस्से से जवाब दिया कि बैठ जाओ क्या तुम ही हरिजनों के ठेकेदार हो। उस टाईम पर ऐसा जवाब दिया जाता था तो चौधरी रणसिंह मान और चौधरी संत कंवर जी कहां गये थे। अपोजि ान के भाईयों को यह भी बताना चाहता हूं कि भजन लाल सरकार ने हरिजनों की पुलिस में भर्ती छह परसैन्ट से बढाकर 17 परसैन्ट कर दी है। रिजर्वे ान में जो 6–7 परसैन्ट ही की कमी है वह भी जल्दी ही पूरी हो जायेगी। मैं इन भाईयों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो ये दम भरते हैं कि हरिजनों का कोई उद्धार नहीं हुआ यह गलत बात कहते हैं। हरिजनों का जो भला इस सरकार में हुआ है। इतिहास में आज तक किसी भी सरकार ने इतना नहीं किया है। इस सरकार ने खाली हरिजनों का ही भला नहीं किया बल्कि अन्य

वर्गों का भी भला किया है। आप को यह जान कर हैरानी होगी कि हरिजन कल्याण निगम का जहां 2 करोड का भोयर कैपिटल था उसे बढा कर पांच करोड कर दिया है। इसके साथ–साथ बैक्वर्ड निगम कायम की। उसे दो करोड रूपया दे कर चालू किया गया। इतना ही नहीं किया बल्कि जो समाज का कमजोर वर्ग है उसके लिए भी सरकार ने निगम कायम की है। इस सरकार की कोि ा ा है कि कमजोर वर्ग के लोग भी उपर उठें। जातपात को बढावा न देकर हर वर्ग के साथ समान बर्ताव किया है। हरियाणा में बसने वाले सभी वर्गों को अधिक से अधिक सुविधांए और सहायता प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लोकदल के भाई खामख्वाह भाोर करते है कि किसी वि ोश जाति का भला किया है। इनको अपने राज की बातें याद नहीं है जब बाबू मूलचंद जैन ने बजट पे ा किया था तो उस बजट की धज्जियां उडा दी गई हालांकि वह बजट अच्छा था। डिप्टी स्पीकर साहब ये सरंक्षण का भी दावा करते हैं। इनके राज में असैम्बली के इलैक ान में हरिजनों को घरों से निकलने नहीं दिया जाता था। उन्हें वोट डालने से भी रोका जाता था।

चौधरी संत कंवरः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। आपने अभी रूल कोट किया था कि कोई सदस्य किसी वि ोश आदमी के बारे में या कीम के खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता लेकिन ये बार बार कौम का सवाल उठा रहे है।

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिए। यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री लहरी सिंह मेहराः मैंने किसी कौम का जिक्र नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब अभी चौधरी लहरी सिंह कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल के जमाने में जब हरिजनों के बारे में सवाल पूछा गया तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि क्या आप ही हरिजनों के ठेकेदार हो। इन्होंने यह भी कहा कि पुलिस में भजनलाल की सरकार में हरिजनों की बडी भारी रिक्रूटमैंट हुई है। अभी अभी मुझे टेलीग्राम मिला है उसमें लिखा है–

"Inspector General of Police Haryana has stopped from 1st March all promotions of Harijan Constables and recruitment of Harijan candidates to cause unrest amongst weaker Sections. Intervene immediately."

ये कारनामें भी भजन सरकार के ही है। (ाोर)

श्री लहरी सिंह मेहराः उपाध्यक्ष महोदय, अगर लोकदल के भाई पार्टी को ही कास्ट मानते हैं तो इनकी मर्जी है। लोकदल पार्टी का नाम है किसी जाति का नाम नहीं है। अगर ये लोकदल को कास्ट में कनवर्ट करते हैं तो अलग बात है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह गर्वनर साहब के अभिभाशण के वि ोश में कहा है। (विघ्न)

11.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में यह भी कहा है कि पिछले साल 290 करोड रूपये का बजट था जिसमें इस वर्श 30 करोड रूपए की बढौतरी की गई है। माननीय गर्वनर साहब ने इस अभिभाशण में यह भी कहा है कि यह सरकार कटिबद्ध है कि गरीब आदमियों को उपर उठाया जाए। जहां तक सरकार के कामों का सम्बन्ध है उसका भी जिक्र इस अभिभाशण में आया है। उपाध्यक्ष महोदय आपको पता ही है कि इससे पहले चौधरी देवीलाल की सरकार ने गन्ने का भाव अढाई तीन रूपए क्विंटल का दिया था लेकिन आज की सरकार ने 22 रूपए क्विंटल का भाव दिया है। आप देखिए दो अढाई साल के राज में कितना भाव गेंहू का बढाया है (व्यवधान व भाोर) इन भाईयों के दो साल के राज में सिर्फ 5 रूपए गेहूं का भाव बढाया गया था लेकिन मौजूदा सरकार ने एक ही साल में 15 रूपए फी क्विंटल गेंहू का भाव बढाया है। इन भाईयों को इस बात के लिए सरकार को दाद देनी चाहिए कि रावी–ब्यास के पानी का और एसवाईएल का फैसला करवा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इनको चाहिए तो यह था कि ये इस सरकार को बधाई देते क्योंकि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है एसवाईएल नहर की खुदाई का काम 8 ताारीख को पंजाब के इलाके में भाुरू हो जायेगा। इसका प्रधानमंत्री जी उदघाटन करेंगी।

इसके साथ ही में प ुपालन विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। उसका भी इसमें जिक आया है कि इस विभाग ने कितना अच्छा काम किया है। आप जानते हैं कि ये बेजुबान प्राणी होते है। उनके इलाज के लिए पहले कोई वि ोश ध्यान नहीं दिया जाता था लेकिन हमारी मौजदूा सरकार ने 20 डिस्पैंसरियों की बजाये एक साल में 200 डिस्पैंसरियो बनायी है। आप देखिए एकदम दस गुना ज्यादा डिस्पैंसरियां प ुपालन विभाग ने खोल दी है। इस काम के लिए सरकार ने इस साल में 2 करोड रूपये का प्रोवीजन किया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस विभाग को कम से कम 5–6 करोड रूपया दिया जाए ताकि प ुपालन विभाग इस क्षेत्र में और ज्यादा काम कर सके और बेजुबान प्राणियों को अच्छी तरह इलाज हो सके। प ुओं के लिए हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मुहैयया होनी चाहिए। राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में इस बात का भी जिक आया है कि कृशि के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। अपोजि ान के भाईयों ने तो यह कहना ही है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन आप जानते हैं कि इतनी कुदरती आपदाओं के बावजूद भी हरियाणा में सबसे ज्यादा अनाज पैदा हुआ है। इस अभिभाशण में यह भी कहा गया है। कि अगले वर्श 71 लाख टन अनाज पैदा कर दिखायेगे। इसके साथ ही मेरी सरकार से गुजारि ा है कि बाढ नियंत्रण के बारे में ज्यादा तवज्जोह दी जाये। आपको पता है कि हरियाणा में हर साल बाढ आती है। यमुना नदी यूपी हिमाचल और दिल्ली के एरिया के अलावा हरियाणा से भी गुजरती है। यूपी वाले ज्यादा से

ज्यादा बांध और ठोकरें बनाकर अपने एरिए को बचा लेते हैं लेकिन उसका सारा असर हरियाणा पर पडता है। हरियाणा के एरिया में यमुना काट करती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हरियाणा में बाढ नियंत्रण के लिए ज्यादा से ज्यादा बांध या ठोकरें बनायी जानी चाहिए। ताकि हरियाणा खु ाहाल हो सके। आपने समय दिया आपका बहुत बहुत भाुक्रिया।

कामरेड भांकर लालः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी बदौलत हाउस के अन्दर जो इस वक्त गर्वनर साहब के अभिभाशण पर तकरीरें हो रही है उसमें भाग लेने के लिए खडा हुआ हूं। सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस अभिभाशण पर जाहिर कर रहे है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाशण का विरोध करने के लिए खडा हूं। मैं यह समझता हूं कि जो कुछ हरियाणा की मौजदूा सरकार ने उन्हें पढने के लिए दिया उस पर बिना कुछ टिप्पणी किये ही पढकर चले गये। गवर्नर साहब की यह अपनी बात नहीं है यह तो इस मौजूदा सरकार की बात है हरियाणा के अन्दर जो इस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही है वह सिरसा जिले के साथ भेदभाव कर रही है। सबसे पहली बात तो मैं चौधरी भजनलाल जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे सिरसा जिले के साथ जो भेदभाव बरता जा रहा है यह क्यों बरता जा रहा है। जो कुछ वहां पर हो रहा है वह सब को पता है। सन 1979–80 के अन्दर सीमेंट की एलोके ान 7000 टन होती थी। उस एलोके ान के कोटे को घटाकर 4100 टन कर दिया और

फिर उसे भी घटाकर 1300 टन कर दिया। मुख्यमंत्री जी जरा हिसार की फिगर्ज भी सीमेंट के कोटे के बारे में सुन ले। वहां पर पहले की अपेक्षा अब दुगुना सीमेंट का कोटा कर दिया है। सिरसा के अन्दर लोग सीमेंट की एक एक बोरी के लिए भटकते फिर रहे हैं। किसी भी गरीब आदमी को वहां सीमेंट नहीं मिल रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सिरसा जिले के साथ यह भेदभाव क्यों बरता जा रहा है। मैं कोई गलत बात नहीं कहता, सच्ची बात कहता हूं। अगर आपको कोई गलत बात लगे तो आप उसका जवाब दे देना। दूसरी बात मैं सिरसा म्युनिस्पिल कमेटी की बाबत कहना चाहता हूं । सिरसा मयुनिस्पिल कमेटी के लिये 40 लाख रूपया हरियाणा सरकार की तरफ से मंजूर किया गया था क्योंकि वहां पर बाहर की तरफ गन्दी बस्तियां है। हरिजनों सैनियों और गुजरों की गन्दी बस्तियों को सुधारने और सिरसा भाहर की पोजी ान बेहतर बनाने के लिये यह 40 लाख रूपया मजूंर किया गया था लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक इस कमेटी को एक भी पैसा नहीं दिया है। हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करने का क्या कारण है जबकि हरियाणा सरकार ने काफी म्युनिस्पिल कमेटीज को लाखों रूपया दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब मैं एक और भेदभाव की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सिरसा के बस अडडे का एलान मुख्यमंत्री जी की तरफसे पहले किया गया था आदमपुर और फतेहाबाद के बस अडडो का एलान बाद में किया गया था। वे दोंनो बस अडडें बन कर तैयार हो गये है लेकिन सिरसा जो कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है वहां पर बस

अडडा अभी तक भी नहीं बना है वहां पर अभी तक कोई बस अडडा नहीं है। न पे ाब करने के लिए कोई जगह है और न ही ठहरने या उठने बैठने के लिए कोई जगह है। अब जहां पर बस अडडा बना हुआ है वहां पपर गन्द पडा हुआ है। आपको पता ही है कि सिरसा जिला हैडक्वार्टर है लेकिन फिर भी बस अडडा नहीं बना हुआ है। हमारे साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

दूसरी बात मैं सिरसा जिले के कर्मचारियों के विशय में अर्ज करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय सब से ज्यादा कर्मचारी चाहे वे एडहाक के हैं और चाहे दूसरे है जो सर्विस से हटाये गये है। जहां तक मुझे मालूम है कि हरियाणा के सब महकमों में चाहे वे एसएसएस बोर्ड के थ्रू लिए गए है। चाहे मार्किटिंग बोर्ड के थ्रू लिए हैं और चाहे खादी बोर्ड के थ्रू लिए गए है। सब से कम कर्मचारी सिरसा जिले के लिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सब से ज्यादा कर्मचारी जिला हिसार के लिए गए है। मैं अगली बात यह कहना चाहता हूं कि विधानसभा में जो गर्वनर एड्रैस पढा गया है उसमें किराएदारों के बारे में कोई बात नहीं कही गई। देहात के जमींदार की जमीन पर सीलिंग लगाई गई है। चाहे उस पर रूपये में से चार आने ही अमल हुआ है लेकिन सीलिंग का कानून तो बना दिया गया है लेकिन भाहरी सम्पति पर यह सीलिंग क्यों नहीं लगाई गई। जो किराएदार सदियों से बैठे है उनसे भी मालिक मकान या दुकान खाली करवा लेता है अगर आप मर जाता है तो बेटे से दुकान खाली करवा ली जाती है। जो लोग दस साल से

बैठे है उनसे मालिक मकान दस साल के बाद भी मकान खाली करवा लेता है। ऐसे बहुत सारे केसिज नोटिस में आए है। मेरा कहना यह है कि जैसे जमीन का छह साला कानून है वैसी ही कानून जायदाद के बारे में भी होना चाहिए। अगर कोई आदमी छह साल तक लगातार किसी जमीन को का त करता है तो छह साल के बाद थोडी कीमत पर उस आदमी को जमीन मिल जाती है। काफी लोगों को इस तरह जमीन मिली है। मेरा निवेदन है कि जायदाद के बारे में भी कानून बनना चाहिए और किराए के बारे में भी एक्ट बनना चाहिए क्योंकि जो लोग काफी समय से दुकानों और मकानों में बैठे है। उस पर कहीं लोगों का अधिकार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार केवल उन लोगों के साथ होना चाहिए जिन के पास काफी जायदाद है। इस तरह का कानून बनाने से किराएदारों को फायदा पहुंचेगा। किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकता।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरप्लस लैंड का एक अलग कुलैक्टर होना चाहिए। आज हालत यह है कि चाहे कोई आदमी किसी भी दल से ताल्लुक रखता हो वह अपनी जमीन बचाने के लिए तरह तरह के ाडयंत्र रच रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सब से बडे जागीदार हिसार और सिरसा जिले में है। हालत यह है कि वहां पर किसी भी सरप्लस जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है। वहां पर भूमिहीन लोग जमीन के लिए तरसते फिर रहे हैं लेकिन जागीरदार पैसा देकर अपनी जमीन

को बचा रहे है। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और झुग्गी झोपडी वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए जागीरदार एक हो जाते है। वे अपनी तरफ से बहुत कोि ा ा कर रहे है कि हमारी चीज बंट न पाये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरप्लस लैंड का अलग से कुलैक्टर होना चाहिए जिसके पास केवल सरप्लस जमीन के ही कैसिज हो। डिप्टी स्पीकर साहब, जनता सरकार के वक्त जबरी चन्दा इक्टठा करने की बात खत्म हो गई थी। लेकिन अब यह चीज फिर काफी जोर से चल रही है। जनता सरकार के समय पांच साला बचत योजना में जबरन पैसा जमा कराने के काम खत्म हो गया था लेकिन अब सेल्ज टैक्स आफिसर्ज और फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमेंट के आफिसर्ज की मारफत अल्प बचत योजना के अन्दर दो सौ रूपए से लेकर दस हजार रूपए तक जमा करवाए जाते है। मैं यही कहना चाहता हूं कि छोटा दुकानदार जिसकी छोटी सी मनियारी की दुकान है अगर वह दो हजार रूपया इस योजना में जमा कर दे तो वह दुकान कैसे चलाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय, रिक ाा पुलरों का एक कानून आया है कि जो रिक ाा चलाएगा वही दो या चार रिक ाा रख सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज ट्रक तो एक आदमी दस और चालीस रख सकता है लेकिन रिक ाा चार भी नहीं रख सकता। इस किस्म की बातें आज हरियाणा के अन्दर चल रही है। यह बडी गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, जिन फसलों का नुकसान हुआ है उनके बारे में भी कहना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब ने उन फसलों को जिनकी ओलों से नुकसान हुआ है। मुआवजा देने का एलान किया है लेकिन चने की फसल जो भीत लहर से मारी गई है। उसके मुआवजें के बारे में कुछ नहीं कहा है। भीत लहर से चने की फसल को सब से ज्यादा नुकसार भिवानी हिसार और सिरसा जिलों में हुआ है। यहां पर 75 फीसदी चने की फसल को नुकसान हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके लिए भी स्पै ाल गिरदावरी कराई जाए और लोगों को मुआवजा दिया जाए। सिरसा जिले के स्पै ाल अबूबगढ और नानकपुर आदि गांवों को दो हजार एकड जमीन में चने की फसल को नुकसान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां की जमीन घग्गर नदी में बाढ के कारण डूब गई है जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहां पर वि ोशकर गेहूं चना और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां की स्पै ाल गिरदावरी कराई जाए और लोगों को मुआवजा दिया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, जींद के अन्दर कर्मचारियों के उपर पुलिस द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा है। यहां पर वर्कचार्ज्ड ऐम्पलाइज जलूस निकाल रहे हैं इस वक्त सारे हरियाणा में कलास थ्री और फोर के कर्मचारियों की जिन्दगी ठीक व्यतीत नहीं हो रही है। क्लास फोर के एम्पलाइज से बेगारी ली जाती है। इस किस्म के हालात आज हरियाणा के अन्दर चल रहे है। डिप्टी

स्पीकर साहब, मैं एक बात और यहां पर कहना चाहता हूं। आज सारे हरियाणा के अन्दर कर्मचारी वर्ग बडा ही दुखी है। इसी तरह किसान भी इस सरकार के हाथों से बुरी तरह पिस रहे है और उनसे भारी ब्याज पर कर्जों की वूसली ली जाती है। जो कि बडा भारी अन्याय है। इसलिये मेरी इस सरकार से दुरखास्त है कि जिस तरह से उद्योगपतियों और दूसरे बडे बडे पूंजीपतियों को बैंकों को भी दूसरी एजेन्सियों से कम ब्याज पर कर्जे दिलवाये जाते है। उसी प्रकार से किसानों को भी कर्जे कम ब्याज पर दिलवाये जायें। ऐसा करने से किसानों को राहत मिलेगी। आज किसान कर्जालू होता जा रहा है। किसानों को बुरी तरह से दबाया जा रहा है।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसान को आज उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। उस के गेंहू का सही भाव नहीं मिल रहा है और अमेरिका जैसे मुल्कों से गेंहू मंगवा कर यहां पर 220 रूपये फी क्विंटल के भाव दिया जा रहा है और दूसरी ओर यहां किसानों को उनकी अपनी खून पसीने की कमाई का उचित दाम नहीं मिल रहा है। केवल 130 और 140 रूपये क्विंटल के हिसाब से किसानों को गेंहू का भाव मिल रहा है। सरकार भी बीच मे कमि ान खोर है और गरीब किसानों का लहू चूस रही है।

अब मैं ला एण्ड आर्डर के मुताबिक भी कुछ कहना चाहता हूं डिप्टी स्पीकर साहब, सिरसा जिले में एक खारियां गांव

की 9 वर्श की लडकी के साथ बलात्कार किया गया। गांव के चौधरी ने बलात्कार किया है यह इनके ला एण्ड आर्डर की स्थिति है।

श्री उपाध्यक्षः कामरेड भांकर लाल जी, आप बैठिये, आपका समय हो चुका है अब श्री जगजीत सिंह पोहलू बोलेंगे।

कामरेड भांकर लालः * *

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए।

कामरेड भांकर लालः * *

श्री सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। कामरेड भांकर लाल जी ने जो कुछ यहां कहां है वह न तो अन–पार्लियामेन्टरी है और न ही इररैलेवैन्ट है लेकिन आपने यह आदे ा दे दिया कि यह रिकार्ड न किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी के केवल एक ही सदस्य बोले है और उन्हें बोलते हुए केवल 20 मिनट भी नहीं हुए है लेकिन आपने उन्हें खत्म करनै के लिए कह दिया है। (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः वे मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे थे, इसलिये रिकार्ड न करने के लिए कहा गया था। (ाोर व व्यवधान)

श्री सुशमा स्वराजः आपने उन्हें समय दिया था इसीलिए वे बोल रहे थे मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह था कि जो कुछ

उन्होंने यहां कहा है उसमें न तो कुछ अन पार्लियामेन्टरी था और न ही इररैलेवेन्ट। इसीलिये आप यह सब कुछ रिकार्ड करवाइए।

कामरेड भांकर लालः अच्छी जी धन्यवाद।

चौधरी जगजीत सिह पोहलूः डिप्टी स्पीकर साहब, जो गवर्नर एड्रैस हमारे सामने है इसे सरकार ने गर्वनर साहब से लिखकर पढवाया है यह एक रूटीन सा प्रोजीसर है लेकिन यह सारे का सारा एड्रैस बे–बुनियाद और खोखला है। इस सरकार ने जनता के लिए कोई खास काम नहीं किए है। और न ही कोई खास कदम उठाये है। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि हरियाणा की आज बहुत बुरी हालत है। चारों तरफ करप् ान ही करप् ान दिखाई देती है **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी हरस्वरूप बूरा पदासीन हुए)** चैयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि इस समय हरियाणा में चारों तरफ करप् ान ही करप् ान दिखाई देती है और जनता को इस सरकार से ठीक इन्साफ नहीं मिल रहा है। चेयरमैन साहब आज सारे हरियाणा के अन्दर घर–घर में इस बात का भाोर है और जैसा कि हमारे माननीय नेता मलिक मुख्यतार सिंह जी जिनका इस सरकार को बनाने में बडा महान हाथ था। उन्होंने भी कहा है कि यह एसएसएस बोर्ड नही है बल्कि यह तो सर्विस सैलिंग बोर्ड है जहां पर नौकरियों बिकती है। इस बात का हम सब को पता है और सभी वजीरों को पता है कि एसएसएस बोर्ड का चेयरमैन पैसे लेकर अप्वायंटमैन्टस करता है। वैकेन्सीज 60 होती है और भर्ती

350 कर लिये क्योंकि सभी से पैसे लिए गए थे। चैयरमेन साहब, मैं आगे आप को यह भी बताना चाहता हूं कि नायब तहसीलदारों, एएस आईज की सिलैक ान होने जा रही है। इनकी सिलैक ान पर एक एक लाख रूपये मांग जा रहे है। आप ही बताएं कि जो लडका इस तरह से रि वत देकर नौकरी लेगा वह इस प्रान्त का किस तरह से भला कर सकेगा?

इसलिये मैं आपके जरिये इस सरकार से कहूंगा कि इस बोर्ड को मुअतल कर दिया जाए। दूसरे जिन बच्चों से एसएसएस बोर्ड के चेयरमैन ने पैसे लिये हैं उनको उन के पैसे वापिस दिलवाए जाएं। चेयरमैन साहब इतना ही नहीं बल्कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से इन बातों की जांच भी करवाई जाए और जो दोशी पाया जाये उसे दंड दिया जाए। चेयरमैन साहब, एक लडका हरी सिंह घूल नाम का है वह बेचारा कांग्रेस (आई) का वर्कर है। छोटी मोटी दवाईयां बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसकी एसएसएस बोर्ड में इंटरव्यू हुई वह सिलैक्ट हो गया, मैंने उसे मुबारिकबाद दी। उसने आगे से कहा कि मुबारिकबाद किस बात की ऐसे ही सिलैक ान नहीं हुई बल्कि 11 हजार रूपया दिया है। (ाोर व व्यवधान)

श्री सभापतिः पोहलू साहब, आप किसी का नाम न लें, वैसे आप जो कहना चाहते हैं कहें (ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकार साहब, मैं कह रहा था कि उस लडके ने नौकरी लैने के लिए 11 हजार रूपये दिये है। बडे अफसोस की बात है कि हम 90 के 90 एमएलएज यहां पर बैठे है और हमारे हरियाणा के अन्दर इस तरह की बातें हो रही है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे है। यह हमारे लिए कितने भार्म की बात है। मैं तो यह कहूंगा कि इस बोर्ड को तोडकर नया बोर्ड बनाया जाए। चेयरमैन साहब, मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस (आई) में जितने वजीर और एमएलएज है वे सारे ही बेईमान है। बहुत से लोग इनमें समझदर और ईमानदार भी हैं लेकिन ईमानदार आदमी पर यहां पर कोई ठिकाना नहीं है। जैसे राव राम नारायण जी है वे बडे ही सज्जन पुरूश है। ईमानदार वजीर थे लेकिन उन्हें वजारत से हटा दिया गया। इनकी ईमानदारी के कारण ही इनको बाहर फैंक दिया गया, यह कितने भार्म की बात है। अतः मेरी इस सरकार से आपके द्वारा अर्ज है कि यह जो करप् ान दिन ब दिन बढती जा रही है इसकी तरफ ध्यान दिया जाए।

चेयरमैन साहब, अब मैं आपका और इस सदन का ध्यान एक ओर मसले की ओर दिलाना चाहता हूं। हरियाणा की जनता आज बडी जागरूक है पढी लिखी है वह इस सरकार के बहकावे में नहीं आएगी। चेयरमैन साहब, सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए इनके बंटवारे के लिए भााह कमि ान बैठा था ताकि पंजाब और हरियाणा की बांउडरीज का निर्णय किया जा

सके। भााह कमि ान ने अपनी रिपोर्ट में चण्डीगढ हरियाणा को दिया लेकिन आज तक चण्डीगढ हरियाणा को नहीं दिया और फाजिल्का व अबोहर का इलाका हरियाणा को दे दिया। अबोहर फाजिल्का भी अभी तक हरियाणा को नहीं मिला। इस बारे में चौधरी बंसीलाल जी ने बडा जोर लगाया। चेयरमैन साहब रिवाडी के अन्दर अहीरों के सैंकडों लडके चण्डीगढ के इ क पर ही मारे गये लेकिन सरकार अभी तक चण्डीगढ को नहीं ले सकी है। राव बीरेन्द्र सिंह जी की बजारत में मैं भी वजीर था। हम पर भी इस तरह का दवाब डाला गया था कि चण्डीगढ पंजाब की ही हमने यह भी मांग की कि लालडू डेरा बरसी, अबोहर फाजिल्का वगैरह का जो हिन्दी स्पीकिंग एरिया है वह भी हमें दिलवाया जाए लेकिन आज की सरकार ऐसा करने में अभी तक नाकामयाब रही है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार से दोबारा सैन्ट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में लिखवाया जाए और मैं खुद बैठकर लिखवाउंगा (हंसी एवं भाोर)

चेयरमैन साहब, मैं रावी ब्यास के पानी के बंटवारे में भी बताना चाहता हूं कि 1 नवम्बर 1966 को हरियाणा बना था। आज हरियाणा को बने हुए 16 साल हो गए हैं लेकिन आज तक यह पानी का बंटवारा नहीं करवा पाये है। चौधरी बंसी लाल जी के समय में फैसला हुआ था कि रावी ब्यास का 3.5 मिलियन एकड फीट पानी हरियाणा को और आधा पानी पंजाब की तरफ जाएगा। पंजाब को यह पानी बराबर जा रहा है लेकिन हम अपना हिस्सा

नहीं ले सके। अगर इतने सालों में इस सरकार से कुछ नहीं हो सका तो आज यह सरकार किस तरीके से अपने हिस्से का पानी ले लेगी। जो फैसला आज से 6 साल पहले हुआ था वहीं फैसला आज है। यह सरकार झूठ बोल रही है कि हम अपने हिस्से का पानी ले कर छोडेंगे। यह तो वही बात हुई कि जिस प्रकार से किसी गांव में मुरबबाबन्दी से पहले गांव के खेतों में कई घरों की जमीन पर जोहड होता था और उसमें सभी प ाुओं को पानी पिला सकते थे लेकिन जब मुरबबाबन्दी हो गई तो जिस खेत में जोहड था वह हिस्सा किसी तगडे जमींदार के पास चला गया। उस तगडे जमींदार ने कहा कि अब इस जोहड में गांव का कोई आदमी प ाुओं को पानी नहीं पिला सकता। लोगों ने प ाुओं को पानी पिलाना बन्द कर दिया परन्तु छह सालों के बाद सारा गांव इक्टठा हुआ कि यह तो गलत बात हुई। सबने फैसला किया कि सब लोग उसी जोहड में पानी पिलाएंगे तो फिर सभी लोगों ने पानी पिलाना भाुरू कर दिया। इसी प्रकार की रावि ब्यास के पानी की स्थिति है।

चेयरमैन साहब, मेरा कहना यह है कि हरियाणा को कोई पानी नहीं मिलेगा। यह तो केवल इलैक ान का ढोल पीट रहा है और लोगों को यूं ही गुमराह कर रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि अगर श्रीमति इंदिरा गांधी ईमानदारी से पानी देना चाहती है तो पंजाब और हरियाणा की सरकारों को मुअतल कर दें। मैं तो यह भी चाहता हूं कि अगर हरियाणा और पंजाब की

सरकारों को डिसमिस कर दें तो पानी के बंटवारे की बात बन जाती है।

चेयरमैन साहब, यहां पर बीस सूत्री प्रोग्राम का नाम लेकर बडा भाोर मचाया गया। मेरे भाई सुरेन्द्र सिंह ने भी बीस सूत्री कार्यक्रम पर बहुत जोर दिया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि यहां पर सूतली से कोई काम नहीं चलेगा। रस्सा लेना पडेगा। बीस सूत्री प्रोग्राम में यह कहते है कि लोगों को कर्जा दे दो। ऐसा करके तो ये लोगों को गुलाम बनाना चाहते है। अगर सरकार असली मायनों में लोगों का भला करना चाहती है तो उसे फौरन भाहरी जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। आज भाहरों में एक आदमी के पास सिनेमा भी है कारखाने भी हैं और बडी बडी कोठियां भी हैं लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं जैसे गांवों में हमारी जमीनों पर सीलिंग लगाई गई है उसी हिसाब से भाहरी जायदाद पर भी सीलिंग लगाई जाए और जो सरप्लस जायदाद हो उसे गरीबों में बांट दिया जाये। अगर आप सही मायनों में सो ालिस्टिक पैट्रन आफ सोसायटी चाहते हैं तो फालतू जमीन को गरीबों में बांट दिया जाए। There must be ceiling on property, whether it is rural or urban. ऐसा करने से चाहे देहाती जगह हो चाहे भाहरी हो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लूट खत्म हो जाएगी और मंहगाई भी खत्म हो जाएगी। इस सारी बीमारी का इलाज भाहरी जायदाद बांटने से हो जाएगा। यह सरकार कहीं पर मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बना रही है कहीं पर

हरिजन की भलाई का बोर्ड बना रही है और कहीं पर वीकर सैक ांज की तरक्की के लिए बोर्ड बना रही है। ऐसा करके यह सूखा ढोल पीट रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बीस सूत्री प्रोग्राम से कुछ नहीं बनेगा बल्कि इसके लिए बडे बडे कदम उठाने पडेंगे। इसके बाद गवर्नर साहब के एड्रैस में लिखा गया है कि कर्जा बांट दो। यह गरीबों के साथ खिलवाड हो रहा है। बडे बडे कारखानेदारों को तो करोडों रूपए की सबसिडी दी जाती है लेकिन जो गरीब आदमी हैं उनको थोडे से कर्जे के लिए जेलों में बन्द कर दिया जाता है। आपने सुना होगा कि हांसी तहसील में एक आदमी के नाम दो हजार रूपया कर्जा था उसको जेल में बन्द कर दिया गया। पता नहीं वह जेल में खुद मर गया या उसे मार दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि बडे बडे साहूकारों को कुछ नहीं कहा जाता। इस एड्रैस में सबसे पहली बात यह लिखनी चाहिए कि सारे सरकारी कर्जे माफ किए जायेंगे ओर जो प्राईवेट कर्जे है उनका सरकार लेन देन करवाए। रोहतक में तो प्राईवेट कर्जे कम हैं लेकिन करनाल, अम्बाला ओर जींद तथा कुरूक्षेत्र के इलाके के लोग तो प्राइवेट कर्जे के नीचे बिल्कुल दबे पडे है। इसके बाद में यह कहना चाहता हूं कि हस्पतालों में दवाईयां बिल्कुल नहीं मिलती। गरीब लोग बगैर दवाईयों के मर जाते है। मैं चाहता हूं कि सारे हरियाणा में फ्री इलाज होना चाहिए ताकि किसी गरीब आदमी को बाजार से दवाई न लानी पडे। पिछली 15 तारीख को मैं भिवानी गया था। वहां एक गरीब को दो अढाई साल का बच्चा मर गया। मैंने पूछा कि यह बच्चा कैसे मर गया

तो बताया गया कि यह सर्दी से मर गया है। यह हालत है आज गरीबों की। नागर साहब तो सबका मुफ्त इलाज करना चाहते हैं लेकिन ये दूसरे लोग उन्हें ऐसा नहीं करने देते।

इसके बाद मैं एजूके ान के बारे में कहना चाहता हूं। अगर सरकार एजूके ान को बढावा देना चाहती है तो सबसे पहले इसे एजूके ान को ने ानेलाइज करना चाहिए। सबको पढाई का बराबर मौका दिया जाए। गरीबों और अमीरों के लडकों के लिए एक जैसे स्कूल होने चाहिएं। (घंटी) चेयरमैन साहब मैं अपनी पार्टी का लीडर हूं लेकिन आपने अभी से घंटी बजा दी। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पक्के खाल बनाए जा रहे है उनमें बहुत हेराफेरी हो रही है। उनमें अच्छा मैटिरियल नहीं लगता हैं जिन अफसरों का इसमें कसूर है उनको सजा दी जाए। अगर खालों को अच्छी तरह से पक्का किया जाएगा और मैटिरियल ठीक लगेगा तो इससे पानी बढेगा जिससे सरकार को भी ज्यादा आमदनी होगी। इसके बाद मैं यह चाहता हू कि एक परिवार एक रोजगारा होना चाहिए और यह बात गवर्नर एड्रैस में लिखी जाए।

इसके बाद में ला एंड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूं। आज हरियाणा में ला एंड आर्डर की हालत चारों तरफ बहुत खराब है। आज जगह जगह डाके पड रहे हैं। चौधरी पटटी में 18 फरवरी को डाका पडा लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। यही नहीं मैंने खुद एक थानेदार और हैड कान्सटेबल के खिलाफ लिख कर दिया। उस बारे में पहले हुकम दे दिया गया कि हैड

कान्सटेबल को बदल दो लेकिन बाद में वह आर्डर कैंसिल कर दिया गया। मैंने पूछाय कि क्या बात हैं तो पता चला कि डीआईजी पचंकूला में मकान बना रहे हैं और स्लीपरों के लिए पांच हजार रूपए मांग रहे है। इसके बाद में यह चाहता हूं कि कैथल को जिला बनाया जाए।

श्री सभापतिः पोहलू साहब, अब आप बैठिए। अब कमला वर्मा जी बोलेंगी।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, ये सब घोशणा मंत्री है– (ाोर)

श्री सभापतिः पोहलू साहब, आप मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं जबकि मैं श्रीमति कमला वर्मा को बोलने के लिए कह चुका हूं। आप कृपया बैठिए वरना मैं आपको नेम कर दूंगा। आप हाउस को डैकोरम मेनटेन करें।

श्रीमति डा0 कमला वर्माः चेयरमैन साहब, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाशण का विरोध करने के लिए खडी हुई हूं। इसमें इस अनैतिक सरकार के जो निक्कमें काम है उनका वर्णन न करके केवल मात्र उन बातों को कहा गया है जो बिल्कुल गलत है। आप इस अभिभाशण के पृश्ठ 4 पर देखें जहां पर सतलुज यमुना नहर और रावी ब्यास के पानी का वर्णन किया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि किस खु ाी में पानीपत रैस्ट हाउस और हरियाणा भवन दिल्ली में बिजली लगाई गई? जब पहले सैन्ट्रल

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया तो उस समय कुल पानी 15.5 एमएएफ था अब इस समय निर्णय लेते समय पानी 17.7 एमएएफ है लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा को वही पुराना 3.5 एमएएफ हिस्सा मिला और पंजाब तथा राजस्थान को ज्यादा हिस्सा मिला। फिर सात साल तक राजस्थान ने कोई नहर नहीं बनानी और उसके हिस्से का पानी भी सात साल तक पंजाब को दे दिया। अधिक पानी होने से कुछ अधिक भाग मिलना चाहिए था। उस हिस्से को हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं ले सके। ऐसा करके इन्होंने लोगों की आंखों के आगे धूल झौंकी है। इन्होंने मिठाई बांटी और कहा खु ा हो जाओ हरियाणा को पानी दे दिया है। सभापति महोदय हरियाणा की जनता को आज भी यह भाक है कि पंजाब का किसान हरियाणा के किसान को नहर खोदने के लिए अपनी जमीन में कसी नहीं लगाने देगा। हरियाणा में पानी लाने के लिए जो नहर खोदनी है उसके लिए पंजाब के लोग कमर कसकर खडे हो गए है। कि हम नहर नहीं बनाने देंगे। इसलिए कई बार यह भाक होता है कि जिन उग्रवादी तत्वों ने पंजाब प्रांत में हलचल मचा रखी है उनको भाांत और काम को प्रारम्भ करने के लिए केंद्र को यह निर्णय लेना पडा। सभापति महोदय, इस सरकार ने हरियाणा की जनता के हितों को छीना है क्योंकि हरियाणा में पानी लाने के लिए पंजाब के एरिया में जो नहर खोदी जाएगी पहले उसको 7500 क्यूसिक पानी की कैपेसिटी थी लेकिन अब वह वर्तमान निर्णय से नहर की चौडाई की खुदाई कम होने से 6500 क्यूसिक हो जाएगी जिसके कारण हरियाणा के किसानों को और

भी कम पानी मिलेगा। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं भाखडा रोपड हरिके पतन डैम के बारे में कहना चाहती हूं। उसके बारे में अभी तक यह नहीं पता कि उसका नियंत्रण किसके हाथ में होगा। केंद्र के कहने के बाद भी पंजाब के मुख्यमंत्री का अखबारों में बयान आया कि यह डैम हम अपने ही नियंत्रण में रखेगें। इसका मतलब यह हुआ कि जब पंजाब सरकार की इच्छा होगी उस समय हरियाणा को बिजली मिल जाएगी और यदि इच्छा नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। सभापति महोदय अब मैं पक्के खालों के बारे में कहना चाहती हूं। यह सरकार कहती है कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर या अन्य साधनों से हरियाणा के अन्दर पक्के खाल बनाए जा रहे है पानी की बचत होगी, किसान को लाभ होगा परन्तु पक्के खालों का खर्चा किसानों को देना पडेगा। सभापति महोदय, इस सरकार ने खाद बहुत मंहगी कर दी और बीज भी महंगे कर दिया। इसके अलावा किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती और ट्रैक्टरों की कीमतें बढने के कारण सारे किसान कर्जदार हुए बैठै है। कृशि के हर साधन महंगें है इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त सरकार का पक्के खालों को खर्चा किसानों से मांगना उन्हें तंग करने वाली बात है। गवर्नर एड्रैस में यह सरकार कहमी है कि हम किसानों के हितैशी है। सभापति महोदय इस सरकार के कार्यकलापों से यह सिद्ध होता है कि यह सरकार किसानों के विरूद्ध और उनको हर प्रकाार से दबाकर रखना चाहती है। कल एक काल अटैं ान मो ान का जबाव देते हुए बिजली मंत्री ने बहुत बडी बडी डींगे मारीं और कहा कि पानीपत में एक थर्मल

प्लांट चल रहा है और यमुनानगर में एक हाईडल प्रोजैक्ट बनाया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं पिछले तीन महीनों में अपने हल्के के हर गांव में जाकर आई हूं। उस समय मुझे हर किसान ने कहा कि हर दूसरे या तीसरे दिन हम को दो या तीन घंटे रात्रि में बिजली मिलती है। हमें रात के समय रोटी अंधेरे में खानी पडती है। नगर में भी घरेलू कामकाज के लिए बिजली प्रांतः 7 या 8 बजे चली जाती है और रात के समय 7 बजे के बाद बिजली आती है। सभापति महोदय, यमुना नगर इंडस्ट्रीयल कम्पलैक्स है। इस सरकार ने वहां पर बिजली की सप्लाई पर 40 परसैंट कट लगाकर हजारों मजदूर बेकार कर दिए है। आज ही प्र नकाल के दौरान खाद्य एवं पूर्ति मंत्री के एक प्र न के उत्तर में सुना था कि आम आदमी को सीमेंट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सीमेंट फैक्टरी पर बिजली का कट लगने के कारण इंडस्ट्रीज की तरफ से सीमेंट नहीं मिल सका जिस कारण 6 मास से आम आदमी को सीमेंट नही मिल रहा। सभापति महोदय, बिजली पर कट लगाने के कारण फरीदाबाद, सोनीपत और यमुनानगर में लगभग 25 हजार मजदूर बेकार हुए। जब रात्रि की सर्दी में ठिठुरता हुआ दूर–दूर गांव से आने वाला मजदूर कारखाने के अंदर काम करने के लिए जाता है तो कारखाने का मालिक उसको कहता हैं कि बिजली नहीं है इसलिए आप वापिस चले जाओ, तो उसके दिल पर क्या बितती है। अध्यक्ष महोदय, बिजली पर निरन्तर कट लगा कर यह सरकार हरियाणा के गरीब मजदूरों के साथ खिलवाड कर रही है। पिछले सै ान में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था और अखबारों में भी

इनका ब्यान आया था कि बहुत से आदमी विदे ाों से आकर हरियाणा के अन्दर बडे बडे उद्योग लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि हरियाणा के अन्दर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पहले की काफी लगी हुई है वे सारी बिजली के अभाव के कारण सिसक रही है लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कहते है कि लोग विदे ाों से आकर हरियाणा में बडे बडे उद्योग लगाएंगे। इनकी यह बात ठीक है कि मुख्यमंत्री के नाते विदे ों की सैर करने का यह मौका नहीं खोना चाहिए था। वे विदे ा चले गए और सारे वि व की सैर कर ली पर यह कहना कि ये विदे ाों में उद्योगपतियों को हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए नियंत्रण देने के लिए गए थे, भम्र हो ही है। मैं इनसे यह जानना चाहती हूं कि हरियाणा के अन्दर कौन से नए उद्योग लगेंगे जबकि यहां पर बिजली का अभाव पहले ही है। अध्यक्ष महोदय, पहले हरियाणा में जितने उद्योग लगें है उनको बिजली की कमी तो पूरी कर लें। फिर मुख्यमंत्री जी नए नए उद्योगपतियों को यहां पर उद्योग लगाने के लिए निमन्त्रण देकर हरियाणा की जनता के साथ बहुत धोखा कर रहे है। अध्यक्ष महोदय, मैं मार्किटिंग बोर्ड के बारे में ये कहना चाहती हूं मुख्यमंत्री हरियाणा के अन्दर मंडियों का ि ालान्यास कर रहे है। सरकार की यह बात ठीक है कि हरियाणा के विकास के लिए अनाज मंडियां बनानी चाहती हैं अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जब यह सरकार किसनों की लहलहाती हुई खेती की जमीन एक्वायर करती है जिनकी धरती

सोना उगलती है कम से कम उनको, उनकी जमीन की कीमत तो पूरी दे लेकिन यह सरकार किसानों को उनकी जमीन की कीमत पूरी नहीं देती। किसानों को कोर्ट में जाना पडता है और कोर्ट जमीन की कीमत बढा देती है। फिर सरकार का सप्लीमेंटरी बजट आता है और उसके अन्दर कोर्ट द्वारा बढाए हुए पैसे की मांग की जाती है। इसके लिए सरकार को पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि जो दो या तीन एकड जमीन वाले छोटे किसान हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण कर ली, अब उनके पास बच्चों के लिए मकान कौडियों के भाव देती है। अध्यक्ष महोदय, इसका उदाहरण यमुनानगर के पास एक गांव गोंदपुरा है। वहां पर गरीब किसानों की जमीन इस सरकार ने मिटटी के भाव एक्वायर की है। वहां पर गरीब किसानों की जमीन इस सरकार ने मिटटी के भाव एक्वायर की है। मैं इस सरकार से कहना चाहती हूं कि वह ऐसी जमीन एक्वायर कर ले जो सरप्लस जमीन पडी हुई हो या पंचायत की फालतू जमीन पडी हुई हो, थोडी जमीन वालों को बेघर न करे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ि ाक्षा के बारे में कहना चाहती हूं। ि ाक्षा हमारे राश्ट्र का आधार है। हमारे बच्चे पढ लिखकर इस दे ा के विकास में सहायक होंगे लेकिन मुझे बडे दुख के साथ कहना पडता हैं कि कुछ राजनीतिक कारणों से हरियाणा ि ाक्षा बोर्ड चंडीगढ से भिवानी ि ाफट कर दिया गया है। भिवानी में आज ि ाक्षा बोर्ड पांच हिस्सों के अन्दर अलग–अलग भवनों में बंटा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं ि ाक्षा बोर्ड की

कार्यकु ालता और कार्यक्षमता के बारे में एक बात कहना चाहती हूं। कल मेरे नैतिक ि ाक्षा परप बोलने के समय ि ाक्षा मंत्री जी नहीं माने पर जो कुछ मार्च 1981 में और 1982 में समाचार पत्रों में बोर्ड की अकु ालता के बारे में छपा, उसके कुछ पृश्ठ मेरे पास पडे हैं। उस ब्यान में कहा गया है कि 1981 में हरियाणा ि ाक्षा बोर्ड के पेपर लीक किए गए है। अध्यक्ष महोदय लोगों को 1982 के पेपर भी लीक होने का भाक है। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि बच्चों के एग्जाम सिर पर आ जाते हैं लेकिन किताबें नहीं छपती है अध्यक्ष महोदय बच्चे 1982 की परीक्षा दे रहे है लेकिन हिन्दी व्याकरण और निबंध की पुस्तकें बच्चों को अभी तक नहीं मिली थी। इसी तरह से 1981 में हुआ था अंत तक पुस्तकें नही मिली थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या ि ाक्षा बोर्ड को भिवानी ि ाफ्ट करने के बाद उसकी कार्यकु ालता बढी है? फरवरी 1982 की हिन्दी व्याकरण की किताब में एक निबंध छपा है कि श्री मोरार जी देसाई भारत के प्रधानमंत्री हैं जब सरकार और बोर्ड के अधिकारियों ने वह पुस्तक देखी तो उस किताब को प्रका ान के लिए दोबारा भेज दिया गया चूंकि प्रधानमंत्री तो श्रीमति इंदिरा गांधी है। मैं इस सरकार से कहना चाहती हूं कि आप गरीब जनता के पैसे के साथ खिलवाड क्यों कर रहे हो। अतः प्रका ान में कितना धन नश्ट हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यापक को ि ाक्षा की रीढ की हडडी माना जाता है पर यह सरकार उनकी आव यकतों और भावनाओं का ध्यान नहीं करती। गवर्नमेंट स्कूल

के अध्यापकों के ग्रेड 1–4–1979 को रिवाइज हो गए थे लेकिन प्राईवेट स्कूलों के अध्यापकों के ग्रेड 1–4–1981से रिवाईज किए गए उनको दो वर्श का घाटा क्यों? अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है जब हमारी जनता पार्टी की सरकार थी उस समय हने प्राइवेट कालेजों को 95 परसैंट ग्रांट दी थी मैडिकल फैसिलिटी दी थी और हाउस रैट दिया था। इस प्रकार की और भी सुविधाएं दी थी। लेकिन यह सरकार आज प्राइवेट स्कूल अध्यापकों को ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, राश्ट्र का निर्माण करने वाले अध्यापक असंतुश्ट रहेंगे तो वे राश्ट्र के निर्माण में सहायक नहीं बन सकेंगे। इसलिए मैं ि ाक्षा मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि ि ाक्षा के अन्दर इस प्रकार विद्यालय व महाविद्यालय के अध्यापकों के लिए भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। इसके साथ साथ में 10+2 स्कीम के बारे में कहना चाहती हूं। पिछले वर्श उसके लिए डीपीआई ने एक करोड 10 लाख रूपए की स्कीम सरकान के पास भेजी थी लेकिन वह योजना हरियाणा के अन्दर राजनीतिक कारणों से रोक दी गई है। सारे भारत में 17 प्रान्तों में वह स्कीम चल रही है। हरियाणा में वह योजना लागू न होने के कारण हरियाणा के बच्चे आल इंडिया कम्पीटि ान में स्थान नहीं ले पाते। अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय एनटीआरसी के एग्जाम होते हैं पिछले 10 वर्शो से उसमें हरियाणा के केवल 8 या 9 बच्चे चुन कर आ सके है। यह मानना पडेगा, हरियाणा के अन्दर ि ाक्षा का स्तर इतना गिर गया हैं कि

आज हरियाणा का बच्चा आल इंडिया लेवल के कम्पीटि ान में नहीं आ पाता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहती हूं। सारे हरियाणा के अन्दर कुरूक्षेत्र में आयुर्वेदिक ि ाक्षा का एक ही कालेज है लेकिन उस के अन्दर कई मासों से प्रिंसिपल नहीं है और उस कालेज के अन्दर जो पढाने वाले अध्यापक है वे अपने विशय में पूरी तरह से पारंगत नहीं है। इसके अलावा वहां पर प्रैक्टिकल के लिए अस्पताल नहीं है और न ही प्रैक्टिकल सीखने के लिए कोई इक्विपमैंट है। परीक्षा देने के बाद भी हम कैसे आ ाा करें कि वह अच्छे आयुर्वेदिक डाक्टर बनेंगे जब उन्हें साधन ही नहीं है।

स्पीकर साहब, इसके साथ साथ में मैडिकल कालेज, रोहतक का भी जिक करना चाहूंगी। रोहतक मैडिकल कालेज के अन्दर भी डिस्कि ानरी कोटे में भर्ती की जा रही है। यह ठीक है मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री स्वैच्छिक कोटे से अपने परिचितों व सम्बन्धियों को प्लाट दे सकते है। कृशि की भूमि भी बांट सकते है। लेकिन यह उचित नहीं कि मैडिकल कालेज के अन्दर योग्य बच्चों की उपेक्षा करके डिस्कि ानरी कोटे से विद्यार्थियों को लिया जाए। वहां पर जिसको भी लिया जाये नियमों के अनुसार मैरिट के आधार पर लेना चाहिये। यदि मैरिट के आधार पर नहीं लिए जाएंगे तो वे कैसे डाक्टर योग्य बनेंगे? उनसें हमारे राश्ट्र की हानि है। 8 सीटें मुख्यमंत्री ने कोटे से दी, कुछ बच्चे सुप्रीम

कोर्ट में गये और योग्यता के आधार पर सरकार को 11 बच्चे अन्य मेडिकल कोलजों में लेने पडें। (ोम भोम की आवाजें)

ऐसा करने से हमारी अपनी ही बदनामी है। हमारे हरियाणा का नाम बदनाम हो रहा है। वैसे भी रोहतक मैडिकल कालेज में व्यवस्था बहुत है। राश्ट्रीय भावना से ओतप्रोत विद्यार्थी रक्तदान करता है लेकिन मेडिकल कालेज में आज किसी निर्धन का खून बिना मूल्य उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज वहां पर एक एक बोलत दो दो सौ, तीन तीन सौ रूपये में मिल रही है। इससे घटिया और क्या बात हो सकती हैं? आज कहीं पर कोई काम ठीक व्यवस्थित नहीं हैं। इससे इस सरकार को अक्षमता और अयोग्यता साफ जाहिर होती है। स्पीकर साहब, यमुना नगर के अन्दर 3 साल पहले एक हाउसिंग कालोनी बनाने के लिए घोशणा की गई थी लेकिन आज तक वहां पर हाउसिंग कालोनी बनानी तो दूर रही उसके लिए जमीन तक एक्वायर नहीं की गई है। चार लाख रूपया लोगों का जमा है। लोग निरा ा हैं। इसलिए इस संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस ओर ध्यान दें। आज ये डींग मार रहे हैं कि हमने इतने मकान बना दिए हैं। यमुनानगर में क्या वहां विरोधी पक्ष का विधायक होने से जनता के काम रोक दिये जायेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है 30 साल से क्यों कुछ नहीं हुआ है। इस काम को आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। स्पीकर साहब आज चारों तरफ भ्रश्टाचार फैला हुआ है। (ाोर व विध्न)

श्री अध्यक्षः आप अपनी स्पीच समाप्त करें।

श्रीमति डा0 कमला वर्माः स्पीकर साहब, ये सीमेंट की बात कर रहे हैं आज न किसी को सीमेंट मिल रहा है और न ही किसी को मिटटी का तेल आदि मिल रहा है। (ाोर) गांव में डिपो वाला मिटटी का तेल लाता नहीं आज गांव के अन्दर रहने वाले हरिजन व मजदूर को भाहर में जाकर एक एक तेल की बोतल के लिए 4 रूपए 50 पैसे देकर ब्लैक में खरीदना पडता है।

सरकार कहती है कि हमने हरिजन कालोनी के अन्दर बिजली पहुंचा दी है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि यह सिर्फ इनके कागजों तक ही सीमित है। कहीं पर भी हरिजन बस्ती के अन्दर गलियों में बिजली नहीं पहुंचाई। गांव में हरिजन बस्ती के बाहर फिरनी पर चार बल्व लगा दिए है। इन चार बल्वों को लगाकर यह कह रहे हैं कि हमने हरिजनों की बस्ती के अन्दर बिजली पहुंचा दी है। जो चार बल्व लगाये हैं वे भी ठीक नहीं लगे हैं। इन खम्भों पर बल्व लगाकर उपर रोड नहीं लगाए। जब कभी आंधी या बारि ा आ जाती है तो वे टूट कर गिर जाते हैं या फयूज हो जाते है। एक बार लगाने के बाद दुबारा बल्व बदलने का नाम नहीं लिया जाता। हरिजन बस्तियों के अन्दर आज भी अंधेरा हैं। ये सरासर गलत बात कह रहे हैं। कोई बल्ब टूट जाता है तो वह वहीं के लोग ही लगाते हैं। यदि मुख्यमंत्री चाहें तो ऐसे मैं बीसियों गांव दिखा सकती हूं। आजकल जो पंचायत की भाामलात जमीन ठेके पर दी जा रही है वह ठीक प्रकार से नहीं

बांटा जा रही। इसके लिए कुछ एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूं। हमारे राजस्व मंत्री के एक रि तेदार है या मित्र हैं इन्होंने दौलतपुर के अन्दर 20 किल्ले जमीन बहुत कम रूपयों में ठेके पर ले ली है। उसी सज्जन ने मछली पालन का कर्जा भी सरकार से लिया पर मछली पालन का काम नीह किया, क्या यह धोखा नहीं है। वह एक अच्छा वकील है। अच्छे खाते–पीते घर का है। किसी गरीब हरिजन को भूमि दी जाती तो दुख नहीं था। इसी प्रकार से कैत गांव में मंत्री के एक रि तेदार को 16 किल्ले जमीन दे दी गई। छछरौली के अन्दर भी 8 किल्ले जमीन अपने ही व्यक्ति हो दे दी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस सारे मामले की जांच करनी चाहिए। क्योंकि यह जमीन गरीब लोगों में बांटी जाती तो बात समझ में आती लेकिन इस पर एक मंत्री के रि तेदारों द्वारा और मित्रों द्वारा ही कब्जा कर लेना उचित नहीं है। प्रत्यक्ष भ्रश्टाचार है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय मैं दो–चार मिनट और लेना चाहूंगी। मुझे एक बात ला एण्ड आर्डर के बारे में कहनी है। आज से 2–3 महीने पहले यमुनानगर के बस डिपो से 18 हजार रूपये की चोरी हुई थी लेकिन आज तक यह पता नहीं चल सका कि अपराधी कौन है? इसी प्रकार से अभी करीब दो मास पहले फिर यमुनानगर बस डिपो में ही एक और चोरी सवा लाख रूपये की हुई है। उसका भी आज तक पता नहीं चल सका। इसलिये मैं जानना चाहती हूं कि पुलिस क्या कर रही है? अपराधी आज तक क्यों नहीं पकडा गया। बैंकों में डकैती, बसों में लूटपाट, पुलिस की अकु ालता ही दिखाती है।

श्री अध्यक्षः आपका समय हो गया है इसीलिये समाप्त करें।

श्रीमति डा0 कमला वर्माः स्पीकर साहब, सिर्फ दो मिनट और बोलना चाहती हूं। अम्बाला जिले में बराडा में एक लज्जाजनक घटना घटी है। एक बहन डाक्टर के पस इलाज कराने के लिए जाती है। वह डाक्टर उससे बलात्कार करता है। भेद न खुल जाए इस भय से उसको कमरे में बंद करके मार दिया जाता है। इससे बडा अन्याय क्या हो सकता है। (ोम भोम की आवाजें) क्या यही कानून व्यवस्था है? वह डाक्टर क्वालीफाईड नहीं था। वह सातवीं पास है और किसी और का झूठा प्रमाण पत्र लेकर प्रैक्टिस करता रहा। स्पीकर साहब, अराजकता की कोई हद नहीं है। होली का दिन था। उस दिन सभी भाई बहनें मिलकर होली आपस में खेलते है लेकिन महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के अन्दर कुछ गुन्डे दाखिल हो जाते हैं वे लडकियों के साथ छेडखानी करते हैं और प्रिसिंपल कोई एक ान नहीं लेता। इस प्रकार की कई और मिसालें है। अम्बाला में बलविन्द्र कौर कांड हरियाणा पर कलंक है।

श्री अध्यक्षः आपने बहुत समय ले लिया है। अब आप खत्म करें।

श्रीमति डा0 कमला वर्माः स्पीकर साहब, यमुनानगर के अन्दर जो हाईडल प्रोजैक्ट बन रहा है उसमें काफी घोटाला हो

रहा है। इसलिये मैं आपके द्वार सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए। (घंटी)

श्री अध्यक्षः आपने बहुत समय ले लिया है। इसलिये आप खत्म करें।

श्रीमति डा0 कमला वर्माः स्पीकर साहब, बातें तो बहुत हैं हरियाणा को आज की सरकार ने अनैतिकता और भ्रश्टाचार से लिप्त कर दिया है लेकिन आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे है। इसलिए राज्पाल महोदय ने जो अभिभाशण दिया है उसका विरोध करते हुए अपना स्थान लेती हूं। धन्यवाद।

राव राम नारायणः अध्यक्ष महोदय, जो अभिभाशण राज्यपाल महोदय ने इस हाउस में दिया है उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। हमारी सरकार ने पिछडी जातियों और गरीब मजदूरों के लिए बहुत काम किए है। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में उन्नति की है। जितना भी काम हमारी सरकार ने किया है वह बडा सराहनीय है लेकिन हरियाणा के अन्दर कुछ ऐसे भी हिस्से रहे है जो बहुत समय से पिछडे रहे हैं। हमारे हरियाणा का एक हिस्सा जिले हम साउथ हरियाणा कहते हैं वह किसी समय में झज्जर नवाब की स्टेट होती थी। 1857 में वहां पर जंगे–आजादी हुई थी। उस समय वहां के लोगों ने डटकर मुकाबला किया था। उस गदर से हमारी हार हो गई थी। बाद में उस इलाके को अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से कुचला।

श्री अध्यक्षः राव साहब आप बैठ जाएं। अब वित्तमंत्री जी बजट पे ा करेंगे। (ोर)

औचित्य प्र न

इलैक ान ईयर में पूरा बजट पे ा करने सम्बन्धी

12.00 बजे

Mr. Speaker: Hon'ble Member, now the Finance Minister will present the Budget for the year 1982-83.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, on a point of order. I want to submit something.

Mr. Speaker: No point of order. It is time for the Finance Minister to present the Budget.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, it is a very serious matter. (Interruptions).

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will present the Budget for the year 1982-83.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, आप मेरा प्वायंट आफ आर्डर सुन लें। ये पूरा बजट पे ा नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्षः आपको चाहिए था कि आप अपना प्वायंट आफ आर्डर पहले रेज करते। बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी ने बजट पे ा करने के लिए टाईम मुकर्रर कर रखा है। अगर आपको इस

बारे में कोई औबजैक ान था तो वह आपको पहले रोज करना चाहिए था। अब आप प्वायंट आफ आर्डर नहीं कर सकते क्योंकि फाइनैंस मिनिस्टर ने बजट पे ा करना है।

चौधरी राम लाल वधवा: सर, यह इलैक ान ईयर है। इसमें पूरा बजट पे ा नहीं हो सकता। आप कृपया मेरा प्वायंट आफ आर्डर सुन लें। (ाोर)

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी से बोलें। I will not allow dilatory tactics.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, Rule 188 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly says-

"188. Tha Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and expenditure of the Government of the State in respect of every Financial year (hereinafter referred to as "the Budget") shall be presented to the Assembly on such day as the Governer may appoint".

Again kindly see page 595 of the book written by Kaul and Shakdher. It is written therein-

"In an election year Budgets may be presented twice-first to secure a Vote on Account for a few months and later in full."

Further I would request you to see to Note 5, wherein it is written-

"In 1957, 1962, 1967, Railway and General Budgets were presented twice. In 1971, the Budgets were presented once in the First Session of Fifth Lok Sabha on March 23, and 24, 1971, respectively. In 1977 also, the Budgets were presented once in the First Session on March 28, 1977 and again in the Second Session of the Sixth Lok Sabha on June 11 and 17, 1977, respectively."

स्पीकर साहब, हरियाणा असैम्बली के रूल्ज आफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 199 को भी आप देख ले। मैं इसे पढना नहीं चाहता क्योंकि समय लग जाएगा। इसमें भी लिखा है कि ये केवल वोट आन अकांउट पे ा कर सकते है।

Finance Minster (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, it is not at all obligatory but it is optional with the State Government whether to present a vote on account or budget for the full year. The State Governments which are confident of returning again, present Budget for the full year and accordingly I am doing it.

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह स्टेट का मामला है। हमे ाा ऐसा होता रहा है। इनको तो खु ाी होनी चाहिए। (ाोर)

चौधरी उदय सिंह दलालः यह इल्लीगल है। यह हाई कोर्ट में चैंलेज होगा। कर्मचारियों को तनख्वाह मिलनी बंद हो जाएगी। (ाोर)

Mr. Speaker: Is there any precedent?

Chaudhri Khurshid Ahmed: Yes, Sir. (Interruptions and Noise)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Sir, also see pages 608 & 609 of Kaul and Shakdher.

Mr. Speaker: No please. Please resume your seat. I have examined the point of order raised by Shri Ram Lal Wadhwa. There it nothing in our Rules which prevants the Finance Minister or the Government from presenting the Budget for the whole of the year. Whatever has been quoted from Kaul and Shakdher rates to Parliament. So far as the Vidhan Sabha is concerned, there are precedents in1967, 1972 and 1977 when elections were due but the Government presented Budgets for the whole year. On the basis of these previous practices the Finance Minister is entirely within his rights to present the Budget for the whole year. (Interruptions and noise).

Shirmati Sushma Swaraj: On a point of order, Sir.....

Mr. Speaker: No further point of order please. I over rule all points of order.

वाक आउट

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Then I walk out as a protest, (Chaudhri Ram Lal Wadhwa then staged a walk-out)

वर्श 1982–83 का बजट पे ा करना

श्री अध्यक्षः अब वित्तमंत्री महोदय वर्श 1982–83 का बजट पे ा करेंगे।

वित्तमंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामय सदन को बजट अनुमान 1982–83 प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। राश्ट्र एंव राज्य दोनों की ही अर्थ व्यवस्था में समाप्त होने वालने वर्श के दौरान हुई सराहनीय उन्नति के उपरान्त वर्श 1982–83 मे और भी अधिक उपलब्धियां होने की पूर्ण आ ाा है। माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हमें दिये गये नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सिद्धांतों के सहारे एवं ''श्रम एवं जयते'' के नारे को अपनाते हुए नये वर्श मे हम अव य ही महान सफलतायें प्राप्त कर सकेंगे। ओलावृश्टि एवं सूखे आदि की आपदायें लगातार 1977 से हमारा पीछा कर रही है एवं इनके दौरान राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों को तुरंत एव बार बार सहायता दी गयी जिसके अभाव मे पीड़ित व्यक्तियों की अवस्था और भी दयनीय हो जाती एवं हमारी सारी उपलब्धियां भून्य हो जाती। इसकी करूणामय यादगारों को तेजी से पीछे छोड़ते हुए हम अब भविश्य का सामना नई आ ााओं एवं नये वि वास के साथ करने जा रहे है।

वर्श 1975 मे भी प्रधान मंत्री श्रमती इंदिरा गांधी ने मौलिक 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा राश्ट्र को उन्नति की और ले जाने के लिये और भारतीय समाज के कमजोर तथा गरीब लोगों के भाग्य को बेहतर बनाने के लिए आहवान किया था। तब से प्राप्त

किये जा चुके अनुक लक्ष्यों, बदलती हुई आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों और अर्थव्यवस्था के सामने नई नई चुनौतियों के कारण यह जरूरी हो गया था कि 1975 के 20 सूत्री कार्यक्रम को नया रूप तथा नया ढांचा दिया जाये। अतः अब राश्ट्र को एक नया कार्यक्रम दिया गया है ताकि अर्थव्यवस्था मे और प्रगति हो सके तथा दलित लोगों का उत्थान हो सके। हरियाणा सरकार ने इस नये कार्यक्रम को काफी जो ा के साथ कार्यरूप देने का संकल्प लिया है और यह इस सच्चाई को मानती है कि मेहनत का स्थान कोई दूसरी चीज नही ले सकती। 'श्री एव जयते' भाब्दों मे इसी सच्चाई पर जोर दिया गया है। वर्श 1982 ''उत्पादकता वर्श'' है और सरकार का यह संकल्प है कि वह सभी उद्यमों मे लगातार अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त करें ताकि राज्य आगे बढ़ सके।

आर्थिक स्थिति

राज्य की आर्थिक स्थिति मे वर्श 1981–82 के दौरान स्पश्अ रूप से सुधार हुआ है। वर्श के दौरान मुद्रास्फीति (इन्फमे ान) मे साफ तौर से कमी आई है। जैसा कि थोक मूल्य सूचक अंकों से पता चलता है, दे ा मे मुद्रास्फीति की वार्शिक दर 16 जनवरी, 1982 को घट कर 5.4 प्रति ात हो गई जबकि यह 17 जनवरी, 1981 को 16.2 प्रति ात थी। यह मंदी धीरे धीरे राश्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों मे भी दिखाई दे रही है जो कि अगस्त, 1981 के 14.4 प्रति ात के मुकाबले मे दिसम्बर 1981 मे घट कर 12.7 प्रति ात हो गये थे। 1960 को आधार मानते हुये अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों मे मार्च, 1981 और अक्तूबर 1981 के बीच 9.5 प्रति ात की वृद्धि हुई जबकि ये अंक 420 से बढ़ कर 460 हो गये थे। 1972–73 को आधार मानते हुये हरियाणा राज्य श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंकों मे इस अवधि के दौरान केवल 8 प्रति ात वृद्धि हुई है।

1980–81 के दौरान हरियाणा मे प्राकृतिक आपदाओं से अर्थ व्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद राज्य मे आर्थिक विकास की गति बहुत उत्साहजनक रही है। राज्य सरकारने मुद्रास्फीति (इन्फले ान) रोकने के लिये ऐसी नीति अपनाई जो कि अपने कार्य क्षेत्र मे सप्लाई और मांग की संतोशजनक व्यवस्था पर जोर देती थी। उपज और खास तौर से कृशि क्षेत्र की उपज बढ़ाने के

लिये भी कदम उठाये गये। सार्वजनिक वितरण पद्धति को मजबूत बनाया गया जिसने राज्य मे जरूरी वस्तुओं मुहैया कराने मे एक महत्पपूर्ण भमिका अदा की। नकली अभाव और वितरण संबंधी रूकावटों को दूर किया गया। सरकार ने अनुत्पादी खर्च, तथा वस्तु सुची को कम करने के लिये सख्त कदम उठाये। इसके अलावा सरकार ने उपलब्ध धन साधनों का कु ालतापूर्वक आवंटन करने का प्रयास किया और विकास संबंधी धन की जरूरतों को पूरा करने और बजट के घाटे को कम करने के लिये करों के अलावा अन्य साधन जुटाये। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों मे अधिक उत्पादन बेहतर क्षमता उपयोगिता और उचित मूल्य समजनों द्वारा आंतरिक साधनों के ज्यादा उत्पादन पर जोर दिया गया। क्रेडिट के विस्तार के प्रतिबंध को ध्यान मे रखते हुए कु ाल वस्तु सुची प्रबंध पर अधिक बल दिया गया। मूल्य स्थिरता लाना और राज्य के आंतरिक उत्पादन की दर मे अधिक बढौतरी करना राज्य सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण उददे य रहेगा। हरियाणा सरकार कृशि औद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देती रहेगी तथानये 20 सूत्री कार्यक्रम को जो ा के साथ कार्यान्वित करने के साथ साथ सप्लाई और वितरण मे और सुधार लायेगी।

अब मैं राज्य के कुछ प्रमुख विकास कार्यक्रमों की चर्चा करूंगा।

सिंचाई

माननीय सदस्यों को पता ही है कि विभिन्न राज्यों के बीच रावी ब्यास के पानी के बंटवारे के सिलसिले मे हरियाणा सरकार की बात मान ली गई है और रावी ब्यास के पानी मे हरियाणा का हिस्सा 35 लाख एकड़ फूट ही रखा गया है, जो ठीक वही है जो कि सरकार को पहले भी दिया गया था। इसकेलिये हम श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति निरंतर आभारी रहेंगें जिन्होंने हमें इस मामले मे इंसाफ दिलवाया है। हमें आ ाा है कि उनके आ ाीर्वाद से पंजाब क्षेत्र से होकर पानी लाने वाली नहर दो वर्श के अंदर मुकम्मिल हो जायेगी। बड़े और मझंले सिंचाई क्षेत्र के लिये चालू वर्श मे 57.87 करोड़ रूपये का और आगामी वर्श मे 60.11 करोड़ रूपये का परिव्यय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित हुआ है। सतलुज यमुना योजक परियोजना की जरूरत को पूरा करने के लिये इन परिव्ययों मे काफी बढ़ौतरी कर दी जायेगी और इस परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा करने के सिलसिले मे पंजाब सरकार के साथ सम्पर्क एवं तालमेल रखा जायेगा। प्रधान मंत्री द्वारा परियोजना के पंजाब भाग के निर्माण कार्य का निकट भविश्य मे उद्घाटन किये जाने के बाद आ ाा है कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल पड़ेगा। वर्तमान सिंचाई मांगों को आधुनिक बनाने के काम को बड़े जो ा के साथ पूरा करवाया जा रहा है और अगस्त, 1982 के अंत तक लगभग 25 करोड़ वर्ग फुट नहरों को पक्का करने का कार्य मुकम्मिल हो जायेगा जिससे 1.37 लाख हैक्टयर अतिरिक्त रकबे मे सिंचाई हो सकेगी। वर्श 1982–83 के दौरान इस काम के लिये 25 करोड़

रूपये के खर्चे का प्रस्ताव है। सिवानी और लोहारू उठान सिंचाई स्कीमों का कार्य तकरीबन पूरा हो गया है और जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम का काम भी काफी आगे है। ये स्कीमें पूरी होने पर और रावी ब्यास पानी का हमारा हिस्सा प्राप्त होने के बाद 2.85 लाख हैक्टेयर रकबे मे सिंचाई हो सकेगी। खरीफ 1980 के मुकाबले मे खरीफ 1981 मे सिंचाई अधीन रकबे मे 2 प्रति ात बढौतरी हुई है और रबी 1980–81 के मौसम मे 10.25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई अधीन रहा है। मार्च 1982 तक 25 हजार हैक्टेयर और वर्श 1982'83 मे 51 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त रकबे मे सिंचाई की सम्भावना हो सकेगी। इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप अगले तीन वर्शो के अंदर अंदर सिंचाई का वर्तमान स्तर 18.20 लाख हैक्टेयर से बढ़ कर लगभग 24 लाख हैक्टेयर हो जायेगा। बाढ़ पर काबू पाने और जल निकास के कामों को आगे बढ़ाया जायेगा ताकि बाढ़ों की तबाही से सूबे को बचाया जा सके और वर्श 1982–83 के दौरान इस काम के लिये 17.50 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है।

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई और नलकूप निगम द्वारा चालू वर्श के दौरान 5.50 करोड़ रूपये की लागत से 200 टयूबवैल और आगामी वर्श के दौरान 3 करोड़ रूपये की लागत से 125 टयूबवैल लगाने का प्रस्ताव है।

बिजली

बिजली अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और विकास मे इसका खास योगदान है। बिजली उत्पादन बढ़ाने और राज्य बिजली बोर्ड के कार्यचालन को सुधारने के लिये भरसक प्रयत्न कियये जा रहे है। मुझे यह बताते हुए खु ाी है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारे ताप बिजल संयंत्रों के लिये बिजली का उत्पादन अपनी श्रमता के 33 प्रति ात से बढ़ा कर 50 प्रति ात करना सम्भव हो सका हैं बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेक छोटी अवधि और ल्म्बी अवधि के उपाय किये गये है। फरीदाबाद ताप बिजलीघर की 60 मैगावाट वाली तीसरी यूनिट को अप्रैल, 1981 मे व्यावसायिक रूप से भाुरू कर दिया गयां पानीपत ताप बिजली संयंत्र के दूसरे और तीसरे चरण का कार्य भाुरू कर दिया गया है। इन के अतिरिक्त बिजली पैदा करने की कई नई स्कीमें, जैसे कि यमुनानगर थर्मल परियोजना, पि चमी यमुना नहर पन बिजली परियोजना चरण–II और विभिन्न छोटी पन बिजली परियोजनायें भाुरू की गई है। नाथपा ढाकारी पन बिजली परियोजना का निर्माण कार्य भाुरू हो गया है और डिजाइन कार्य भाुरू किया जा चुका है।

राज्य की सभी हरिजन बस्तियों मे 18 नवम्बर, 1981 को जबकि श्री राजीव गांधी ने अंतिम हरिजन बस्ती मे बिजली जलाई थी, बिजली पहुंचाना सरकारकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब तक लगभग, 4000 गांवों की गलियों मे बिजली लगाई जा चुकी है और आ ाा है कि 1984 तक सभी गांवों को यह सुविधा

दे दी जायेगी। वर्श 1982–83 के दौरान बिजली क्षेत्र के लिये 102.50 करोड़ रूपये के योजना खर्चे का प्रस्ताव रखा है। उत्पादन स्कीमें पूरी करने के काम सब से ज्यादा तरजीह दी जायेगी।

कृशि उत्पादन

नये 20 सुत्री कार्यक्रम मे खेती तथा संबंध क्षेत्रों के विकास के लिये कुछ महत्वपूर्ण मार्ग निर्दे ा है। उनके ढांचे मे इस क्षेत्र के विकास के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है।

कृशि क्षेत्र मे सरकार की नीतियां लगातार उत्पादन बढ़ाने, किसानों को फायदेमंद कीमतें दिलाने और देहाती इलाकों मे कमजोर वर्गो के लाभ के लिये रोजगार अवसर जुटाने संबंधी उपायों पर केंद्रित है। खेती उत्पादन बढ़ाने की कार्यनीति से सिंचाई सम्भावनायें बढ़ाने, कृशि इनपुटों के ज्यादा और उचित प्रयोग करने, किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली सप्लाई करने और फायदेमंद समर्थन मूल्य नीतियां अपनाने पर जोद दिया जाता रहा है।

दुर्भायव ा खरीफ 1981 के दौरान राज्य भारी सुखे की चपेट मे रहा जिससे खरीफ और रबी दोनों फसलों की उपज को हानि पहुंची । फिर भी, कृशि इनपुटों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करके और खेती बाड़ी के उचित खरीकों को प्रयोग मे लाकर सरकार कृशि की उपज मे भारी कमी को रोक पाई है। वर्श 1981–82 के दौरान खाद्यान्नों की पैदावार 69 लाख टन तक पहुंच

जाने की सम्भावना है। गनने को उपज गुडं के रूप मे 5.502 लाख टन और कपास की 6.80 लाख गांठे पैदा होने का अंदाजा है। वर्श 1982–83 के लिये खाद्यान्नों की उपज का लक्ष्य 71.40 लाख टन और गन्ने का गुड़ के रूप मे 7.60 टन तय किया गया है। कपास की उपज का लक्ष्य 7.10 लाख गांठे रखा गया है वर्श 1981–82 के दौरान लगभग 11.22 लाख टन गेहूं औ 7.05 लाख टन चावल की खरीद की गई थी। कृशि उत्पादन की विविधता और पौधों के बचाव संबंधी उपयों पर जोर दिया जाता रहेगा। भूमि संरक्षण उपायों और जल व्यवस्था प्रणालियों के प्रचार को तरजीह दी जा रही है। हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड वि व बैंक कार्यक्रम के अधीन 23.43 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 26 मडियों की स्थापना कर रहा है। कृशि के लिये वर्श 1982–83 मे 17.03 करोड़ रूपये के खर्च का प्रस्ताव है, जबकि चालू वर्श का परिव्यय 13.30 करोड़ रूपये है।

राज्य मे ुसल बीमा स्कीम खरीफ 1980 के दौरान 17 तहसीलों मे भुरू की गई थी। चालू रबी मोसम के दौरान इस स्सकीम को फैला दिउया गया है। अब इस स्कीम के तहत गेहूं के लिये सारा राजय, जौ के लिये 11 तहससीलें और चले की फसल के लिये 12 तहसीलें आ गई है।

गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के मंसूबें मे तथा उचित क्षेत्रीय विकास को सुनि ित करने के लिये वि ोश कृशि कार्यक्रम जारी रखे जा रहे है। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये चालू वित्त वर्श कू दौरान 4.80 करोड़ रूपये के खर्च और अगले वर्श के लिये 5.44 करोड़ रूपये के खर्च का प्रस्ताव किया गया है।

राज्य के विभिन्न इलाकों के बीच असमानतायें कम करने के लिये मेवात विकास बोर्ड ने इस क्षेत्र के विकास के लिये नई स्कीमें बनाई है। चालू वर्श के दौरान सामान्य विभागीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त 40 वि ोश स्कीमें लागू की जायेगी। अगले चार वर्शो मे मेवात क्षेत्र के सभी गांवों मे पीने के पानी का इंतजाम करना हमारा लक्ष्य है। वर्श 1982–83 मे इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिये 2 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा हर साल प्रति ब्लाक कम से कम 600 परिवारो को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का प्रस्ताव है। इस काम के लिये वर्श 1981–82 के दौरान प्रति ब्लाक 6 लाख रूपये का उपबंध किया गया है। वि ोशकर ऐसे लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हे, लाभ पहुंचाने के लिये ब्लाक स्तर की केडिट योजना पर खासतौर से ध्यान देते हुये अग्रणी बैंकों और कृशि वित्त निगम के सहायेग से दे ा के अंदर राज्य मे पहलली बार व्यापक ब्लाक लैवल विकास आयोजना पद्धति भ्ाुरू की गई है। नरवान ब्लाक की पहली आर्द ा रिपोर्ट 26 फरवारी 1982 को बैंकरों की राज्य स्तर की तालमेल कमेटी मे अनुमोदित हुई और कार्यक्रम चालू कर दिया गया था और गुड़गांव जिले के पुनहाना ब्लाक के लिये ऐसी ही

ब्लाक विकास रिपोर्ट तेयार करने का कार्य भी चालू कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने भूमि सुधार कानुन पर बड़ी तेजी से अमल किया है ओर 40 हजार पात्र आदमियों को फालतू जमीने दे दी है। राज्य मे लगभग 1.30 लाख एकड़ भूमि सरप्लस घोशित हुई है और इस ीाूमि के लगभग 354 हजार अलाटियों को 1.15 लाख एकड़ भूमि का कब्जा दे दिया गया है। 40 हजार पात्र आदमियों मे से जिन्हे भूमि अलाट की गई है अधिकां ा अनुसूचित जातियों के लोग है। वर्श 1982–83 के अंत तक, जुई तथा लोहारू सिंचाई अधीन क्षेत्र मे सारे 3.29 लाख एकड़ क्षेत्र मे चकबंदी का काम पूरा कर लिया जायेगा।

प ाुपालन, डेरी विकास तथा मछली पालन

राज्य के किसानों के लिये प ाुपालन का काम परम्परागत रूप से एक महत्वपूर्ण संबंधकार्य रहा है। इस क्षेत्र के विकास कार्य अगले वित्त वर्श मे 2.01 करोड़ रूपये के योगनागत परिव्यय से चालू रखे जायेगें। चालू वर्श के दौरान 50 प ाु डिस्पैंसरियों और प ाुपालन केन्द्रों को प ाु चिकित्सा अस्पतालों मे बदल दिया गया हैं 50 नई प ाु डिसपैसरियों स्थापित की गई है। और 50 प ाुपालन केन्द्र खोल दिये गये है। नारनौल मे एक नई सघन प ाु विकास परियोजना चालू की गई है। पशुपालन के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन केवल अनुसूचित जातियों के लाभ के

लिये वि ोश संघटन योजना के अंतर्गत वर्श 1982–83 के दौरान 70.47 लाख रूपये का उपबंध है। इन कार्यक्रमों से लगभग 3300 परिवारों को लाभ होगा जिनमे से 1350 परिवार अनुसूचित जातियों के होंगे। वर्श 1982–83 के दोरान डेरी कार्यकलापों के लिये आमदनी बढ़ाने के लिये राज्य मे मछली पालन के कामों को भी बढ़ावा दे रही है। इस प्रायोजना के लिये वर्श 1982–83 मे 48 लाख रूपये के योजनागत खर्चे का प्रस्ताव किया गया है।

सहकारिता

सहकारिता आंदोलन अब केवल ग्रामीण ऋण के क्षेत्र तक ही सीमित नही है बल्कि इसके अंतर्गत विकास के अंन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भी जाते है जैसे कि कृशि इनपुटो की सप्लाई, कुशि उत्पादन को बेचना, उपीाोक्ता सामन की सुनि ित सप्लाई और अधिप्राप्ति । सहकारी उधार समितियों ने सहकारिता वर्श 1980–81 के दौरान 12474 करोड़ रूपये के कर्जे दिये। वर्श 1981–82 के दौरान लगभग 130 करोड़ रूपये और वर्श 1982–83 के दौरान 140 करोड़ रूपयों के कर्जे देने की आ ाा है। सहकारिता वर्श 1982–83 के दौरान प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों ने राज्य मे 30.52 करोड़ रूपये के लम्बी अवधि के कर्जे दिये है। छः और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों का संगठन किया जा रहा है ताकि किसानो की लम्बी अवधि की धन जरूरत को पूरा करने के लिये पैसे आसानी से मुहैया हो सके।

हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन संध द्वारा चालू वर्श के दौरान 150 करोड़ रूपये और वर्श 1982–83 के दौरान 165 करोड़ रूपये के कृशि उत्पाद के खरीद फरोख्त की सम्भावना है। हैफेड ने डींग मे एक बिनौला विधायन काम्पलैक्स और तिया तथा डींग मे कपास से बिनौला अलग करने के दो कारखाने स्थापित किये है। भााहबाद, जींद और पलवल मे नई चीनी की मीलें स्थापित करने के लिये भारत सरकार द्वारा आ य पत्र दिये गये है। वर्श 1982–83 के दौरान सहकारिता के लिये प्रस्तावित योजनागत परिव्यय 6.50 करोड़ रूपये का है जिसमे से 1.59 करोड़ रूपये कमजोर वर्गो के लाभ के लिये है।

पंचायतें तथा विकास

ग्रामीण क्षेखों के विकास के लिये समुदायिक विकास कार्यक्रम सरकार की एक खास नीति संबंधी योजना है और इस प्रयोजन के लिये 1982–83 मे 90 लाख रूपये के खर्चे का प्रस्ताव रखा गया है। हरिजन चौपालों के निर्माण कार्य को काफी तरजीह की गई है और वर्श 1981–82 के अंत तक 350 चौपालें पूरी हो जाने की आ ाा है। सरकार महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों और पोशण कार्यक्रमों को, जो कि नये 20 सूत्री कार्यक्रम मे भी भामिल है, महत्व दे रही है। चालु वर्श के दौरान 220 पोशण केन्द्र खोले गये है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अधिक मजबूत और विस्तृत करने के लिये देहाती विकास कार्य तेजी किया जा रहा है। औद्योगिक घरारों को भी इस कार्यक्रम मे भाामिल किया गया है और चालू वर्श के दौरान इनकी सहायता से 4.42 करोड़ रूपये की ग्रामीण परियोजनाओं पी काम किया जा रहा है। फोकल गांवो के विकास की स्कीम, जिससके अंतर्गत चुनिंदा देहातों को न्यूनतम बुनियादी सहूलियतें दी जाती है, 25 लाख रूपये के उपबंध से अगले वर्श भी जारी रखी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास कार्यो हेतु मैचिंग ग्रांट की स्कीम के लिये वर्श 1982–83 मे 42 लाख रूपये का उपबंध किया गया है।

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने सामुदायिक परिसम्पतियां बनाने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों मे कमजोर वर्गो की धन कमाने की क्षमता बढ़ाने मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चालू वर्श के दौरासन इस कार्यक्रम के लिये 3.20 करोड़ रूपये का योगनागत परिव्यय रखा गया है।

राज्य मे रोजगार के अवसर जुटाने के लिये वि ोश प्रयास किये गये है। बेरोजगार ग्रामीण युवकों को अधिक से अधिक नौकरियों के अवसरों की सूचना जुटाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रो मे 34 अतिरिक्त रोजगार कार्यालय स्थापित किये जा रहे है।

वन

वन साधनों को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि इससे भूमि संरक्षण और पड़ौस के रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने मे मदद मिलती है। इसे नये 20 सूत्री कार्यक्रम मे भाामिल करके राश्ट्र ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। सरकार वन रोपण और सामाजिक एवं कृशि वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन दे रही है। वर्श 1981–82 के दौरान छः करोड़ पौधे लगाये जायेंगे और इस वर्श के लिये 4.10 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय का प्रावधान है। वर्श 1982–83 के दौरान 7005 हैक्टेयर क्षेत्र मे और 6350 किलोमीटर पंक्ति मे पौधे लगाने का कार्य किया जायेगां लगभग 12 करोड़ वक्ष लगाये जायेंगे। पहली अप्रैल 1982 से वि व बैंक कार्यक्रम के अंतर्गत 33.33 करोड़ रूपये के परिव्यय से एक सामाजिक वानिकी परियोजना चालू की जा रही है।

उद्योग

सरकार की औद्योगिक नीति का उदे य क्षमता उपयोगिता संबंधी बाधाओं को दूर करना, औद्योगिक रूग्णता को कम करना, राज्य मे विभिनन इलाको के बीच असंतुलन को ठीक करना तथा रोजगार के अवसर जुटाना है। अवस्थापना की असमान कारगुजारी के कारण औद्योगिक उत्पादन पर आई बाधायें काफी हद तक दूर हो गई है। निर्यात योग्य सामान के उत्पासदन की ओर सरकार पूरा ध्यान देती आ रही है और इसके परिणाम स्वरूप

राज्य से 100 करोड़ रूपये से अधिक का निर्यात हुआ है। राज्य मे नये उद्योगों को अनेक आकर्शक प्रोत्साहन दिये जाते है। इसके अतिरिक्त पढे लिखे बेरोजगारों को सुविधाये भी दी जाती है। राज्य मे उद्योग स्थापित करने के लिये प्रवासी भारतीयों को औद्योगिके प्लाटों आदि के आरक्षण जैसे वि ोश प्रोत्साहन दिये जा रहे है। इसके परिणामस्वरूप राजय मे उद्योग स्थापित करने के लिये प्रवासी भारतीयो से अब तक 386 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके है। हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम ने नियत समय के कर्जे देने के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और चालू वित्त वर्श के दौरान यह निगम अब तक 5.88 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर चुका है। हरियाणा वित्त निगम ने भी अब तक 20.35 करोड़ रूपये का आवधिक कर्ज स्वीकृत किया है।

औद्योगिक उद्यमकर्ताओं को एक ही स्थान पर सभी सेवाये प्रदान करने के लिये सरकार ने एक औद्योगिक सहायता ग्रुप किया है ताकि उद्योग स्थापित करने मे आने वाली अड़चनों को भीघ्र दूर किया जा सके। राजय मे लगभग 30 हजार छोटे पैमाने की इकाइयों मे से तकरीबन 7959 इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों मे है। एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने 2 करोड़ रूपये से संयुक्त राश्ट्र विकास कार्यक्रम और यू0 एन0 आई0 डी0 ओ0 की आं ाक सहायता से अम्बाला मे एक परियोजना स्थापित की है ताकि उपकरणों के नवीनतम डिजाइन ओर प्रोटोटाइप विकास के लिये

तकनीकी आधार बनाया जा सके तथाराज्य मे इस उद्योग का विकास किया जा सके।

चालू वर्श के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की कारगुजारी की रफतार काफी तेज हुई है। कृशि मे सुधार के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग खूब बढ़ गई है। बिजली और औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता भी संतोशजनक रही। वर्श 1982 मे, जो उत्पादकता वर्श भी है, यह यत्न किये जाएंगे कि औद्योगिक उपक्रम अपनी वर्तमान क्षमता से उत्पादन बढ़ाने मे समर्थ हो सकें और वे अपनी क्षमता मे भी वृद्धि करें।

वर्श 1981–82 के दौरान राज्य मे श्रमिक संबंध अच्छे रहे जिसकी वजह से औद्योगिक उत्पादकता मे वृद्धि हुई। राज्य मे अकु ाल कामगारों के लिये मजदूरी की कम से कम दरें 285 रूपये से 304 रूपये प्रतिमास के बीच थीं और वे दरें उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के साथ संबंध कर दी गई है तथा प्रति प्वाइंअ 1050 रूपये की दर नियत की गई है। राज्य सरकार ने राज्य मे आने वाले प्रवासी कामगारों के हित को सुरक्षित रखने के लिये भी अनेक कदम उठाये है। ये कामगार न्यूनतम मजदूरी और ओवरटाइम की अदायगी, चिकित्सा सुविधाओ, विस्थापन भत्ता और अन्य लाभों के भी हकदार होंगे। कामगारों को कानूनी सहायता भी दी जा रही है।

वर्श 1981–82 के दौरान दो औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थान आदमपुर और नलवा मे भाुरू किये गये है। वर्श 1982–83 के दौरान यमुनानगर मे एक उच्च व्यावसयिक प्रि ाक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी। वर्श 1982–83 के दौरान औद्योगिक प्रि ाक्षण के लिये 50 लाख रूपये के योजनागत परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

सड़कें

हमारी सड़कें राजय के आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे का कार्य करती रही । चालू वित्त वर्श के दौरान मैदानों मे कम से कम 250 और इस से अधिक आबादी वाले और पहाड़ों मे कम से कम 150 तथा इससे अधिक आबादी वाले परंतु खादर और अन्य क्षेत्रीय इलाकों के कुछ गांवों को छोड़ कर अन्य सभी गांव पक्की सडकों से जोड़ दिये गये है। वर्श 1982–82 के दौरान सड़कों ओर पुलों के निर्माण के लिये 15 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव है तथा इससे 560 किलोमीटर सड़कों का और निर्माण किया जायेगा।

परिवहन

हरियाणा रोडवेज अपनी कु ाल सेवाओं के लिये प्रसिद्ध है। इसकी क्षमता उपयोगिता बहुत अच्छी रही। वर्श 1982––83 के अंत तक इसकी बसों की संख्या 2800 हो जायेगी। यात्रियों को बीमा सुरक्षा देने के लिये यात्री बीमा सकीम भाुरू

करने की सरकार की योजना है। चालू वित्त वर्श के दौरान फरीदाबाद मे एक डिपों की स्थापना की गई है। वर्श 1982–83 के दौरान महत्वपूर्ण ग्रामीण जंक ानों पर 100 नये क्यू अड्डे बनाए जायेंगे। कामगारों की भलाई के लिये सरकार ने आगामी दस वर्शों के दौरान 50 प्रति ात कामगारों को आवास देने की योजना बनाई है। गुड़गांव मे स्थित हरियाणा रोड़वेज की बसों का ढांचा बनाने वाली वर्क ाप को रोजकामेओ ले जाया जायेगा जिससे मेवाल क्षेत्र के विकास मे सहायता मिलेगी। इस उदे य के लिये 25 लाख रूपये की रा ि ा रखी गई है। परिवहन विकास विभाग की विकास गतिविधियों के लिये 10 करोड़ रूपये की रकम आगामी वर्श मे रखी गई है।

पर्यटन

हरियाणा पर्यटन हो हमे ा की तरह अपने कार्यो के लिये हरि जगह प्र ांसा मिलती रही है। चण्डीगढ़ मे एक नया नर्यटक अतिथि गृह और रिवाड़ी मे पर्यटक केन्द्र खोल दिया गया है। सूरजकूंड मे राजहंस मोटल की स्थापना इसका एक नया और महत्वपूर्ण उपक्रम है जो वर्श के अंत के 1982 के ऐ ि ायाई खेलों के दौरान यात्रियों को ठहराने का काम भुरू कर देगा। इस मोटल मे आरम्भ्र मे 78 कमरें होंगे और इसे 1982 मे ऐ ि ायाई खेलों के लिये चांदमारी के मैदानों से पक्की सड़कों द्वारा मिला दिया जायेगा। कैथल मे एक पर्यटक केन्द्र खोलने का काम भुरू कर दिया गया है। अनुमान है कि हरियाणा पर्यटन निगम ने वर्श

1980–81 के दौरान लगभग 10.29 लाख रूपये का लाभ कमाया है।

ि ाक्षा

सरकार लड़कियों की ि ाक्षा पर वि ोश जोर देते हुए सर्वजनिन आरम्भिक ि ाक्षा को फैलाने और प्रौढ़ो की निरक्षरता को दूर करने के लिये कटिबद्ध है। यह नये 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा निर्दिश्ट लक्ष्यों के अनुसार भी है। 6 से 11 वर्श के आयु वर्ग मे स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या वर्श 1980–81 मे 32.80 प्रति ात से कम हो कर 16.32 प्रति ात रह गई है। वर्श 1981–82 के दौरान 21 ब्रांच प्राथमिक स्कूलों को पूर्ण प्राथमिक स्कूल घोशित किया गया है, 210 प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर माध्यमिक स्तर और 125 माध्यमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उच्च स्तर कर दिया गया है। गैर सरकारी स्कूलों का 75 प्रति ात तक वित्तीय घाटा सरकार पूरा करती है और उनके कर्मचारियों को एक अप्रैल, 1981 से सरकारी वेतनमानों की दरों के अनुसार वेतन की अनुमति दी गई है। गैर सरकारी स्कूलों को सहायता अनुदान देने के लिये चालू वर्श मे 1.78 करोड़ रूपये का और वर्श 1982–83 के लिये 3.41 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है। सरकार ने चालू वर्श के दौरान दो गैर सरकारी स्कूल अपने अधिकार मे ले लिये है। वर्श 1981–82 के दौरान प्रौढ़ ि ाक्षा स्कीमों के लिये 69.24 लाख रूपये का उपबंध किया गया है। वर्श 1982–83 के दौरान 400 प्रौढ़ ि ाखा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

है। अि ाक्षित श्रमिकों की ि ाक्षा और प्रि ाक्षण के लिये फरीदाबाद मे एक श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना की गई है।

उच्च ि ाक्षा देने वाले गेर सरकारी कालेजो के वार्शिक संधारण अनुदान को वर्श 981–82 मे 95 प्रति ात तक बढ़ा दिया गया है। इस अनुदान को इस कालिजों के घाटे की गणना के लिये आय नही माना जाता । ग्रामीण क्षेत्रों मे उच्चतर ि ाक्षा मे विभिन्न गतिविधियों के लिये चालू वर्श के दौरान 9.86 करोड़ रूपये का और वर्श 1982–83 के लिये 9.90 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है इसके अतिरिक्त तकनीकी ि ाक्षा सुविधाएं बढ़ाने और इंजीनियरी हुनर की व्यवसथा के लिये वर्श 1982–83 की योजना मे 52 लाख रूपये का उपबंध किया गया है। हरियाणा के युवा वर्ग का सर्वागीण विकास सुनि ि चत करने के लिये वर्श 1982–83 के दौरान विभिन्न खेलकूद स्कीमों के लिये 60 लाख रूपये का उपबंध किया गया है।

स्वास्थ्य

नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की जिम्मेवारी है वह सर्वजनीन प्राथमिक उपचार सुविधाए पर्याप रूप से बढ़ाये, कुश्ठ तपेदिक और अंधेपन के रोगो पर काबू पाये तथा ऐच्छिक आधार पर परिवार नियोजन को बढ़ावा दे। राज्य सरकार ने चालू वर्श के दौरान 7.84 करोड़ रूपये के योजना परिव्यय से राज्य मे चिकित्सा ओर स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं के विकास एवं प्रसार के

प्रयास किये है। हरियाणा के स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 1966–67 मे 1.33 रूपये के बढ़ कर वर्श 1981–82 मे 18 रूपये हो गया है। वर्श 1982–83 के दौरान 16 नये सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्वात है और 12 ग्रामीण डिस्पैंसरियों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों मे बदल दिया जायेगा। 100 उप केन्द्रों और बावल मे पराम र्ी अस्पताल के भवन का निर्माण काम आरम्भ किया जायेगा।

आयुर्वैदिक चिकित्सा प्रणाली को हरियाणामे यथोचित महत्व दिया गया है और चालू वित्त वर्श के दौरान 10 नई डिस्पैंसरियां खोली जा रही है। वर्श 1982–83 के लिये 50 लाख रूपये का योजना परिव्यय प्रास्तावित है। इस का उपयोग सिविल अस्पताल भिवानी मे अन्य कार्यो के अतिरिक्त आयुर्वैदिक विंग के निर्माण, 10 नई आयुर्वैदिक डिस्पैंसरियां खोलने ओर कुरूक्षेत्र मे आयुर्वैदिक कालिज तथा अस्पताल के भवन के निर्माण के लिये किया जायेगा। गुड़गांव रैडक्रास सोसाइटी द्वारा 8 होम्योपैथी डिस्पैंसरियां खोली जा रही है। सरकार ने इस कार्य के लिये मेवाल विकास बोर्ड के जरिये 1981–82 के दौरान 80 हजार रूपये के अनुदान का उपबंध किया है। ऐसी सहायता भविश्य मे भी दी जायेगी।

लोक स्वास्थ्य

राज्य के सभी समस्या गांवो को पेयजल उपलब्ध करवाने के काम पर सरकार ध्यान दे रही है। वर्श 1981–82 के लिये ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के लिये 10.70 करोड़ रूपये का उपबंध है जो तवरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिये 3.35 करोड़ रूपये के प्रावधान के अलावा है। चालू वित्त वर्श के दौरान दिसम्बर, 1981 के अंत तक 155 गांवों को पेयजल सप्लाई सुविधायें प्रदान की गई है। सामान्य योजनागत उपबंध के अलावा राज्य के सुखाग्रस्त क्षेत्रों मे पेयजल सप्लाई स्कीमों को तेज करने के लिये 1.07 करोड़ रूपये की रा ि ा खर्च की जायेगी। वर्श 1982–83 के वि व बैंक परियेाजना के तहत ग्रामीण जल सप्लाई हेतु 2.06 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है तथा इस रा ि ा समेत ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम के लिये 11.73 करोड़ रूपये के उपबंध का प्रस्ताव है। वर्श 1982–83 के दौरान 225 गांवों को जल सप्लाई सुविधाएं दी जायेगी। वर्श 1982–83 के दौरान भाहरी जल सप्लाई तथा मल विकास स्कीमों के लिये 2.27 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया है।

आवास तथा भाहरी विकास

गंदी बस्तियों के वातावरण को सुधारना और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गो के लिये रिहाय ी घर उपलब्ध कराना नए 20 सूत्री कार्यक्रम का एक हिस्सा है। भाहरों मे से 2.25 लाख लोगों को 100–100 वर्ग गज का रिहाय ी प्लाट मुफ्त दिया गया है। खास तौर पर 1.39 लाख हरिजन परिवारों को इसका लाभ

पहुंचा है। हरिजनों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो के कल्याण के लिये ग्रामीन आवास स्कीम भी भ्रारू की गई है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत जिन लोगों को मुफ्त प्लाट दिये गये है। उन्हें 5000 रूपये तक वित्तीय सहायता दी जायेगी जो 15 से 25 वर्शो की की अवधि के दौरान किस्तों मे वसूल की जायेगी। अनुसूचित जातियों के लोगो को 2000 रूपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। राज्य के पांच नगरों मे भाहरील सम्पदायें स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार ने तीन स्थानों पर नयी मंडी टाऊनि ाप स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो का कल्याण

सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो के उत्थान को बहुत त्यादा तरजीह देती है। इसके लिये अनेक कार्यक्रम भ्रारू किये गये है। जिन पर चालू वर्श मे 4.98 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। उन की ि ाक्षा की विभिन्न स्कीमों पर 68.06 लाख रूपये खर्च किये जायेगे। अनुसूचित जातियों के लोगों को उपयुक्त मकान देने के लिये वर्श 1982–83 मे 29 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने चालू वित्त वर्श के दौरान 5800 लोगों को 1.70 करोड़ रूपये के कर्जे दिये है।

तपरीवास और विमुक्त जातियों के उत्थान संबंधी कार्यक्रम भी भ्रारू किये गये है। पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये

भिन्न भिन्न भौक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं मे दाखिले के लिये आरक्षण 2 प्रति ात से बढ़ा कर 10 प्रति ात कर दिया गया है।

चालू वर्श के 290 करोड रूपये के राज्य योजना उपबंध मे से 30.41 करोड़ रूपये की रा ि ा वि ोश संघटन योजना के लिये निर्धारित की गई है जो अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च की जायेगी। इसके अलावा अनुसूचित जातयों के आर्थिक विकास का खर्च करने के लिये भारत सरकार से 2.61 करोड़ रूपये की रा ि ा वि ोश केन्द्रीय सहायता के रूप मे प्राप्त होगी।

समाज कल्याण

सरकार, महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा उनकी बेहतर पोशण के कार्यक्रमों को तेज करना चाहती है। वर्श 1982–83 के दौरान समाज कल्याण संबंधी स्कीमों के लिये 80 लाख रूपये का उपबंध किया गया है और पोशण कार्यक्रमों के लिये भी इतना ही उपबंध किया गया है। चालू वर्श मे ि ा ू व्यापक विकास के लिये दी परियोजनायें स्थापित की जा रही है और ऐसी ही तीन परियोजनाये वर्श 1982–83 के दौरान स्थापित की जायेगी। वृद्धि तथा निराश्रित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हेतु वर्श 1982–83 के लिये 78.36 लाख रूपये का उपबंध किया गया है एक अक्तुबर, 1981 से वृद्धावस्था पें ान 50 रूपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 60 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है।

वर्श 1981 के दौरान अपाहिज लोगों की और वि ोश ध्यान दिया गया था। लेत्रहीन, गूंगे, बहरे और विकलांग व्यक्तियों के लिये सरकारी सेवा मे श्रेणी–III और श्रेणी–IV के पदों मे तीन प्रति ात पद आरक्षित रखे गये है। इन व्यक्तियों को अनेक अन्य सुविधायें भी दी गई है। 21 वर्श से अधिक आयु वाले पूरी तरह लाचार व्यक्तियों को 50 रूपये प्रतिमाह पैं ान देने की स्कीम भाुरू की गई है।

सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के उत्थान के लिये एक निगम स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इस निगम को अन्य बातों के साथ साथ उपयुक्त स्कीमों के जरिये इन लोगो को अधिक आमदनी पैदा करने मे सहायता का काम भी सौंपा जायेगा।

खाद्य तथा सप्लाई

सरकार उचित मूल्य की दुकाने, वि ोशकर ग्रामीण क्षेत्रों मे, खोल कर वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे विस्तार करने और उपभोक्ता की सुरक्षा के सिलसिले मे जागरूकता पैदा करने का इरादा रखती है। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों मे 1255 और भाहरी क्षेत्रों मे 4125 उचित मूल्य की दूकानें लोगों को अनिवार्य और रोजाना खपत वाली वस्तुयें मुहैया कर रही है। जमाखोरी और चोरबाजारी को रोकने के लिये कार्यवाही की गई है ताकि

बनावटी कमी के कारण आम लोगों पर कोई प्रभाव न पड़े। विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई संतोशजनक बनी रही ।

सहकारी उपभोक्ता संघ ने ग्रामीण क्षेत्रों मे जरूरी वस्तुओं के वितरण के लिये 30 जून 1981 तक 957 खुदरा बिक्र की दुकाने खोली और आ ाा है कि 30 जून 1982 तक 2000 या इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों मे कांफैड की भााखायें खोल दी जायेंगी।

प्राकृतिक आपदायें

वर्श 1977 से राज्य का किसान वर्ग निरंतर प्राकृतिक आपदाओं का ि ाकार होता आ रहा है। जनवरी, फरवरी और मार्च, 1981 की ओलावृश्टि के तुरंत प चात् राज्य के एक बड़े भाग को खरीफ 1981 के दौरान सुखे से हानि पहूंची। भूमि जोत कर और आबियाने की वसूली लम्बित करने और इससे छूट देने के अलावा सरकार ने तकाबी कर्जो की वसूली भी मुलतवी कर दी। इसके अतिरिक्त, पीड़ित किसानों की अनुग्रह राहत और तकावी कर्जे भी दिये गये। कुछ छोटी अवधि वाले कर्जो को मध्यम अवधि के कर्जो मे बदल दिया गया। चालू वित्त वर्श मे किसानों को राहत देने के लिये 11.13 करोड़ रखे गये है। इसके अलावा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे रोजगार पैदा करने के लिये यौजनागत परिव्यय 7.90 करोड़ रूपये बढ़ाया गया जिसके लिये केन्द्रीय सरकार ने सहायता प्राप्त होगी। इसके लिये मैं भारत सरकार के प्रति आभार

प्रकट करना चाहता हूं। आबियाना, भूमिजोत कर और तकाबी ऋण के निलम्बन औद छूट के कारण राजकोश मे 3.82 करोड़ रूपये की कमी आई। राजय मे हाल ही मे ओलावृश्टि से हुई तबाही का अनुमान वि ोश गिरदावरी पड़ताल द्वारा लगाया जा रहा है। पीड़ीत किसानों को गत वर्श की भांति ही उदारता के साथ राहत दी जायेगी।

कर एकत्रीकरण और व्यापारियों की समस्यायें

सरकार द्वारा एकत्रित करों मे सामान्यतः काफी बढौतरी हुई और वर्श 1979–80 से आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा एकत्रित करों की रा ि ा मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस विभाग ने 1979–80 के 156.73 करोड़ रूपये के मुकाबले मे वर्श 1980–81 मे 186.67 करोड़ रूपये एकत्र किये थे। इस प्रकार 19.10 प्रति ात वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्श के दौरान अब तक एकत्रित राजस्व के संबध मे उपलब्ध प्रमकाण से पता चलता है कि केर की वसूहिचखें मे काफी वृद्धि हुई है। जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था मे उन्नति ओर कर संबंध कानूनों को दृढ़ता से लागू करने के कारण है। करों से एकत्रित धन के आंकड़े वर्श 1981–82 मे 245 करोड़ तथा वर्श 1982–83 मे 272.94 करोड़ रूपये तक पहूंच जाने की सम्भावना है, जो कि क्रम ाः 31.25 तथा 11.40 प्रत ात वृद्धि है। विभा गकराधान कानूनों को दृढ़ता से लागू करने के लिये जहां एक ओर प्र ांसा का पाख्त्र हे वहां दूसरी ओर राज्य के व्यापार और उद्योगो की वास्तविक समस्याओं के प्रति सजग हा हैं। इसका

पता इस बात से चलता है कि उन्होंने कर सरंचना पुनरीक्षण समिति (टैक्स स्ट्रक्चर रिव्यू कमेटी) की कुछ सिफारि ाों को तुरंत स्वीकार कर लिया है। सरकार ने चालू वित्त वर्श के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पिरवर्तन किये है जो इस प्रकार है:–

(i) कम कर निर्धारण ओर छूटे हुए कर के निर्धारण के मामलों का पुनरीक्षण करने के लिये 8 वर्श की सीमा नियत करना,

(ii) एस0 टी0 13, एस0 टी0 14 और एस0 टी0 15 फार्मो को मासिक अथवा त्रैमासिक आधारों पर प्रस्तुत किये जाने की बजाये वर्श की अंतिम विवरणी के साथ प्रस्तुत करना,

(iii) पंजीकरण प्रमाण पत्रों के पंजीकरण अथवा नवीकरण की फीसें अब खजाने मे जमा करने के बजाए न्यायालय फीस स्टाम्पों द्वारा जमा करवाना।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रथम अप्रैल 1981 से एक वर्श की अवधी के लिये अपंजीकृत विक्रेता अथवा ग्राहकों को ट्रैक्टरों की अंतर्राज्जीय बिक्री कर की दर 4 प्रति ात नियत कर दी है जबकि पहले यह दर 10 प्रति ात थी। इसी प्रकार 1 अप्रैल 1981 से बनस्पति घी की बिक्री पर से छूट दे दी गई है। 1 अप्रैल 1981 से परतदार मढ़ाई वाले जूट के थैलों की बिक्री पर कर की दर को 7 प्रति ात से घटा कर 4 प्रति ात कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारी

सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों के वेतनमानों मे सं ाोधन करके उन्हें पर्याप्त वितीय राहत दे चुकी हैं वेतनमानों मे विसंगतियां दूर करने का काम तकरीबन मुकम्मिल हो चुका है और बहुत सी सूरतों मे पहले सं ाोधित वेतनमानों को और उदार बना दिया गया है। अब कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस वर्श पांच अतिरिक्त महंगाई भत्ते कि किस्तें दी गई है जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्श के दौरान सरकार पर लगभग 17.58 करोड़ रूपये का बोझ पड़ा है। कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतनमानों मे भी सं ाोधन किया जा रहा है।

लेखे 1980–81 और वार्शिक योजना 1980–81

वर्श 1980–81 के दोरान अर्थ व्यवस्था मे निरंतर मुद्रास्फीति (इन्फले ान) के दबावी के कारण राज्य के बजट साधनों मे कमी होने का खतरा बना रहा । प्राकृतिक आपदाओ, जिनके लिये सातवें वित्त आयोंग की सिफारि ाों पर आरम्भ मे किये गए उपबंध अपर्याप्त सिद्ध हुए, के कारण स्थिति पर और दबाव पड़ा। साथ ही साथ वसूलियों के संबध मे किसानों को दी गई राहतों से राज्य की आमदनी पर असर पड़ा है। उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक मे हुई वृद्धि को ध्यान मे रखते हुए महंगाई भत्ते

की किस्तें भी देनी पड़ी। इन तथ्यों के बावजूद, राजय की समूची बजट व्यवस्था काफी सीमा तक उन्नत बनी रही है।

वश्र 1980–81 रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अनुसार 45. 01 करोड़ रूपये और महालेखाकार, हरियाणा के अनुसार 45.54 करोड़ रूपये के घाटे के साथ समाप्त हुआ। इसके द्वारा दिये गये घाटे के वास्तविक आंकड़े क्रम ाः 36.01 करोड़ रूपये ओर 28.41 करोड़ रूपये है। तथापि घाटे के अंतिम आंकड़े दोनों सूरतों मे लेखे बंद करते समय असमंजित अर्थोपाय पे ागियों (भारतीय रिजर्व बैंक की सूरत मे 9 करोड़ रूपये और महालेखाकार की सूरत मे 17.13 करोड़ रूपये) का हिसाब लगाते हूए क्रम ाः 45.01 करोड़ रूपये और 45.54 करोड़ रूपये बने है। सं ाोधित अनुमान 1980–81 के समय अनुमानित 37.84 करोड़ रूपये के घाटे की तुलना मे 45.54 करोड़ रूपये का वास्तविक घाटा कुछ अधिक है जो कि लोक निर्माण कार्यो, ि ाक्षा, सिंचाई, जल निकास, बाढ़ नियंत्रण और परिवहन के लिये अधिक रा ि ा के खर्च के कारण है। राजस्व अधिवेश 10.20 करोड़ रूपये बढ़ गया, पूंजीगत खर्च भाामिल है। सं ाोधित अनुमान 1980.81 मे योजनागत परिव्यय 253.78 करोड़ रूपयेा का था। कमी मुख्य रूप से सतलुज यमुना योजक नहर के पंजाब के भाग पर खर्च न होने के कारण हुई। परंतु योजना आयोग ने अंत मे केवल 227.84 करोड़ रूपये का परिव्यय अनुमोदित किया । वर्श 1979–80 मे 203.50 करोड़ रूपये के वास्वविक योजनागत परिव्यय, जिसमे सुखा परिव्यय के 4

करोड़ रूपये भा भाामिल है, के साथ तुलना महत्वपूर्ण है। योजना खर्च मे, कृशि तथा सम्बंद्ध क्षेत्रों मे 64.90 प्रति ात, जल तथा बिजली विकास मे 5.67 प्रति ात, उद्योग तथा खनिजों मे 90.61 प्रति ात, परिवहन तथा संचार मे 24.81 प्रति ात, सामाजिक तथा समुदायिक सेवाओं मे 34.54 प्रति ात और आर्थिक सेवाओं मे 83. 33 प्रति ात तथा सामान्य सेवाओं मे 56.92 प्रति ात वृद्धि हुई। वर्श 1980.81 के दौरान राज्य योजना का खर्च वश्र 1979–80 के मुकाबले मे 20.89 प्रति ात बढ़ गया।

इस प्रकार राज्य सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वह विकास की ऐसी योजनायें बनाने और उन्हें लागू करने की योग्यता रखती है जो वृद्धि के सभी संबंधित पहलुओं पर काफी बल दे और बजट संबधी प्रतिबंधों और दबावों के बाबजूद ज्यादा से ज्यादा आर्थिक वृद्धि करें ओर नागरिकों को निरंतर सम्पन्न बनाने का यत्न करती रहे।

सं ाोधित अनुमान 1981–82 और वार्शिक योजना 1981–82

चालू वित्त वर्श की आर्थिक नीति विकास इतर व्यय कम से कम करने, वस्तु सूची पर सख्त नियंतण रखने, कर इतर राजस्व मे वृद्धि करने, बचतों के लिये प्रोत्साहन देने पर केन्द्रित थी, ताकि मुद्रास्फीति अथवा करों मे वृद्धि किये बिना विकास कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त धन जुटाया जा सकें राज्य सरकार ने यह सुनि ित करने का प्रयास किया है कि सार्वजनिक उद्यामों

द्वारा ज्यादा से जयाद आंतरिक साधन बढ़ाए जाये। इन उपक्रमों की वितीय कारगुतारी पर लगातार नजर रखी जा रही है। सं ाोधित अनुमानों मे योजनागत वयय बजट के स्तर से अधिक है क्योंकि राज्य मे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण और अनुसूचित जातियों को ऊपर उठाने के लिये क्रम ाः 7.90 करोड़ तथा 2.61 करोड़ रूपये के अधिक खच्र के कारण योजना खर्च मे वृद्धि हुई है। इन कामों के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई। वि ोश वितीय सहायता से हम येाजनागत खर्च मे वृद्धि कर कसे। योजना भिन्न खर्च के बजट के स्तर से वृद्धि सार्वजनिक सेवाएं मुहैया करने की लागत मे जरूरी वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अचानक या पड़ने वाले खर्च के कारण हुई है। राहत के कामो (9.66 करोड़ रूपये), मंहगाई भत्तें की कि तें (17.58 करोड़ रूपये), ब्याज की अदायगी (3.39 करोड़ रूपये), पैं ान लाभों (1. 43 करोड़ रूपये), पुलिस (4.19 करोड़ रूपये), ि ाक्षा (7.29 करोड़ रूपये), परिवहन सेवाओं (4.50 करोड़ रूपये), और अन्य प्र ाासनिक सेवाओं (1.56 करोड़ रूपये), पर अधिक खर्च हुआ है।

राज्य करों से 31.86 करोड़ रूपये की रकम अधिक प्राप्त हो रही है जोकि काफी वृद्धि का सुचक है। इस सदन द्वारा 1981–82 के बजट अनुमान पारित किये जाने के बाद से राज्य सरकार के राजस्व अधि ोश मे 16.15 करोड़ रूपये की कमी हुई है, पूंजीगत व्यय 2.74 करोड़ रूपये बढ़ा है, लोक ऋण मे 28.51 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई, कर्जे ओर पे ागियों के निवल

परिणामों मे 10.74 करोड़ रूपये का सुधार हुआ है, अनिधिक ऋण मे 5.64 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है तथा निक्षेप एवं पे ागियों की स्थिति मे 6.06 करोड़ रूपये की कमी हुई है। बजट अनुमान 1981–82 के बाद चालू वर्श के अथ ोश मे 7.70 करोड़ रूपये की गिरावट आई है। फिर भी चालू वर्श के बजट के अनुमानों मे 49. 29 करोड़ रूपये के घाटे की व्यवस्था के विरूद्ध अब सं ाोधित अनुमानों के समय हमारा अनुमान है कि वर्श केवल 37.48 करोड़ रूपये के घाटे से समाप्त होगा। इस प्रकार इस गरिमामय सदन द्वारा मार्च 1981 मे 1981–82 के बजट अनुमान स्वीकृत यकरने बाद 11.81 करोड़ रूपये का सुधार हुआ है। स्पश्टतः सतलुज–यमुना योजक नहर, प्राकृतिक आपदाओं के कारण दी गई राहत (9.66 करोड़ रूपये) अतिरिक्त मंगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी (17.58 करोड़ रूपये) के कारण होने वाले अधिक खर्च के बावजूद बजट के घाटे को उचित सीमाओं के अंदर रखना सम्भव हो पाया है। सरकार सार्वजनिक उद्यमों द्वारा योजना के लिये धन जुटाने मे अं ादान की वृद्धि सुनि चत कर सकी। प्राप्तियों मे 19. 88 प्रति ात की वृद्धि हुई है जबकि वर्श 1980–81 के दौरान वृद्धि दर 14.26 प्रति ात थी। पिछले वर्श 17.56 प्रति ात दर के मुकाबले मे इस वर्श के योजना भिन्न व्यय मे मे 14.29 प्रति ात की ही वृद्धि हुई है। 297.90 करोड़ रूपये काराज्य योजना व्यय, जिस मे सूखा राहत के 7.90 करोड़ रूपये भाामिल है। वर्श 1980–81 के 246.01 करोड़ रूपये के खर्च की तुलना मे 21.09 प्रति ात बढ़ा है, जबकि वर्श 1980–81 मे वृद्धि दर 20.89

प्रति ात और वर्श 1979–80 मे वृद्धि दर केवल 4.93 प्रति ात थी। 1980.81 के वास्तविक योजना व्यय की तुलना मे वर्तमान वर्श के प्रस्तावित योजना व्यय मे, जिसमें सूखाराहत व्यय भी भाामिल है, कृशि और संबंध क्षेत्रों के प्रस्तावित व्यय मे 27.33 प्रति ात, जल और बिजली विकास केव्यय में 22.09 प्रति ात, पहरवहन एवं संचार पर 3.95 प्रति ात, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं मे 26 प्रति ात, आर्थिक सेवाओं मे 45.45 प्रति ात और सामान्य सेवाओं के व्यय मे 68.14 प्रति ात की वृद्धि हुई है। इससे इस बात का पता चलता है कि राज्य की वृद्धिपरक आर्थिक नीति हमें अच्छे परिणाम देने मे सफल हुई है।

बजट अनुमान 1982–83 और वार्शिक योजना 1982–83

अब मैं गरिमामय सदन के सामने 1982'83 के बजट अनुमान पे ा करूंगा। सं ाोधित अनुमान 1981–82 और बजट अनुमान 1982–83 के बजट संबंधी लेन देन से उभरने वाली स्थिति नीचे दी जाती है:–

(रूपये करोड़ो में)

क्रं0 सं0	संघटक	बजट अनुमान 1981–82	सं ाोधित अनुमान 1981–82	बजट अनुमान 1982–83

	1	2	3	4
(1)	अथ भोश	(–)37.84	(–)45.54	(–)37.48
(2)	राजस्व लेखे			
	प्राप्तियां	518.24	544.97	621.78
	खर्च	434.35	477.23	491.40
	अधि ोश	(+)83.89	(+)67.74	(+)47.91
	घाटा	–	–	–
(3)	पूंजीगत व्यय (निवल)	119.06	121.80	124.19
(4)	लोक ऋण			
	लिया गया ऋण	335.06	431.61	461.43
	पुनः अदायगी	296.08	364.12	413.52
	(निवल)	(+)38.98	(+)67.49	(+)47.91
(5)	कर्जे और पे ागियां			
	पे ागियां	71.60	55.01	100.56

	वसूलियां (निवल)	24.75 (–)46.85	18.90 (–)36.11	35.46 (–)65.10
(6)	अंतर्राज्यीय भूगतान	–	–	–
(7)	आकस्मिक निधि (निवल)	–	(+)0.27	–
(8)	अनिधिक ऋण (निवल)	(+)17.03	(+)22.67	(+)17.88
(9)	जमा और पे ागियां (निवल)	(+)13.76	(+)7.70	(+)10.29
(10)	प्रे शण (निवल)	(+)0.80	(+)0.10	(+)1.00
(11)	वर्श का इति ोश	(–)49.29	(–)37.48	(–)19.31

अगला वर्श 37 करोड़ रूपये के घाटे से आरम्भ होगा और वर्श के अंत मे घाटा 19.31 करोड़ रूपये रह जायेगा। अगामी वर्श के दौरान 319.98 करोड़ रूपये के पर्याप्त अधिक योजना व्यय की व्यवस्था करते हुए भी वर्तमान वर्श के घाटे मे 18.17 करोड़ रूपये की कमी होगी जिससे पता चलता है कि हम अपनी विकास गतिविधियों की रफतार बनाये रखने का इरादा रखते है। दूसरी ओर हमारा प्रयत्न रहा है कि हम गैर जरूरी और व्यर्थ के खर्च

पर कठोर निगरानी रखे, बचत के लिये उचित वातावरण पैदा करें और कर इतर राजस्व मे वृद्धि करे। यह बाते चालू वर्श मे हमारे लिये कारगर सिद्ध हुई है और इन्हें अगले वर्श भी जारी रखा जायेगा।

राजस्व लेखे मे 130.38 करोड़ रूपये के अधि ेश का पता चलता है जो चालू वर्श के अधि ेश से 92.47 प्रति ात अधिक है। यह खास तौर से इसलिये संभव हो पाया है कि योजना भिन्न खर्च मे केवल 2.82 प्रति ात की वृद्धि हुई है। जबकि चालू वर्श मे यह 14.29 प्रति ात है। वर्श 1982–83 मे योजनागत परिव्यय 319.98 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जोकि चालू वर्श की येाजना स्कीमों के 290 करोड़ रूपये की योजना परिव्यय, जिसमे सूखे की राहत का खर्च भाामिल नही है, से 10.34 प्रति ात अधिक है। इसमे 56.88 प्रति ात जल एवं बिजली विकास के लिये, 17.93 प्रति ात कृशि एवं संबंध कार्यो के लिये, 8.27 प्रति ात परिवहन एवं सिंचार और 14.05 प्रति ात सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिये आबंटित है। अर्थ–व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये वि ेश योजना को उचित तरजीह दी गई है।

बजट के घाटे की कमी पूरा करने के उपाय

राज्य की अर्थ–व्यवस्था की कारगुजारी अत्यंत संतोशजनक और वि ेश रूप से लचीली रही है। पिछले दो वर्शो

ने बढ़ते हुए विकास संबधी क्रियाकलाप भुरू करने और विकास से संबंध न रखने वाले खर्च पर रो लगा कर मुद्रास्फीति का दबाव रोकने तथा अधिक उत्पादकता प्राप्त करने की हमारी योग्यता को साबित किया है। सरकार के कार्य संचालन मे वितीय अनु ाासन का कठोरता से पालन और राज्य के साधनो मे पर्याप्त वृद्धि के कारण घाटा पूरी तरह से काबू के भीतर है।

इस प्रकार वर्श 1982–83 के अंत मे रहने वाला 19.31 करोड़ रूपये का घाटा बिना पूरा किये इस आ ाा से छोड़ दिया गया है कि राजय के करों मे अधिक प्राप्तियां, अधिक उत्पादकता और क्षमता के बेहतर उपयो, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ज्यादा आंतरिक साधनो के पैदा किये जाने, येाजना भिन्न खर्चे के कम से कम होने, बेहतर वस्तु सूची व्यवस्था ओर घरेलू तथा ग्रामीण बचतें जुटाने से राज्य को यह घाटा और कम करने मे सहायता मिलेगी।

मूझे पूर्ण वि वास है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित बजट उपबंधों एवं हमारे नियत लक्ष्यों के द्वारा, कम से कम अवधि मे नये बीस सूत्री कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के हमारे प्रयासों के फलस्वरूप, निरंतर बढ़ती हुई उत्पादकता के प्रति हमारे संकल्पों के सहारे एवं वि ोश संघटक योजना तथा बढ़ी हुई संख्या मे ददिद्र हरिजनों के घरो से फूटती हुई रो ानी की किरणों द्वारा उन्हें भविश्य के लिये मिले नये वि वासों के जरिये, उम उज्जवल भविश्य की ओर दृढ़ एवं निःसंकोच कदम उठायेंगे। इस आ ामय

भविश्य की प्राप्ति के भाुभकार्य पर, आईये, हम अपने आप को फिर से समर्पित करे।

अपना भाशण समाप्त करने से पूर्ण मैं वित्त विभाग के अधिकारियो ंऔर कर्मचारियोंके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जिनकी कोि ा ाों से मैं ये अनुमान समय पर पे ा करने मे सफल हुआ हूं। मैं महालेखाकार हरियाणा, चण्डीगढ़ प्र ाासन और हरियाणा मुद्रणालय का भी मैं अभारी हूं जिन्होंने मुझे इस काम मे बहुमूल्य सहायता प्रदान की है।

श्रीमन्, मैं इन भाब्दों के साथ बजट अनुमान 1982–83 इस सदन के विचारार्थ एवं अनुमादनार्थ पे ा करता हूं।

वाक आउट्स

During the course of the presentation of the budget by the Finacne Minister—

1. Ch. Sant Kanwar, a member from the Opposition Benches staged a walk out stating that most of the facts and figures givenin the Budget are incorrect.

2. Shri Bhale Ram, a member from the Opposition, also staged a walk outdescribing the Budget as anti-social and anti-kisan.

श्री अध्यक्षः अब सदन सोमवार दिनांक 22–3–83, बाद दोहपर 2.00 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

13.16 बजे*

(तत्प चात सदन सोमवार, दिनांक 22 मार्च, 1982 बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ)